• पटरी पर भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट • किसानों पर मंडराती आसमानी आफत

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

बगावत और भितरघात का डर...

वर्ष 18, अंक-18 | 15 से 30 जून 2020 | मूल्य 25 रूपये

महामारी बनी महात्रासदी

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2018-20

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

इस अंक में

राजतंत्र

9 | अबकी बार 100 पार

क्या राज्यसभा में एनडीए 100 सदस्यों का जादुई आंकड़ा छू पाने में कामयाब हो जाएगा? क्या भाजपा के पास कांग्रेस से दोगुनी सीटें हो जाएंगी? आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्यों में बनाए और बिगाड़े...

राजपथ

10-11 | बगावत और भितरघात का डर...

मप्र में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे, यह तो तय नहीं है लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों में अंदरूनी घमासान चरम पर आ गया है। दलबदल के कारण खाली हुई 22 सीटों पर मामला पेचीदा हो गया है।

विवाद

13 | ऑडियो की राजनीति

मप्र की राजनीति में इन दिनों ऑडियो की राजनीति गरमाई हुई है। ऑडियो की राजनीति के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। आश्चर्य की बात यह है कि सोशल मीडिया पर चार ऑडियो क्लिप जारी हुई हैं। एक में प्रदेश...

सौगात

16 | स्कॉलरशिप का तोहफा

देश में अक्सर यह बात आम लोगों की जुबान से सुनी जाती है कि पुलिसकर्मी का बच्चा किसी काम का नहीं होता। इसकी वजह यह है कि लगभग सभी राज्यों में अमला कम होने के कारण पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को 12 से 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में पुलिसकर्मी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत सहित पूरे विश्व में भूकंप, सूनामी, बाढ़, चक्रवात सहित तमाम तरह की आपदाएं आईं लेकिन गरीबों की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई, जैसी कोरोना संक्रमण के दौरान देखने को मिली है। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान के अपने ज्ञान पर गुमान करने वाले देश अभी तक कोरोना वायरस के इलाज का न तो वैक्सीन इजाद कर पाए और न ही कोई दवा बना पाए। भारत में तो यह महामारी करोड़ों लोगों के लिए महात्रासदी बन गई है।

19

20

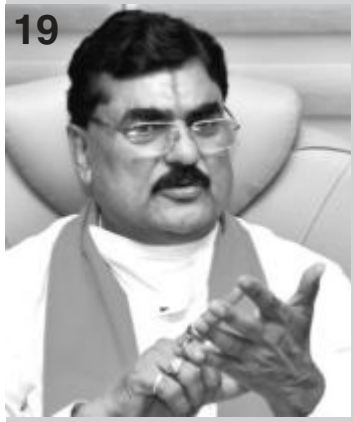

37

45

राजनीति

30-31 | शाह हुए सफल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक लंबी पारी खेलने के बाद अब अमित शाह देश के गृहमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री के रूप में उनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान देश में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। शाह के गृहमंत्री बनने के बाद...

सियासत

32-33 | एंटी इंकम्बेंसी नहीं...

केंद्र में भाजपा को सत्ता संभाले 6 साल हो गए लेकिन आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी नहीं है। इसकी यह वजह नहीं है कि केंद्र सरकार सबकुछ अच्छा कर रही है। दरअसल, विपक्ष कमजोर और निष्क्रिय है। जरा फरवरी 2020 की स्थिति पर गौर करें। नरेंद्र मोदी सरकार...

छत्तीसगढ़

34 | मनरेगा में टॉप पर छत्तीसगढ़

कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के बाद भी मनरेगा के विभिन्न मानकों पर छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरुआती दो महीनों में ही सालभर के लक्ष्य का...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

अपने–अपने विश्वासपात्र...

किसी शायर ने क्या खूब कहा है...

बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया मैंने,
कि अपनी जगह हर कोई इंसान सही होता है!!

मप्र ही नहीं देशभर में कुछ इसी अंदाज से लोग सरकारों के फैसलों को सही मानते आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि सरकार जो कुछ करती है, वह सही होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तबादलों को ही देख लें। मप्र में कमलनाथ सरकार आई तो उसका शुरुआती 6 महीने का कार्यकाल केवल तबादलों में ही बीता। रिकार्डतोड़ तबादलों के बाद भी कमलनाथ सरकार थकी नहीं और अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में लगातार तबादले करती रही। उसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद वर्तमान सरकार ने भी तबादलों की झड़ी लगा दी है। इस सरकार ने भी लगभग 3 महीने में 200 से ऊपर नौकरशाहों को इधर से उधर घुमा-फिरा दिया है। सवाल उठता है कि सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? अफसर कोई भी हो काम तो उसे सरकार का ही करना है। सरकार जो दिशा-निर्देश देगी अफसर उसका पालन करेंगे हीं। फिर यह तबादले का खेल क्यों? सरकारों का तर्क होता है कि कर्मठ अधिकारी को उचित सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन देखा यह भी जाता है कि जो अफसर एक सरकार में कर्मठ की श्रेणी में आते हैं, वही दूसरी सरकार में अकर्मण्य मान लिए जाते हैं। वहीं कुछ अफसर तो ऐसे होते हैं जो हर सरकार में लाइमलाइट में रहते हैं। दरअसल, हर सरकार अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से अफसरों की जमावट करती है। चाहे इसके लिए क्यों न नियमों को ताक पर रखा जाए। अभी हाल ही में पुलिस मुख्यालय का एक पुराना आदेश फिर से चर्चा में आया, जिसमें कहा गया है कि तबादले के लिए कोई भी अधिकारी-कर्मचारी नेता की सिफारिश न कराए। इस आदेश के बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या तबादले बिना राजनीतिक दखल के होंगे? अगर अब तक की स्थिति और परिस्थिति को देखें तो यह साफ दिखता है कि प्रदेश में अधिकतर तबादले सिफारिश पर ही होते हैं। राज्य में सिविल सर्विस बोर्ड तो कागजों पर चल रही है। प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रहे, किंतु ब्यूरोक्रेट के तबादले राजनीति दखल से किए जाते रहे हैं। पिछले दो दशकों में ब्यूरोक्रेट्स की पदस्थापना उनकी योग्यता से नहीं बल्कि नेताओं की गणेश परिक्रमा से होने लगी है। प्रदेश में सरकार किसी की भी रहे तबादले सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र की गाइडलाइन को दरकिनार कर किए जाते रहे हैं। प्राइम पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स नेताओं की परिक्रमा करते रहते हैं। कमलनाथ सरकार में तो तबादलों का रिकार्ड बना था। वहीं वर्तमान सरकार में भी लगातार तबादले हो रहे हैं। तबादले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सिविल सर्विस बोर्ड की राय भी नहीं ली जाती है। कोरोना संक्रमण काल में मप्र में सरकार भले ही अभी तक पूर्ण आकार नहीं ले पाई है, लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के स्थानांतरण की सूची-दर-सूची धड़ाधड़ जारी हो रही है। दरअसल, हर सरकार की कोशिश यह रहती है कि वह मुख्यालय से लेकर मैदानी स्तर तक अपने-अपने विश्वासपात्र अफसरों की जमावट करे। इसका परिणाम यह होता है कि अफसर आए दिन फुटबाल बने रहते हैं। इससे अफसरों में हीन भावना बढ़ती है, क्योंकि उनके साथ के कुछ अफसर सरकार की आंखों का तारा बने रहते हैं, वहीं कुछ उपेक्षित रहते हैं।

–राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 18, 16 से 30 जून, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21 नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

श्रम सिद्धि अच्छा कदम

कोरोना वायरस के संक्रमणकाल के कारण खराब हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। जो प्रवासी मजदूरों गांवों में पहुंचे हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत करके अच्छा कदम उठाया है।

● **सुरभि राजपूत,** इटारसी (म.प्र.)

किसानों पर भी ध्यान

प्रदेश सहित देशभर में जिस प्रकार कोराना वायरस ने पैर पसारे हैं, उसका किसानों पर भी बहुत असर पड़ा है। किसानों को गेहूं का एक-एक दाना बेचने के लिए कई व्यापारियों से कम दामों में सौदा करना पड़ता है जिससे उनका नुकसान होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **आयुष वर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

टिड्डियों ने और कमर तोड़ी

लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान के कारण एक तो पहले से किसान अपने गेहूं को लेकर परेशान है, ऊपर से खेतों में टिड्डियों के हमले ने और कमर तोड़ दी है। मप्र की कृषि पर टिड्डी दल का हमला बड़ा संकट है और इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर व्यापक प्रबंध करना होगा।

● **श्रेयांश सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

भारत की अर्थव्यवस्था को लगेगा कंधा

कोरोनावायरस के इस संक्रमणकाल के कारण जहां दुनियाभर के देशों में लोगों की मौतें हुईं और लाखों लोग अब भी इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। वहीं दक्षिण एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी धक्का लगा है। अब इन देशों के पास आपसी सहयोग और मजबूत करने के लिए एक बेहतर मौका है। अब इन देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत और बढ़ गई है। भारत के पास भी अपने छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाने का अच्छा मौका है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा कंधा लगने की भी उम्मीद है। इस संक्रमण से निपटने के लिए अब दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष एक ही रास्ता है, और वह है आपसी सहयोग का। भारत हमेशा से आपसी सहयोग का हिमायती रहा है।

● **प्रवीना सूर्यवंशी,** रायसेन (म.प्र.)

गड़बड़ाया भाजपा का गणित

प्रदेश कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं। कांग्रेस को इस बार उपचुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। तभी वह भाजपा से कांटे की टक्कर का मुकाबला कर सकेगी। उधर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से भाजपा का गणित गड़बड़ा गया है। भाजपा के कई नेता ऐसे हैं जो सिंधिया के आने के बाद अपने आपको अनसेफ महसूस कर रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों न। जिन नेताओं ने प्रदेश में भाजपा की रीढ़ को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी, अन्य पार्टी से किसी बड़े चेहरे के आने पर उन्हें अनसेफ तो लगेगा ही।

● **राजीव कुमार,** नई दिल्ली

ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पानी

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। अब मप्र में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत हर घर में नल का सपना साकार होगा। इस योजना से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। अभी प्रदेश के कई गांवों में लोग अशुद्ध पानी पीने के कारण बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में अशुद्ध पानी से होने वाली बीमारियों पर अंकुश लग पाएगा।

● **विवेक त्रिपाठी,** गुना (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

आलाकमान ने दिखाया आईना

राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में अपनी अनदेखी से कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा दुखी हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा की तरफ से चार सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव में तीन नामों की सिफारिश की थी। प्रभाकर कोरे, प्रकाश शेट्टी और रमेश कट्टी। पर आलाकमान ने विधायकों के संख्या बल के अनुपात में दो ही उम्मीदवार उतारे-अशोक गस्ती और एरन्ना कडाडी। शेट्टी बड़े होटलों के मालिक हैं और उनके भाई इस समय कर्नाटक सरकार में काबीना मंत्री हैं। तीसरा उम्मीदवार आलाकमान ने जानबूझकर नहीं उतारा। जद(एस) की तरफ से कांग्रेस के समर्थन के बूते पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की उम्मीदवारी सामने आने के बाद तीसरी सीट जीतने की सोचना भी व्यर्थ था। येदियुरप्पा ने करीबियों के सामने दुखड़ा रोया कि भाजपा में भी अब आलाकमान वाली कांग्रेसी संस्कृति हावी हो चुकी है। भाजपा ने पिछले साल कांग्रेस और जद(एस) के विधायकों में तोड़फोड़ कर कुमारस्वामी की सरकार तो जरूर गिरा दी पर पार्टी आलाकमान अब येदियुरप्पा को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। उन्हें गुमान है कि कर्नाटक में पार्टी को उन्होंने ही बढ़ाया है। लिहाजा उन्हें अपने तरीके से काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। पर वे भूल रहे हैं कि वे 77 के हो चुके हैं। 75 पार का भाजपा में अब दूसरा एक भी मुख्यमंत्री नहीं।

समरथ को नहीं दोष गुंसाई

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कालजयी पंक्ति लिख रखी है कि समरथ को नहीं दोष गुंसाई। इसका नजारा भाजपा में देखा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने की बात कही जा रही है। दरअसल वे 75 पार जो निकल चुके हैं। उम्र का तकाजा भी यही है और तेवर भी उतने तेज-तर्रार कहां रह पाते हैं। बेचारे हकीकत से अनजान नहीं हैं। चुनाव में पार्टी को विजय मिली होती तो मुख्यमंत्री नहीं बनाते उन्हें। तब तो ताज वसुंधरा राजे के सिर पर ही दिखता। कोरोना के संक्रमण ने लोगों को नुक्ताचीनी का मौका और दे दिया कि लोगों के बीच जाने के बजाय घर में दुबके हैं कटारिया। जवानी के दौर में तो दबंगई और सक्रियता का लोहा विरोधी भी मानते थे। पर कोरोना ने लाचार बना दिया। ऊपर से डाक्टरों की सलाह अलग कि 65 पार वालों को चौकस रहना चाहिए। घर से बाहर मजबूरी में ही निकलना चाहिए। पर अपने घर उदयपुर में ही कोरोना के संक्रमण ने विकराल रूप ले लिया तो खुद को रोक न पाए। लोगों के बीच पहुंचना भी भारी पड़ गया। किसी मरीज का हालचाल पूछा था कि बाद में वह कोरोना संक्रमित निकला। एकांतवास भी भोगा और जांच भी करानी पड़ी। ऐसा दो बार हुआ। गनीमत रही कि दोनों बार रिपोर्ट निगेटिव आई। बढ़ती उम्र और कोरोना संक्रमण ने भावुक अलग बना दिया।

आफत भी तोहमत भी

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का पूरा परिवार ही नहीं स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हो गया। शुरुआत उनकी पत्नी अमृता रावत से हुई। सतपाल महाराज, उनकी पत्नी, बाकी परिवारजन और स्टाफ कुल मिलाकर 22 लोग एकमुश्त हो गए संक्रमण के शिकार। उनकी कड़ी तो और लंबी जाएगी। मसलन खुद मुख्यमंत्री, सरकार के चार और मंत्री व कई आला अफसर सभी एकांतवास भुगत रहे हैं। जांच होगी तो संक्रमण होने या नहीं होने की पुष्टि बाद में होगी। मुख्यमंत्री ज्यादा चकित हैं। कोरोना पर उठाए गए कदमों के फुलप्रूफ होने का दावा कर रहे थे। जहां तक सतपाल महाराज का सवाल है, अपनी वरिष्ठता का उन्हें भी कम गुमान नहीं। संयुक्त मोर्चे की केंद्र में सरकार थी तो सतपाल महाराज रेल राज्यमंत्री थे। कांग्रेस से भाजपा में आए तो इसी हसरत से थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी पड़ गए, उन्हें मंत्री पद के साथ ही संतोष करना पड़ा। कहने वाले तो अब इतना कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि महाराज को पत्नी के संक्रमित होने की पहले से जानकारी थी। जांच भी उन्होंने सरकारी लैब से नहीं कराई ताकि संक्रमण की बात जगजाहिर न हो। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि मंत्री होते हुए भी उन्होंने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का जान बूझकर उल्लंघन किया।

गुरूर चूर-चूर

कोरोना का संक्रमण यकीनन ऐसी महामारी है जिसने सर्वशक्तिमान इंसान का सारा गुरूर चूर-चूर कर दिया है। साधू-संत, ज्योतिषी, धर्माचार्य सब बेबस हैं। चारधाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा सब टल गया। नया खतरा हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले पर मंडरा रहा है। अगले साल एक जनवरी से प्रस्तावित है। अखाड़ा परिषद् के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि और महामंत्री महंत हरि गिरि ने दो टूक कह दिया है कि कुंभ के स्नान पर्व ज्योतिष की गणना के हिसाब से तय होते हैं। लिहाजा इसकी तारीखों को टाला नहीं जा सकता। महंत हरि गिरि ने 30 जून को कुंभ की बाबत सभी तेरह अखाड़ों की बैठक बुलाई है। राज्य सरकार की दुविधा दोहरी है। एक तो अर्थाभाव, ऊपर से प्रवासी मजदूर उपलब्ध नहीं हैं। लिहाजा कुंभ से जुड़े काम भी शुरू नहीं हो पाए। साधु-संत भी दानियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अब वर्चुअल कुंभ कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब देखना यह है क्या ऐसा होता है।

सियासी प्रबंधन पर नाज

कहने को लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन बताया जाता है पर यही जनता अपने जिन नुमाइंदों को अपनी सेवा की अपेक्षा में चुनकर संसद और विधान मंडलों में भेजती है, वे कुर्सी और धन के लोभ को संवरण नहीं कर पाते। राज्यसभा चुनाव में इसी लोभी प्रवृत्ति का विकृत रूप हम कब से देखते आ रहे हैं। विधायक-सांसद बिकाऊ हो रहे हैं। तभी तो राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी प्रबंधन पर बड़ा नाज है। पर्याप्त विधायकों का समर्थन न होने के बावजूद कई उम्मीदवार चुनावी जंग में कूद पड़ते हैं। इसीलिए गुजरात के अपने विधायकों को भाजपाई सेंध से बचाने के लिए गहलोत के सुपुर्द कर दिया। इससे पहले कर्नाटक के कांग्रेसी विधायकों की हिफाजत भी गहलोत ने ही की थी। पर अचानक यह क्या हुआ? गहलोत को तो अब अपने ही विधायकों की चिंता सताने लगी है। अन्यथा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी सूबे की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक को शिकायती पत्र क्यों भेजते?

शासन भी यही... प्रशासन भी यही

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो नौकरशाहों की तूती बोल रही है। आलम यह है कि इन्हें ही शासन और इन्हें ही प्रशासन माना जा रहा है। इसके पीछे वजह ही कुछ ऐसा है। दरअसल, ये साहेबान जो कहते हैं वही होता है। इनमें से एक साहब मंत्रालय की पांचवी मंजिल पर तो दूसरे साहब चौथी मंजिल पर बैठते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इनकी अनुमति के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता। आलम यह है कि कोई कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों न हो, अगर ये नहीं चाहेंगे तो वह काम कोई नहीं करा सकता। इसलिए इन दिनों इन दोनों अफसरों के पास आने-जाने वालों की कतार लगी रहती है। स्थिति यह है कि ये दोनों साहब हर किसी को दर्शन भी नहीं देते हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि इन दोनों अफसरों के पास आप बिना माध्यम के पहुंच ही नहीं सकते। भाई...! साहबों की ताकत ही कुछ ऐसी है। बताया जाता है कि इन साहब लोगों की कलम में इतनी ताकत है कि वे चाह दें तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है। अगर उन्होंने ठान लिया कि अमूक काम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए तो कोई माई का लाल नहीं है जो वह काम शासन-प्रशासन से करा सके। इस कारण इन दिनों इन दोनों साहबों की शासन-प्रशासन में तूती बोल रही है। इनकी हैसियत को देखकर कुछ लोग जल रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठ ही सकते हैं।

गरीबी में आटा गीला

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इन दिनों यह मप्र में हकीकत बनने जा रही है। दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन पूर्ववती सरकार के एक फैसले के कारण वर्तमान सरकार को उसकी मार झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने प्रदेश का बी-200 विमान कबाड़ में बेचकर नए विमान बी-250 यूएस का ऑर्डर दिया था। अब यह विमान बनकर तैयार है, लेकिन कोरोना के कारण विमान के भारत आने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। हालात सामान्य होने पर विमान प्रदेश लाया जाएगा। लेकिन सरकार के सामने समस्या यह है कि विमान की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने विमान का सौदा करीब 57-58 करोड़ रुपए में अमेरिका की कंपनी से किया था। इसके लिए दस फीसदी राशि भी कंपनी को भेज दी गई थी। विमान बनकर तैयार है लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद होने के कारण उसे नहीं लाया गया है। इस बीच विमान की कीमत भी लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए बढ़ गई है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता हो गया है। पहले से कर्ज में डूबी सरकार इस समय पाई-पाई के लिए मोहताज है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं इसी तरह बाधित रहीं तो प्रदेश के लिए खरीदे जा रहे विमान की कीमतें बढ़ती जाएंगी और सरकार पर बोझ बढ़ता जाएगा।

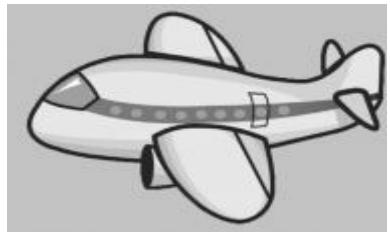

विवेक से काम लेना पड़ेगा...

राजनीति ही नहीं नौकरशाही में भी यह बात प्रचलित है कि मौके पर जो चौका मार दे वही आगे बढ़ता है। दोनों जगह जो लोग मौके का सही से फायदा उठा पाते हैं, वे छा जाते हैं। ऐसा ही मौका इन दिनों एक आईपीएस अधिकारी को मिला है। कहा जा रहा है कि अगर वे विवेक से काम करें तो उनकी लॉटरी लग जाएगी। दरअसल, उक्त आईपीएस अधिकारी को पुलिस विभाग के मुखिया का करीबी अफसर बनने का मौका मिला है। या यूं कह सकते हैं कि बड़े साहब ने उन पर अपना विश्वास जताया है और उन्हें अपना विश्वासपात्र बनाया है। जिस पथ पर उक्त आईपीएस अधिकारी पदस्थ किए गए हैं, वह पद पुलिस महकमे में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विभाग के मुखिया की हर गतिविधियां और हर निर्णय में ये साझेदार होते हैं। अत: ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उक्त आईपीएस अधिकारी ने विवेक के साथ काम किया तो उन्हें उच्च ओहदा मिल सकता है। गौरतलब है कि राजधानी में डीआईजी बनने के लिए कई अफसर लॉबिंग कर रहे हैं। इस पद के लिए अभी तक जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनकी पदस्थापना परिवहन विभाग में हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उक्त आईपीएस अधिकारी ने अपने काम से पुलिस विभाग के मुखिया को संतुष्ट कर दिया तो उन्हें राजधानी में उच्च पद पर पदस्थ किया जा सकता है। अब देखना यह है कि उक्त आईपीएस अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं?

यह भाजपा है...

भाजपा चाल, चेहरा और चरित्र वाली पार्टी मानी जाती है। इस पार्टी में पद का महत्व होता है और उक्त पद की गरिमा का ख्याल रखा जाता है। लेकिन विगत दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां मप्र के दो कद्दावर नेताओं के बीच कुछ ऐसा हुआ कि अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि भाई...! यह भाजपा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि विगत दिनों पार्टी अध्यक्ष दिल्ली स्थिति बंगले पर मप्र भाजपा के दो कद्दावर नेता पहुंचे थे। इनमें एक नेता हाल ही में अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। जबकि दूसरे नेता को मप्र में पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है और वे केंद्रीय नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं। बातचीत के दौरान नवागत कद्दावर नेता ने बात ही बात में दूसरे नेता को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसे अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया। यही नहीं उन्होंने नवागत नेताजी को सलाह दे डाली कि भाई...! यह भाजपा है। यहां हर बात नापतौल कर बोली जाती है। सूत्र बताते हैं कि अपने आपको किंगमेकर समझने वाले उक्त नेताजी को तब जाकर समझ में आया कि वर्तमान पार्टी में उन्हें किस तरह रहना है।

वैध बंद, अवैध चालू है

प्रदेश में सरकारी आदेश के तहत इन दिनों रेत खनन बंद है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन अवैध खनन का कारोबार चरम पर है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अवैध खनन करने वालों ने रेत की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। इसका असर यह हुआ है कि एक तगाड़ी रेत जो पहले 30 रुपए में मिलती थी, अब वह 90 रुपए की हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। लेकिन हकीकत यह है कि रेत का ये काला कारोबार सरकार की सरपरस्ती में ही चल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार चाह दे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। दरअसल, जानकारों का कहना है कि राजधानी में जो रेत आती है वह होशंगाबाद से आती है। वहां सरकार ने पुराने ठेकेदार को रेत का खनन करने की अनुमति दे दी है। क्योंकि नया ठेकेदार लूट-खसोट की आशंका से अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर चला गया है। अब जो ठेकेदार खनन कर रहा है, उसे सरकारी संरक्षण है और प्रतिबंध के बाद भी रेत का अवैध खनन कर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है।

भारत ने नकली काली नदी दिखाकर हमारा इलाका हड़प लिया है और वहां अपनी सेना तैनात कर दी है। नेपाल को तिब्बत जैसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। भारत के बढ़ते कदम को रोकने की जरूरत है। वरना वह हमारी बहुत सी जगहों पर कब्जा कर सकता है।

● **केपी शर्मा ओली**

चीन आया और उसने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खामोश हैं और परिदृश्य से गायब हैं। केंद्र सरकार को लद्दाख में चीन के अतिक्रमण को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। अभी तक बड़ी-बड़ी बात करने वाले प्रधानमंत्री चीन के इस कदम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। वे कहां गायब हैं।

● **राहुल गांधी**

मुझे और श्रीलंका के थिसारा परेरा को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी कालू कहकर बुलाते थे। पहले मुझे इस शब्द का अर्थ पता नहीं था। उस समय मुझे लगता था कि इस शब्द का मतलब तगड़ा घोड़ा है, लेकिन अब सच जानकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अब सनराइजर्स के खिलाड़ियों से पूछूंगा कि मुझे कालू क्यों कहते थे।

● **डैरिन सैमी**

कर्नाटक और मप्र की तरह भाजपा राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा ने कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा को जनता द्वारा चुनी गई सरकार पसंद नहीं आ रही है।

● **अशोक गहलोत**

जम्मू-कश्मीर के इकलौते कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या हो गई है, लेकिन आतंकियों की मौत पर राग अलापने वाले लोग अब कहां गायब हैं। इस हत्याकांड पर तथाकथित बुद्धिजीवियों की चुप्पी चिंता का विषय है। इन्हें मानवता तभी आती है, जब किसी घटना के पीछे जिहादी एजेंडा छिपा हो, वरना इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छिपा होता है, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग सेक्युलरिज्म की खाल में छिपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। ऐसे लोगों का हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। तभी इन्हें पता चलेगा कि असली सेक्युलरिज्म क्या होता है।

● **कंगना रानौत**

वाक्युद्ध

देश में भाजपा ने लोकतंत्र को आइसोलेशन में भेजा है और ममता बनर्जी ने उसे आईसीयू में पहुंचाया है। राज्य के लोग कोरोना वायरस की महामारी, आर्थिक संकट और तूफान से हुई तबाही से परेशान हैं, ऐसे में अमित शाह यहां के लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्हें तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है।

● **मोहम्मद सलीम**

पश्चिम बंगाल को ममता और माकपा ने बर्बाद किया है। हम तो उसे आबाद करने में जुटे हुए हैं। अगर इसके लिए वहां की जनता से सहयोग मांगा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहां की जनता भी चाहती है कि उन्हें भाजपा का मजबूत कंधा मिले। इस बार भाजपा वहां के लोगों की मंशा को पूरा करने वाली है।

● **संबित पात्रा**

क्या राज्यसभा में एनडीए 100 सदस्यों का जादुई आंकड़ा छू पाने में कामयाब हो जाएगा? क्या भाजपा के पास कांग्रेस से दोगुनी सीटें हो जाएंगी? आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्यों में बनाए और बिगाड़े जा रहे समीकरणों के आधार पर भाजपा और यूपीए के बीच अंकगणित का खेल रोचक हो गया है।

अबकी बार 100 पार

राज्यसभा में एनडी की गिनती 100 करने के लिए भाजपा पूरा दम लगाने में कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं कांग्रेस को साख बचाने का संघर्ष करना पड़ रहा है। आगामी 19 जून को राज्यसभा में कुल 24 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से 18 सीटें तो वही हैं, जिन पर चुनाव कोरोना वायरस संक्रमण के हालात के चलते इस साल मार्च में स्थगित कर दिया गया था।

जिन 24 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे, उनमें से 6 सीटें वो हैं, जो आगामी 40 दिनों के भीतर मौजूदा सदस्यों के रिटायरमेंट के कारण खाली होने वाली हैं। इनमें कर्नाटक की 4 और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की एक-एक सीट शामिल है। राज्यसभा चुनावों में सीटों, उम्मीदवारों और राज्यों में राजनीतिक समीकरणों का पूरा ब्योरा बिंदुवार समझें।

चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया है, उसके मुताबिक आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की कुल 24 राज्यसभा सीटों के लिए आगामी 19 जून को चुनाव होगा। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के उच्च सदन में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। साथ ही भाजपा के पास भी पूरी ताकत नहीं है इसलिए केंद्र सरकार को यहां बिल पास कराने के लिए अन्य पार्टियों को साधने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है।

245 सदस्यों वाली राज्यसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 224 है, जिसमें भाजपा के पास अभी कुल 75 सदस्य हैं और एनडीए की गिनती 91 की है। वहीं, कांग्रेस 39 सदस्यों के साथ सदन में है जबकि यूपीए की ताकत 61 सदस्यों की है। बीते मार्च में हुए चुनाव के दौरान भाजपा के सदस्यों की संख्या 81 से घट गई थी इसलिए इस बार भाजपा **कम से कम नौ सीटें** जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। ऐसा हुआ तो भाजपा की सदस्य संख्या कांग्रेस की तुलना में दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि भाजपा 9 सीटें जीती तो कांग्रेस को सीटों का नुकसान होगा ही।

हाल ही में कर्नाटक में सबको चौंकाते हुए भाजपा ने एरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती पर दांव खेला। जबकि यहां से उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा प्रभाकर कोरे, रमेश कट्टी, प्रकाश शेट्टी, निर्मल सुराना या प्रोफेसर एम नागराज में से किसी को बतौर कैंडिडेट सामने लाएगी। दूसरी तरफ, गुजरात से भाजपा ने अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा के साथ ही एक अतिरिक्त उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस से भाजपा में जुड़े नरहरि अमीन का नाम सामने रखा है।

मप्र में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हुई हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा दो सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे चुकी भाजपा ने दूसरी सीट पर भी दावेदारी ठोक दी है। भाजपा ने दूसरी सीट के लिए सुमेर सिंह सोलंकी का भी नामांकन करा दिया है। विधायकों के गणित के आधार पर भाजपा को दोनों सीटें मिलना तय है। बहरहाल, मप्र से फिर दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय है। लेकिन जिस सीट से फूलसिंह बरैया संसद पहुंचते रहे हैं, उससे मुकाबला कठिन होने के आसार हैं। इसी तरह, राजस्थान से भाजपा ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को राज्यसभा में लाने की तैयारी की है तो झारखंड की दो सीटों में से एक पर **कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला** करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश का नाम प्रकाशित किया है। अरुणाचल से नेबाम रेबिया के लिए भी भाजपा आश्वस्त है।

राज्यसभा चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर टूट-फूट का दौर चल रहा है। गुजरात में पिछले हफ्ते तीन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। राज्य विधानसभा में 2017 में जहां कांग्रेस के 77 विधायक थे, अब 65 ही बचे हैं। गुजरात से कांग्रेस के शशिकांत गोहिल और भरतसिंह सोलंकी का भविष्य तय होगा। राजस्थान से कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। वहीं, झारखंड से प्रकाश के मुकाबले में कांग्रेस ने शहजादा अनवर का नाम आगे रखा है। यहां एक सीट शिबू सोरेन की पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जा रही है।

● **जितेन्द्र तिवारी**

राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति

राज्यसभा में सत्तापक्ष की मजबूती उतनी ही जरूरी है, जितनी लोकसभा में। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि वह इस बार के राज्यसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीते ताकि वह मजबूत हो सके। वर्तमान समय में राज्यसभा में एनडीए के 91 सदस्य हैं। इनमें भाजपा के 75, जदयू के 5, शिअद के 3 और अन्य के 8 सांसद हैं। वहीं यूपीए के 61 सदस्य हैं। इनमें कांग्रेस के 39, डीएम के 7, आरजेडी के 5, एनसीपी के 4, शिवसेना के 3 और अन्य के 3 सदस्य हैं। वहीं बगैर गठबंधन के 68 सदस्य हैं। इनमें पीएमसी के 13, एआईएडीएमके के 9, बीजेडी के 9, सपा के 9, टीआरएस के 7, सीपीआईएम के 5, नामांकित 4 सदस्य हैं। ऐसे में भाजपा की पूरी कोशिश यह है कि वह इस बार राज्यसभा की अधिक से अधिक सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ले। वर्तमान समय में 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। उनमें आंध्रप्रदेश की 4, गुजरात की 4, कर्नाटक की 4, राजस्थान की 4, मप्र की 4, झारखंड की 2, मणिपुर की 1, मेघालय की 1, मिजोरम की 1 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट है। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने जमावट शुरू कर दी है। इसके लिए तोड़-फोड़ और जोड़-तोड़ का भी सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि अपने अभियान में कौन सफल होता है।

मप्र में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजनीति के सभी रंग दिखेंगे, इसका संकेत अभी से मिलने लगा है। हर बार से अलग हटते हुए इस बार मप्र में राजनीति का मिजाज बदला हुआ है। असंतोष, बगावत और भितरघात का खतरा भाजपा और कांग्रेस के ऊपर मंडराने लगा है। इसलिए अभी से साम (समझाना), दाम (आर्थिक प्रलोभन देना), दंड (बल प्रयोग) और भेद (कुटिलता पूर्वक शत्रु की शक्ति को कम करना) का सहारा लिया जा रहा है। उधर, बसपा ने सर्वे शुरू कराकर भाजपा और कांग्रेस को उलझा दिया है।

बगावत और भितरघात का डर...

मप्र में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे, यह तो तय नहीं है लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों में अंदरूनी घमासान चरम पर आ गया है। दलबदल के कारण खाली हुई 22 सीटों पर मामला पेचीदा हो गया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में आए विधायकों को टिकट देना पार्टी की मजबूरी है। वहीं, इस क्षेत्र से अब तक भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की मुखालफत ने संगठन को उलझा दिया है। भावी प्रत्याशियों को लेकर मुखालफत दोनों तरफ है। ऐसे में दोनों पार्टियों के **रणनीतिकारों** को रोजाना रणनीति बदलनी पड़ रही है।

भाजपा और कांग्रेस ने 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारियों को तैनात कर दिया है। ये प्रभारी अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन उनके सामने असंतोष, बगावत, भितरघात की जो तस्वीर आ रही है उससे उन पर उपचुनाव की तैयारी भारी पड़ रही है। भाजपा की बात करें तो आगर विधानसभा सीट के प्रभारी जगदीश अग्रवाल और जौरा प्रभारी दुर्गालाल विजय के सामने तो कम चुनौतियां हैं, लेकिन अन्य 22 सीटों के प्रभारियों के लिए कठिन अग्निपरीक्षा है। क्योंकि ये 22 सीटें उन सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की हैं, जो 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। इन पूर्व विधायकों के खिलाफ उनके क्षेत्र में माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नाखुश हैं ही भाजपा के नेता भी खुश नहीं है। भाजपा के लिए उपचुनाव का क्या महत्व है यह इसी से समझा जा सकता है कि पार्टी ने 8 पूर्व मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। सागर जिले की सुरखी विधानसभा में गोविंद राजपूत को जिताने का जिम्मा उसी जिले से पूर्व मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह को दिया गया है। सांची में मंत्री पद के लिए प्रतिक्षारत प्रभुराम चौधरी की सीट का प्रभारी रायसेन जिले से पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को दिया गया है। अनूपपुर में बिसाहूलाल सिंह को जिताने के लिए दो पूर्व मंत्रियों राजेंद्र शुक्ला और संजय पाठक को मैदान में उतारा गया है। वहीं, सुवासरा से हरदीप डंग की सीट पर प्रभारी के रूप में मंत्री पद के दावेदार जगदीश देवड़ा को जिम्मा सौंप दिया है। इन सीटों पर पिछला चुनाव हारने वाले किसी भी भाजपा नेता को सीट का प्रभारी नहीं बनाया गया है। ग्वालियर शहर की दोनों सीटों के लिए दिग्गज पूर्व मंत्रियों जयंत मलैया और गौरीशंकर बिसेन को भेजा जा रहा है।

कांग्रेस ने भी मैदानी जमावट शुरू कर दी है। पार्टी ने कई सीटों पर नेताओं को प्रभार देकर उन्हें सक्रिय कर दिया है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की नीति का अनुशरण करते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे

भाजपा ने संघ तो कांग्रेस ने 3 सर्वे एजेंसियों को मैदान में उतारा

उपचुनाव को लेकर जीत की रणनीति बनाने में भाजपा और कांग्रेस जुट गई हैं। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा ने विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति का आंकलन कराने के लिए संघ के पूर्णकालिकों को पहले ही तैनात कर दिया है। ये पूर्णकालिक घर-घर जाकर लोगों का मन जान रहे हैं, वहीं भाजपा की जीत के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं सत्ता में दोबारा आने के लिए कांग्रेस ने 2018 चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी एजेंसियों के जरिए 15 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रहे हैं। तीन अलग-अलग एजेंसियां सर्वे के काम में जुटी हैं।

कांग्रेस की सोच है कि अगर सिंधिया की घेराबंदी होगी है तो ग्वालियर संभाग की 16 सीटों का आसानी से जीता जा सकता है। इसके लिए पार्टी ने कभी **सिंधिया के करीबी** रहे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, ग्वालियर में सिंधिया के घुर विरोधी डॉ. गोविंद सिंह, केपी सिंह और पूर्व मंत्री लाखन यादव समेत अशोक सिंह को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के निशाने पर पाला बदलने वाले दलबदलू विधायकों से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे।

गौरतलब है कि मप्र में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर-चंबल की 16 विधानसभा सीटें भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई हैं। ये 16 सीटें तय करेंगी कि भाजपा और कांग्रेस का सियासी भविष्य क्या होगा। ग्वालियर-चंबल इलाके में जीत दर्ज करने वाले को सत्ता की चाभी मिलना तय माना जाता है। इस कारण यहां कांग्रेस से भाजपा में गए सिंधिया की साख दांव पर लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिंधिया के दम पर कांग्रेस ने ये इलाका जीता था, लेकिन इस बार सिंधिया विरोधी पार्टी में जा खड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का कहना है ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। भाजपा के नरोत्तम मिश्रा का मानना है कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल इलाके में उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में टीम कैसे तैयार होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर ग्वालियर चंबल इलाके में चुनाव मैदान में उतरेगी और वो भी सिंधिया के खिलाफ लड़ेगी। लेकिन देखना यह होगा कि कमलनाथ की रणनीति पर टीम कांग्रेस सिंधिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है। सिंधिया को उनके इलाके में मात देकर सत्ता में वापसी कर पाती है।

भाजपा और संघ के सर्वे में संकेत मिले हैं कि सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों में से करीब 10 के खिलाफ उनके क्षेत्र में जबर्दस्त माहौल है। ये वे विधायक हैं जो पहली बार कांग्रेस से जीते। लेकिन, इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। जीतने के महज 15 माह के भीतर ही दल बदलने से उनके सामने कई चुनौतियां हैं। वैसे इन क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए राह आसान नहीं होगी। भाजपा ने कमोबेश अपनी गाइडलाइन साफ कर दी है कि इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के **बागी विधायकों** पर ही वह दांव लगाएगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में अम्बाह, अशोकनगर, करैरा, ग्वालियर पूर्व, दिमनी, पोहरी, भांडेर, मुरैना, मेहगांव और हाटपिपल्या में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीते विधायक अब भाजपा में हैं। इन दस क्षेत्रों में ज्यादातर सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस के बागियों के आने से 2018 के भाजपा उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह को हराकर मुरैना में रघुराज सिंह कंषाना पहली बार कांग्रेस से जीते थे। गुर्जर समाज के बड़े नेता रुस्तम सिंह ने अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उनके समर्थक रघुराज सिंह कंषाना के साथ दिल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किल यह है कि 2018 के उनके मजबूत स्तंभ अब भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में उनके सामने उम्मीदवारों का टोटा है और अब उनकी निगाह भाजपा के ही **असंतुष्टों पर टिक गई** है। अगर कांग्रेस ने भाजपा के पुराने उम्मीदवारों पर दांव लगा दिया तो लड़ाई रोमांचक हो जाएगी। फिर चेहरे वही हो सकते हैं, लेकिन सिंबल बदला रहेगा।

बानगी के तौर पर अम्बाह सीट पर 2018 में कांग्रेस से लड़ रहे कमलेश जाटव निर्दलीय नेहा किन्नर से करीब साढ़े सात हजार मतों से जीते। इसी तरह पोहरी में पहली बार सुरेश धाकड़ भी बसपा के कैलाश कुशवाहा से 7918 मतों से कड़ी मशक्कत के बाद जीत सके थे। इन क्षेत्रों में भाजपा तीसरे नंबर पर थी। अब अम्बाह और पोहरी में भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं रहेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल और भी बड़ी होगी। भाजपा को उपचुनाव में विजय हासिल करने में सर्वाधिक भरोसा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। सिंधिया के प्रभाव में ही चंबल-ग्वालियर की अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। अब वह भाजपा में हैं और उनके लिए यह प्रतिष्ठापरक भी है। उधर, कांग्रेस भी भाजपा को शिकस्त देने के लिए सारे समीकरण आजमा रही है।

● **कुमार राजेन्द्र**

टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में भी बहुत टेंशन

भाजपा की तरह कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर टेंशन बहुत है। सिंधिया खेमे के लोगों को मात देने के लिए कांग्रेस अपने पुराने बागियों पर चांस लेने की तैयारी में हैं। लेकिन बागियों की एंट्री को लेकर कांग्रेस में ही एकमत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने ही चर्चा के दौरान कई नेताओं ने इस्तीफे की धमकी तक दे दी। उसके बाद कमलनाथ ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को टिकट सर्वे के आधार पर ही मिलेगा। दरअसल, उपचुनाव वाले सभी सीटों की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में लगे हैं। प्रेमचंद गुडडू की तरह ही भिंड के मेहगांव सीट से राकेश सिंह चतुर्वेदी को टिकट देने की चर्चा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह इनका विरोध कर रहे हैं। उधर, कांग्रेस ग्वालियर-चंबल अंचल की 16 सीटों को जीतने के लिए वहां के करीब 20 फीसदी दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने बसपा में सेंधमारी शुरू कर दी है। गत दिनों बसपा नेता प्रागी लाल जाटव सहित दो दर्जन से अधिक नेताओं ने मायावती का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसके अलावा डबरा नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी बसपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गईं। ये दोनों नेता ग्वालियर-चंबल इलाके में बसपा का बड़ा चेहरा माने जाते थे। इससे पहले बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश और पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।

सिंधिया बनाम कमलनाथ क्यों?

मप्र में शिवराज सिंह चौहान के सत्ता संभालने से अब तक हुए उपचुनावों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस के लिए मुश्किलों का अंदाजा सहज लगता है। वर्ष 2004 से 19 तक हुए 30 उपचुनावों में 19 भाजपा जीती है, यानी 63.33 प्रतिशत। भाजपा ने अपनी 13 सीटें बचाई, तो कांग्रेस की 6 सीटें छीन ली। हालांकि उसे 6 सीटें गंवानी भी पड़ीं। जबकि कांग्रेस 10 सीटें जीत सकी यानी 33.33 प्रतिशत। वह 4 सीटें छीनने में कामयाब रही। ऐसे में कांग्रेस को अपने खाते की सीटें बचाने के लिए भाजपा से कड़ी चुनौती मिलना तय है।

19 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से जोर-आजमाइश में जुट जाएंगी। राज्य के लिए यह उपचुनाव कोई छोटा-मोटा उपचुनाव नहीं है। बल्कि, इसमें राज्य की सत्ता फिर से उलट-पुलट करने का माद्दा है। लेकिन, कांग्रेस यह चुनाव दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तो वह हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से प्रदेश की सत्ता में वापसी चाह रही है; और दूसरी ओर उसकी कोशिश पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और कभी कांग्रेस की **फर्स्ट फैमिली** के बेहद करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से सियासी हिसाब भी चुकता करना है।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के बाद विधानसभा की 24 सीटों के लिए उपचुनाव भी होने हैं। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के लिए सत्ता बचाने का चुनाव होगा तो कांग्रेस और कमलनाथ के लिए मुश्किल से हाथ आई सत्ता गंवाने का बदला लेने का। इस तरह से दोनों दलों की राजनीति इस उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यह प्रदेश के लिए पूरी तरह से मिनी असेंबली इलेक्शन की तरह ही होने वाला है। मार्च में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा की सरकार इसलिए बन पाई, क्योंकि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 बागियों ने अपनी विधायकी छोड़ दी। यानि, कमलनाथ सरकार नहीं गिरती अगर सिंधिया ने कांग्रेस से अपना रास्ता नहीं **नाप लिया** होता। जाहिर है कि कांग्रेस और कमलनाथ के मन में जो खुन्नस सिंधिया के लिए होगी, मुख्यमंत्री और भाजपा के लिए शायद उससे कम ही होगी।

सबसे बड़ी बात ये है कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 22 सीटें सिंधिया समर्थकों की ही हैं और माना जा रहा है कि वही सारे लोग इस बार भी हाथ में कमल थामकर भाजपा प्रत्याशियों के रूप में कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने चुनावी मैदान में खड़े होंगे। यानि यह सीधी चुनौती कमलनाथ के लिए कांग्रेस की सारी सीटें बचाए रखने की है, तो सिंधिया को इस बार हवा का रुख भगवा की ओर करना है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अब अपने पूर्व श्रीमंत को ही सीधे निशाने पर लेने में लगे हैं। मसलन, ग्वालियर-चंबल इलाके के कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज केके मिश्रा ने सिंधिया पर ट्विटर के जरिए यह कहकर हमला किया कि, 'क्या मजाक बनाया हुआ है, पिछले दिनों घोषित मप्र भाजपा की चुनाव संचालन समिति की सूची में छठवें स्थान पर? 11 मार्च को बतौर राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा में भी नाम के आगे 'श्रीमंत' शब्द गायब, जबकि महाराष्ट्र के एक प्रत्याशी के नाम के आगे श्रीमंत उदयना राजे भोंसले लिखा हुआ है! मजाक?'

प्रदेश के राजनीतिक पंडितों की मानें तो उपचुनाव को सिंधिया बनाम कमलनाथ बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से सारे घोड़े खोल दिए गए हैं। इसकी वजह ये है कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 22 सिंधिया समर्थकों की तो हैं ही, उनमें से 16 ग्वालियर-चंबल संभाग में पड़ती हैं, जिसे सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि ग्वालियर-चंबल के लोगों ने विद्रोह को तो स्वीकार कर लिया है। लेकिन, इस इलाके की एक खासियत ये है कि यहां धोखेबाजी को सबक सिखाया जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों को धोखेबाज साबित करने की कोशिशों में जुटी है और यही वजह है कि इस चुनावी जंग को सिंधिया बनाम कमलनाथ करने का प्रयास है।

● **अरविंद नारद**

कांग्रेस ने खोला है सिंधिया के खिलाफ मोर्चा

दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता तो शुरू से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर धोखा देने और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, इसके लिए कांग्रेस लोगों के पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान का भी खूब जिक्र कर रही है, जिसमें उन्होंने पूर्व कांग्रेसी नेता को 'विभीषण' की संज्ञा दी थी। गौरतलब है कि महाकाव्य रामयाण में 'विभीषण' ने अधर्म में अपने भाई रावण का साथ न देकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ देना स्वीकार किया था। अलबत्ता, समाज में 'विभीषण' के नाम की चर्चा अक्सर अपनों के साथ धोखा करने वालों के रूप में की जाती है।

ऑडियो की राजनीति

मप्र में जब भी चुनावी माहौल होता है ऑडियो-वीडियो सामने आने लगते हैं। उपचुनाव की दस्तक से पहले मप्र की राजनीति में इन दिनों ऑडियो की राजनीति गरमाई हुई है। इसके निशाने पर सिंधिया हैं।

मप्र की राजनीति में इन दिनों ऑडियो की राजनीति गरमाई हुई है। ऑडियो की राजनीति के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। आश्चर्य की बात यह है कि सोशल मीडिया पर चार ऑडियो क्लिप जारी हुई हैं। एक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सिंधिया के सहयोग से गिराने की बात कह रहे है तो दूसरे में अशोकनगर की कांग्रेस नेत्री से बातचीत करते स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया सुनाई दे रहे है। तीसरे ऑडियो में मौ टीआई राजकुमार शर्मा सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि महाराज मुझे लहार ले जा रहे हैं। वहीं चौथे ऑडियो में सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी एक युवक को आंख फोड़ने की **धमकी** दे रही हैं। उपचुनाव से पहले आने वाले इन ऑडियो ने प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं कांग्रेस को मौका दे दिया है कि वह सरकार के खिलाफ माहौल बना सके। इन वायरल ऑडियो ने मप्र की सियासत एक बार फिर गरमा दी है। जहां एक बार फिर कांग्रेस हमलावर हो गई है तो दूसरी ओर भाजपा बचाव की मुद्रा में दिख रही है।

पहला ऑडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे के दौरान 8 जून का बताया जा रहा है जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो और अब वीडियो में केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने का जिक्र कर रहे हैं। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के बलिदान की बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो के बाद ट्वीट का दौर चला और एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए।

दूसरा ऑडियो विधानसभा चुनाव 2018 के समय का है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेत्री अनीता जैन से टिकट न दिलवा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। अनीता जैन ज्योतिरादित्य सिंधिया से किसी पाराशर के कहने पर 50 लाख रुपए किसी अग्रवाल के पास रखवाने की बात कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया है। अग्रवाल ने इससे संबंधित एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा है कि सिंधिया ने भोपाल के कांग्रेसी मित्र के साथ मिलकर भाजपा से कांग्रेस में आए सरताज सिंह को टिकट बेचा है। मानक अग्रवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, अशोकनगर की अनीता ने जिस तरीके से सिंधिया पर आरोप लगाया कि उनके पीए पाराशर के कहने पर परशु अग्रवाल के पास 50 लाख रुपए टिकट के लिए रखवा दिए थे। इसी तरीके से होशंगाबाद विधानसभा का टिकट सरताज सिंह को एक करोड़ रुपए में उनके भोपाल के एक कांग्रेसी मित्र ने मिलकर दिलवाया था।

तीसरा ऑडियो ग्वालियर जिले के मौ टीआई राजकुमार शर्मा का वायरल हुआ है। इसमें वे सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि मंत्री की कथनी और करनी में अंतर है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरी विधानसभा में आ जाओ। वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। टीआई बोलते हैं कि नहीं महाराज मुझे लहार ले जा रहे हैं। सामने वाला फिर पूछता है लहार। इस पर टीआई बोलते हैं कि गोविंद सिंह के खिलाफ महाराज सिंधिया ले जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में टीआई राजकुमार शर्मा का कहना है कि यह **उनके खिलाफ साजिश** है। वायरल करने वाले को नोटिस दूंगा। वही पूर्व मंत्री एवं लहार विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने टीआई पर कार्रवाई के लिए डीजीपी विवेक जौहरी को चिट्ठी लिखी है।

चौथा ऑडियो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुकीं इमरती देवी से जुड़ा है। जिसमें वे एक युवक को आंख फोड़ने की धमकी दे रही हैं। इन चारों ऑडियो से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस इनको आधार बनाकर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले कई और ऑडियो-वीडियो मप्र की राजनीति में तहलका मचाएंगे।

● **विकास दुबे**

शह और मात का खेल

उपचुनाव और राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाले चुनाव की राजनीति में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। जिसमें अपनी-अपनी जमीन बचाने के लिए महाराजा और राजा की लड़ाई चरम पर है और जिसके मजे प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ले रही है। लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में भी सिंधिया सरकार चल रही थी तो अब भाजपा की शिवराज सरकार में भी सिंधिया सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज के ऑडियो को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इशारे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने का यह खेल खेला गया जिसमें सरकार गिराने वाले पूर्व विधायकों को मोटी रकम दी गई। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए सियासी तीर छोड़कर सियापति रामचंद्र की जय बोल दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। हमारा धर्म तो यही कहता है। और लोगों के लिए प्रश्न छोड़ दिया कि सियापति रामचंद्र की जय क्यों बोलो?

पटरी पर मेट्रो प्रोजेक्ट

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एक बार फिर पटरी पर उतरने को तैयार है। लेकिन यह प्रोजेक्ट कब पूर्ण होगा, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इसके साथ शुरू हुआ लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट लगभग 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है। दरअसल, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में कोई न कोई बाधा आती रही है। अभी तक यह प्रोजेक्ट बजट के अभाव में लड़खड़ाता रहा है। पिछले तीन माह से मेट्रो रेल का काम कोरोना संक्रमण के कारण रूका हुआ है। अब इस रुके प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है।

वहीं दूसरी तरफ बहुप्रतिक्षित प्रोजेक्ट के लिए लोन का रास्ता साफ हो गया है। यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से 3200 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत हो गया है। लेकिन इस लोन के ब्याज का भुगतान डॉलर के हिसाब से करना पड़ेगा। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बंद अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होने पर अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। भारत सरकार, मप्र सरकार, मेट्रो रेल कंपनी और ईआईबी की ओर से लोन की शेष औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मेट्रो रेल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि ईआईबी 400 मिलियन यूरो (3200 करोड़ रुपए) का लोन देगा।

ईआईबी ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। इसके बाद भारत सरकार, मप्र सरकार और मेट्रो रेल कंपनी ने अपनी ओर से औपचारिकताओं को पूरा कर लिया। मेट्रो रेल कंपनी के अफसरों के अनुसार यदि लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाते। ईआईबी के इस लोन की ब्याज दर परिवर्तनशील है। दर इस बात पर निर्भर करेगी कि भुगतान के समय यूरोप के बैंक आपस में कर्ज देते समय कितना ब्याज लेते हैं। इसे यूरो बोर कहा जाता है। मौजूदा स्थिति में यह ऋणात्मक है। इस यूरो बोर पर आधा प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा और ऋणात्मक को शून्य माना जाएगा। इसके अलावा मेट्रो के निर्माण के दौरान कोई भुगतान नहीं करना है। इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो गईं हैं। सभी पक्षों के बीच एक अनुबंध होना है। इसके लिए सबकी उपस्थिति जरूरी है। कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन खत्म होने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने पर संबंधित अधिकारी यूरोप जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

पांच साल पहले भोपाल मेट्रो के लिए जापान के इंटरनेशनल को ऑपरेशन एसोसिएशन (जायका) ने लोन पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। लेकिन अक्टूबर 2016 में पता चला कि जायका ने लोन देने से इनकार कर दिया। जायका की ब्याज दर केवल 0.3 प्रतिशत थी, लेकिन इसके साथ ही जापानी कंपनियों से 30 फीसदी मटेरियल खरीदने, और 30 फीसदी अतिरिक्त मटेरियल जापान और भारत की, संयुक्त कंपनियों से लेने जैसी शर्तें शामिल थीं। इसके लिए जापान की कंपनियां ट्रेक और ट्रेन में बदलाव चाह रहीं थीं, जिस पर मप्र मेट्रो रेल कंपनी सहमत नहीं हुई थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल का काम फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू की जा रही हैं।

मेट्रो प्रोजेक्ट की मैदानी हकीकत यह है कि केवल 247 करोड़ रुपए का 6.22 किमी के रूट के सिविल वर्क का काम जमीन पर शुरू हुआ था और वह भी तीन माह से बंद है। कोरोना लॉकडाउन के कारण मजदूरों के जाने के बाद कांट्रेक्टर कंपनी को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उधर, दूसरी हकीकत यह है कि शेष रूट के सिविल वर्क या ट्रेक बिछाने या किसी अन्य कार्य के लिए टेंडर भी जारी नहीं हुए। लॉकडाउन के कारण बंद हुआ मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तीन महीने बाद शुरू हो गया है। कान्हासैंया में स्थित मेट्रो के स्लैब (वाया डक्ट) निर्माण के कारखाने में काम शुरू हो गया है। यहां अभी 50 मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि पहले 200 मजदूर लगे थे। अगले कुछ दिनों में फील्ड में भी मेट्रो का काम शुरू होने की संभावना है। काम बंद होने से मेट्रो का काम कम से कम 6 महीने और पिछड़ गया है। यदि यह काम चालू रहता तो अब तक गर्डर लॉन्चिंग शुरू हो जाती।

एम्स से सुभाष नगर तक 6.22 किमी के जिस हिस्से का काम चल रहा है, उसमें कुल 212 पिलर हैं। इनमें से 52 बनकर तैयार हैं। लगभग इतने ही पिलर की फाउंडेशन का काम चल रहा था, जो अचानक रोक दिया गया। अभी कारखाने में काम शुरू हुआ है, लेकिन इसे पूरी गति पकड़ने में कम से कम एक माह लगेगा। विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हैं।

● **रजनीकांत पारे**

योजना के अनुसार ये होगी लागत

अभी तक प्लान के मुताबिक भोपाल मेट्रो की लागत 6941 करोड़ रुपए और इंदौर मेट्रो की लागत 7500 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें कीमतें बढ़ने, एक्सचेंज रेट में बदलाव, काम में देरी के कारण कोई भी बढ़ोतरी होती है, तो उसे प्रदेश सरकार को वहन करना होगा। यह शर्त मेट्रो के लिए केंद्र, राज्य सरकार और मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) के बीच होने वाले एमओयू में शामिल हैं। एमओयू के अनुसार, मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड यदि लोन चुकाने में चूकी तो इसका खामियाजा भी प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेट्रो के लिए जमीन के अधिग्रहण से लेकर विस्थापितों के पुनर्वास तक का खर्च राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा। इसमें लोगों को बसाने का काम भी सरकार को करना होगा। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार मेट्रो के काम के लिए एमपीएमआरसीएल को अपने यहां के सभी टैक्स से छूट देगी या उन करों की पूर्ति करेगी।

बे बस मप्र

पूरा देश अनलॉक हो गया है, लेकिन मप्र में बसों के पहिए अब भी लॉक हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में लोग पैदल या लिफ्ट लेकर ऑफिस जाने और आने के लिए मजबूर हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी लोगों को टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गरीबी में आटा गीला हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी भोपाल की सिटी बसों के साथ ही प्रदेशभर में करीब 35 हजार से अधिक यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं, इस कारण 60,000 ड्राइवरों और 90,000 कंडक्टर-क्लीनरों के सामने रोजी-रोटी का संकट मंडरा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बस ऑपरेटर बस चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उनसे लॉकडाउन के दौरान 3 माह बसें खड़ी होने के बावजूद टैक्स का दबाव बना रही है। वहीं नए-नए कायदे-कानून भी लाद रही है। इससे बस संचालकों पर दोहरी मार पड़ रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन ने और खराब कर दी है। ऐसे में सरकार आबकारी और परिवहन विभाग के माध्यम से आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है। सरकार की इसी कोशिश का नतीजा है कि शराब की बिक्री से इस साल मिलने वाला करीब 15 हजार करोड़ का राजस्व भी डूबता नजर आ रहा है। ऐसी ही स्थिति अब परिवहन विभाग में भी नजर आ रही है। पिछले एक माह से बस संचालक सरकार से लगातार चर्चा कर मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन अवधि में संचालन बंद होने के कारण सभी बसों का टैक्स शून्य किया जाए, लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात बसों के संचालन की नीति का शासन स्पष्टीकरण दे, सोशल डिस्टेंस नीति में बसों का संचालन पर शासन मोटर मालिकों से प्रदेश स्तर पर चर्चा करे, तीन माह में बसों के बंद संचालन अवधि में बेरोजगार कर्मचारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाए और बसों में 50 प्रतिशत सवारी बैठाने के निर्णय के तहत किराया दोगुना किया जाए। उन्होंने किराया बढ़ाने को लेकर तर्क दिया है कि सरकार ने यात्री बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों को मंजूरी दी है, हम लोग अपने नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ बसें नहीं चलाई जा सकतीं है। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारी भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं इसका भी हाल आबकारी विभाग जैसा न हो जाए।

लाखों का रोजगार छीना

प्रदेश में बसें बंद होने के कारण 60,000 ड्राइवरों और 90,000 कंडक्टर-क्लीनर बेरोजगार हो गए हैं। एक बस के जरिए दो ड्राइवर और 3 से ज्यादा कंडक्टर, क्लीनर का रोजगार चलता है। इसके साथ ही बसों की रिपेयरिंग, उनकी डेंटिंग-पेंटिंग के साथ उसकी ऑयल ग्रेसिंग करने से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिलता है। बसों से जुड़ा व्यापार भी होता है। कई व्यापारियों और कारोबारी का बिजनेस बस ही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में यात्री बसों के पहिए थमे हुए 85 दिन से ज्यादा हो गए हैं। सरकार बसों के संचालन को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है।

लॉकडाउन के कारण राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में बंद की गई बसें दोबारा शुरू करने के बारे में सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। दरअसल, राज्य शासन के द्वारा लॉकडाउन 5 में भोपाल, इंदौर व उज्जैन संभाग को छोड़कर अन्य संभागों में बसों के संचालन को अनुमति दे दी गई थी। लेकिन 2-3 दिन कुछ बसों के संचालन के बाद इन्हें फिर बंद कर दिया गया। बस ऑपरेटर का कहना है कि जिन जिलों में बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। वहां भी 50 प्रतिशत क्षमता में सवारी बैठाने की जो शर्त गाइडलाइन में दी गई है, उससे भारी परेशानी होना है। क्योंकि क्षमता से अधिक सवारी ढोने के बाद ही संचालन खर्च पूरा होगा। ऐसे में सवारी से किराया दोगुना लेना पड़ेगा जो सरकार के निर्धारित मापदण्ड अनुसार आपत्तिजनक होगा। मध्यप्रदेश प्राइम रूट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को समस्या से अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही इसका हल निकालने की बात कही है।

सरकार के निर्देश के बाद भोपाल, इंदौर व उज्जैन संभाग को छोड़कर अन्य संभागों में जो कुछ बसों का संचालन हो रहा था, उनके पहिए भी 1 जून से थम गए हैं। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि भारत में कोरोना के प्रकोप पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बसों का संचालन ग्रीन जोन एवं यलो जोन में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा एवं हमारे स्टाफ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बसों का संचालन बंद रखा गया है।

बस ऑपरेटरों पर तीन महीने का 70 करोड़ रुपए का **टैक्स बकाया है।** ऑपरेटरों की मांग है कि अप्रैल, मई और जून माह का यह टैक्स माफ किया जाए। बता दें कि बस ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा था। परिवहन महकमे ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन में बसों का संचालन ना हो पाने के कारण टैक्स माफी की मांग की थी। सूत्र बताते हैं कि सरकार जल्द ही बैठक कर फैसला ले सकती है। जिसमें ऑपरेटरों के टैक्स में 40 फीसदी तक की राहत देने की बात कही जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां सिटी बसों (लाल बसों) का संचालन कराने में सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सूत्रों का कहना है कि राजधानी में बसों का संचालन करने वाली प्रसन्ना पर्पल कंपनी का करीब साढ़े 4 करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है। कंपनी लगातार अपनी बकाया राशि की मांग कर रही है। वहीं सरकार को ऑपरेटरों को भी 6 करोड़ रुपए देना है। उधर, नगर निगम की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। ऐसे में सिटी बसों का संचालन अधर में लटका हुआ है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस दिशा में फिलहाल कोई भी कदम उठाती नहीं दिख रही है। उधर, लोगों की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

● **सुनील सिंह**

स्कॉलरशिप का तोहफा

होनहार बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप

नया शिक्षा अधिनियम जारी करते हुए डीजीपी विवेक जौहरी ने बताया कि अब उन पुलिसकर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। 10वीं और 11वीं की परीक्षा में जिन बच्चों ने 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए हैं उन्हें पुलिस विभाग की तरफ से 4 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। जिन बच्चों के 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक होंगे उन्हें ढाई हजार रुपए की राशि दी जाएगी। 12वीं क्लास में 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले पुलिसकर्मी के बेटे की कॉलेज फीस में भी मदद की जाएगी और निजी कॉलेज में पढ़ने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी 75 हजार तक की कॉलेज फीस में मदद की जाएगी।

देश में अक्सर यह बात आम लोगों की जुबान से सुनी जाती है कि पुलिसकर्मी का बच्चा किसी काम का नहीं होता। इसकी वजह यह है कि लगभग सभी राज्यों में अमला कम होने के कारण पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को 12 से 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में पुलिसकर्मी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मप्र में पुलिसकर्मियों की इस व्यथा को डीजीपी विवेक जौहरी ने महसूस किया है और पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हुए ऐलान किया है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को पुलिस विभाग स्कॉलरशिप देगा। डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बनेगी और होनहार बच्चों की पढ़ाई में विभाग पुलिसकर्मियों की मदद करेगा। डीजीपी विवेक जौहरी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा न बने इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है और पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए नया शिक्षा निधि नियम जारी किया जाएगा और 11वीं, 12वीं और निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को स्कॉलरशिप पुलिस विभाग की ओर से दी जाएगी।

डीजीपी विवेक जौहरी की ये सौगात कई **पुलिसकर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है** क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी के कारण पुलिसकर्मी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ा पाते हैं और अब जब विभाग की तरफ से उन्हें मदद मिलेगी तो उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार हो सकेगा। मप्र पुलिस के इतिहास में पहली बार नवीन शिक्षा निधि का गठन किया गया। इस शिक्षा निधि का फायदा राज्य के करीब डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने की उम्मीद है। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों द्वारा शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने एक जून 2020 से नवीन शिक्षा निधि नियमावली जारी की है। इसके तहत ही पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस महानिदेशक द्वारा पूर्व की शिक्षा निधि-शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को बदलकर नवीन शिक्षा निधि नियमावाली जारी की गई है। इसमें अशासकीय संस्थानों में अध्ययन करने वाले पात्र बच्चों की शासकीय महाविद्यालयों के अनुरूप ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा।

पुलिसकर्मियों के 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत बच्चे, जिनका पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत 60 से 84 तक है, को 2500 रुपए और 85 प्रतिशत या अधिक है तो 4 हजार रुपए वार्षिक राशि दी जाएगी। बारहवीं कक्षा के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स (4 या 5 वर्षीय), स्नातक (3 से 4 वर्षीय), स्नात्कोत्तर (2 से 3 वर्षीय) तथा डिप्लोमा कोर्स में गत वर्ष 60 प्रतिशत या अधिक अंको से परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा शासकीय महाविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य से मान्यता प्राप्त स्वशासी, गैर शासकीय महाविद्यालय या संस्थान में अध्ययनरत बच्चों को शासकीय महाविद्यालय में संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित वार्षिक ट्यूशन फीस अथवा क्लेम की जाने वाली वार्षिक फीस, दोनों में से जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। शिक्षण सत्र की वार्षिक (दो सेमेस्टर) ट्यूशन फीस अधिकतम 75 हजार रुपए तक देय होगी।

दिवंगत हुए ऐसे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी जिन्हें असाधारण परिवार पेंशन स्वीकृत होती है, के बच्चों को भी पात्रता अनुसार ट्यूशन फीस प्रदान की जाएगी। ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप-सेनानी से आरक्षक स्तर के कर्मियों के अध्ययनरत प्रथम दो बच्चों के लिए होगी। बाल आरक्षक स्वयं के वयस्क होने तक शिक्षा निधि से पात्रतानुसार ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकता है। जिस शाखा के अधीन बाल आरक्षक पदस्थ हैं, उस शाखा प्रभारी का दायित्व रहेगा कि वह उसका प्रकरण इकाई प्रमुख के माध्यम से नियमानुसार भेजें।

ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राशि पात्रतानुसार नियमित रूप से प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही प्रदान की जाएगी। किसी कक्षा-सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने पर उस कक्षा-सेमेस्टर के लिए दूसरी बार **प्रतिपूर्ति राशि नहीं** दी जाएगी। लगातार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही पात्रतानुसार ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। विगत शिक्षण सत्र में गैप, पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं होगी। इकाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का इकाई स्तर की कमेटी द्वारा परीक्षण कर, जोन-रेंज को भेजा जाएगा, जिसका जोन स्तर पर बनाई गई कमेटी द्वारा परीक्षण कर, अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। यह योजना शिक्षण सत्र 2020-21 से आगामी आदेश तक आने वाले शिक्षण सत्रों के लिए मान्य होगी। मध्यप्रदेश पुलिस शिक्षा निधि से राशि स्वीकृति के संबंध में पुलिस महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

● **नवीन रघुवंशी**

तीसरे मोर्चे की गोलबंदी

मप्र के 15 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। बसपा, सपा के बाद अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनावी तैयारी कर रही है। वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होना है, लेकिन उनकी हार-जीत का गणित बिगाड़ने के लिए तीसरा मोर्चा आकार ले रहा है। गौरतलब है कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बसपा और सपा ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में 2018 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। वो तीसरे मोर्चे से भी संपर्क कर रही है। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में कांग्रेस से आगे रही जनाधार नेशनल पार्टी अब मप्र में भी दस्तक देने जा रही है। पार्टी ने घोषणा की है कि 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी।

भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शाह बट्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके लिए पार्टी तीसरा मोर्चा के घटक दलों से संपर्क कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सबसे ज्यादा असर महाकौशल और कुछ मालवा अंचल के इलाकों में है। लेकिन पहली बार पार्टी ग्वालियर चंबल इलाके में अपने उम्मीदवार खड़ा कर प्रमुख सियासी दलों के समीकरण को बिगाड़ने की तैयारी में जुट गई है। मनमोहन शाह बट्टी के मुताबिक जल्द ही तीसरा मोर्चा के कई नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। उसमें 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके प्रभाव वाले अनूपपुर, सुरखी, सांची के अलावा मालवा-निमाड़ की सीटों पर पूरे दम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी।

2018 के चुनाव में दलों में बंटी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया था। जीजीपी प्रत्याशियों ने 6 लाख 75 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर तो पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर थी। हालांकि उपचुनाव से पहले पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी शुरू हो गई है। भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने-अपने बैनर तले 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बहरहाल 24 सीटों में तीसरे दल के **नेता कितना प्रभावी होंगे** यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि बसपा के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भाजपा और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगड़ना तय है।

2018 के विधानसभा चुनाव नतीजे पर नजर डालें तो महाकौशल इलाके में गोंडवाना फैक्टर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी की थी। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। 2018 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 76 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2003 के चुनाव में जीजीपी ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीटें जीती थीं। उसके बाद 2008 के चुनाव में दो टुकड़ों में बंटी पार्टी ने अलग-अलग सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। जिसके चलते पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया था। लेकिन 2018 के चुनाव में जीजीपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के वोट कटवा दिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भले ही ग्वालियर चंबल इलाके की सीटों पर ज्यादा असर ना हो लेकिन मालवा-निमाड़ समेत रायसेन, सागर और अनूपपुर में वो अपना असर दिखा सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर उपचुनाव में तीसरे मोर्चे की गोलबंदी हो गई तो यह भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

उपचुनाव में बिगड़ सकता है भाजपा-कांग्रेस का खेल

उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। लेकिन बसपा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। ग्वालियर-चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस के बाद यहां बसपा और सपा का भी प्रभाव है। विधानसभा चुनाव 2018 में बसपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी। जिसमें से एक सीट ग्वालियर-चबंल की थी। बसपा भी मध्यप्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बसपा अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बसपा की नजर भाजपा और कांग्रेस के बागियों पर भी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा ने मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ा था। सपा को एक सीट में जीत मिली थी जबकि बसपा को दो सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने भिंड और दमोह जिले की पथारिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनावों में बसपा करीब 5 फीसदी वोट प्रतिशत के साथ मध्यप्रदेश में तीसरे स्थान पर थी। बहुजन समाज पार्टी मध्यप्रदेश की 97 सीटों पर तीसरे स्थान पर थी। जबकि 6 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। ऐसे में उपचुनाव में बसपा मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बसपा की नजर मध्यप्रदेश के बागियों पर हो सकती है। कांग्रेस की नजर ग्वालियर-चंबल में एससी-एसटी वोट पर है। यही कारण है कि बसपा के वोट बैंक में कांग्रेस ने अब सेंध लगाना शुरू कर दिया है।

आतंकवाद कोरोना से खतरनाक

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। भारत का स्वर्ग कही जाने वाली प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह अप्रतिम घाटी इस देश की शान ही नहीं, बल्कि मस्तक भी है। लेकिन दुख होता है कि सरकारों द्वारा इस स्वर्ग में शांति बहाली के लाख दावों तथा वादों के बावजूद यहां आज भी डर, दहशत और अशांति व्याप्त है। हर साल यहां न जाने कितने ही निर्दोष भारतीय नागरिक आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और हमारी सुरक्षा में दिन-रात लगे हमारे वीर जवान इस भारत-भूमि और यहां रहने वाले भारतीयों की रक्षा करते-करते शहीद हो जाते हैं। सत्ताएं आती हैं। खोखले दावे करती हैं। अपनी-अपनी सियासी बिसात बिछाती हैं और चली जाती हैं। मगर भारत के इस स्वर्ग में नरक की तरह दिन-रात हमलों और हत्याओं का खेल यूं ही चलता रहता है। इस दर्द को एक सच्चा भारतीय ही महसूस कर सकता है।

हिंसा का नया दौर अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हुआ, जब नियंत्रण रेखा के पास केरन सेक्टर में ऑपरेशन रेंडोरी बेहाक के तहत चली कार्रवाई में एकसाथ पांच सैनिक शहीद हुए और पांच आतंकवादियों की मौत हुई। घुसपैठियों के समूह के बारे में जानकारी मिलने पर सेना ने उन्हें घेरने के लिए सैनिकों को मौके पर भेजा था। यह एक कठिन पहाड़ी इलाका था, जहां भारी बर्फबारी भी हुई थी। इससे आतंकवादियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। फिर भी हमारी जांबाज सेना ने अंततः घुसपैठियों को खत्म कर दिया। हालांकि इसमें पांच सैनिक शहीद हो गए। इन उलटफेरों के बाद 5 मई को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में अपने पैतृक गांव बेगपोरा में छिपे हिजबुल मुजाहिद्दीन के ऑपरेशनल चीफ रियाज नाइकू को मार गिराया। नाइकू पिछले 8 साल से यहां सक्रिय था। पिछले साल अलकायदा की कश्मीर यूनिट 'अंसार गजवत-उल-हिंद' के कमांडर जाकिर मूसा को ढेर करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सबसे बड़ी सफलता थी।

हालांकि, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान चले जाने से कश्मीर में चल रही हिंसा से ध्यान हट गया है। लेकिन घाटी और नियंत्रण रेखा दोनों पर आतंकी गतिविधियों में नाटकीय वृद्धि को देखते हुए, जिसमें 6 साल के बच्चे सहित 4 नागरिकों की हत्या भी हुई; गर्मियों के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। स्तंभकार नसीर अहमद कहते हैं कि ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान को कोविड-19 महामारी के मरीजों को देखने और उनकी जान बचाने की जरूरत है, तब हिंसा की आशंका बढ़ रही है। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि यह गर्मियों तक न चले।

एलओसी पर झड़पों में अचानक हुई वृद्धि को सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों को भारत की तरफ भेजने की पाकिस्तान की कोशिश का नतीजा बताया है। सुरक्षाकर्मियों की हत्या इस दावे को **सत्यापित** भी करती है। लगभग सभी उग्रवादी जो मुठभेड़ों में मारे गए या घात लगाए बैठे थे; कश्मीरी थे। इन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में प्रशिक्षण लिया था। दक्षिण कश्मीर में उनके परिवारों ने संबंधित थानों में उनके शव लेने के दावे किए। हालांकि पुलिस ने उन्हें देने से मना कर दिया। क्योंकि इससे उनके अंतिम संस्कार की एक बड़ी कड़ी बन जाती। उनके शव उत्तरी कश्मीर में कहीं दफनाए गए थे।

घाटी में जैसे सुरक्षा स्थिति बन रही है, उसमें हालिया हिंसक घटनाओं से परे देखने की भी जरूरत है। एक, इस पैमाने पर हिंसा पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद पहली बार हुई है। इसने एक बार फिर आतंकवाद को केंद्र में ला दिया है, जो आगे गर्मियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरा, हमलों का दावा एक नए आतंकवादी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने किया है। इसके अलावा एक और उग्रवादी संगठन तहरीक-ए-मिल्लत-ए-इस्लामी (टीएमआई) ने अपने जन्म की घोषणा की है और दोनों का दावा है कि उनकी उत्पत्ति स्वदेशी है। अब लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक दूरगामी रणनीति है, जिसमें यह जाहिर करने की कोशिश हो रही है कि कश्मीर का आतंकवाद स्थानीय रूप से पैदा हुआ है। यदि ऐसा है, तो यह पिछले 30 साल में पहली बार होगा कि कश्मीर-आतंकवाद को स्वदेशी बनाने के लिए जानबूझकर एक प्रयास किया गया है। यह लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तान स्थित उग्रवादी संगठनों के कश्मीर में कार्रवाई के कमजोर होने का नतीजा हो सकता है। पिछले साल के पुलवामा हमले, जिसका दावा जैश ने किया था और जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे; ने भारत और पाकिस्तान को लगभग युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा- 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) लश्कर का ही एक छद्म रूप है।

● **प्रवीण कुमार**

घुसपैठ और प्रशिक्षण का खेल

आतंकी हिंसा में ऐसे समय में फिर से तेजी आई है, जब आतंकवाद कमजोर होने के संकेत दे रहा था। पुलिस के अनुमान के अनुसार, कश्मीर में लगभग 250 सक्रिय आतंकवादी हैं, जिनमें से लगभग 50 इस साल जनवरी के बाद मारे गए हैं। इसके अलावा धारा-370 के निरस्त होने के कुछ महीनों बाद कश्मीरी युवाओं के हथियार उठाने के मामलों में गिरावट दिखाई दी थी। इससे आतंकवादियों की संख्या में कमी आने की संभावना थी। लेकिन सुरक्षा बलों की हाल की हत्याओं ने इन गणनाओं को गलत साबित किया है। इसने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। घुसपैठ एक निरंतर प्रक्रिया बनी हुई है, वह भी तब जब हाईटेक सीमा बाड़ लगाने की बातें की गई हैं। जो आतंकी सीमा पार कर रहे हैं, वे अत्यधिक प्रशिक्षित और युद्ध में निपुण हैं। यह इस तथ्य से जाहिर हो जाता है कि उन्होंने पांच पैराट्रूपर्स को भी मार दिया, जिन्होंने सितंबर, 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। यह चीजें यह दर्शाती हैं कि कश्मीरी युवा एक बार फिर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हथियारों के प्रशिक्षण के लिए सीमा पार कर रहे हैं। कुछ मामलों में युवाओं को वाघा सीमा से वैध वीजा पर पाकिस्तान का दौरा करने के लिए कहा जाता है। पिछले डेढ़ दशक में ऐसा नहीं था। युवा आतंकवाद से जुड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। लेकिन इन सशस्त्र युवाओं के पास यह ट्रेनिंग प्रतीकात्मक ही जाहिर होती है, क्योंकि अल्पकालिक प्रशिक्षण अक्सर एक के बाद एक होने वाली मुठभेड़ में उन्हें जान बचाना मुश्किल हो जाता है।

गेहूं उपार्जन में नंबर वन

मप्र में इस बार गेहूं खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड बना है। जितनी खरीदी प्रदेश में गेहूं की इस बार हुई इससे पहले इतनी कभी नहीं हुई थी। कोविड-19 आपदा की वजह से हुए लॉकडाउन में मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं ने वह कारनामा कर दिखाया है, जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस बार किसानों से एक करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश इससे पहले ही पंजाब को पछाड़ कर नंबर वन हो चुका है। ये काम आसान नहीं था, वो भी लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के इस दौर में। ये संभव हो पाया बेहतरीन मैनेजमेंट और किसानों की मेहनत के कारण। मप्र में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसकी सरकारी खरीदी किसी चुनौती से कम नहीं थी।

खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार जितना गेहूं खरीदा गया वो पिछले साल के मुकाबले 75 फीसदी से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं का खरीदा गया है जो पूरे देश का 33 प्रतिशत से ज्यादा है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 54 हजार मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीदी की गई। इस मामले में मप्र ने पंजाब को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। पिछले साल की तुलना में मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल मध्य प्रदेश में 73.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। मध्य प्रदेश में इस बार 15 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हुई थी जो 5 जून को खत्म हुई। गेहूं का ज्यादा उत्पादन होने के कारण इस बार खरीदी केंद्र भी 3 हजार 545 से बढ़ाकर 4 हजार 529 कर दी गई।

इस बार मप्र में गेहूं की बंपर पैदावार हुई थी लिहाजा **गेंहू खरीदना भी एक बड़ी चुनौती** थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी में मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी। 23 मार्च से अब तक लगातार 75 से ज्यादा बैठकें कर डालीं। मुख्यमंत्री ने हर रोज खरीदी की समीक्षा की। जबकि नंबर-1 आने पर मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है।

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भण्डारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देरी से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा उपार्जन कम अवधि में करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भण्डारण की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई।

सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा किसानों से कम अवधि में ज्यादा उपार्जन करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 3 हजार 545 को बढ़ाकर 4 हजार 529 केंद्र खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केंद्र पहुंचे। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर स्वयं एक-एक केंद्र पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सकें। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14 लाख 19 हजार किसानों के खातों में 20 हजार 253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान मिल सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई। जिससे कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40 प्रतिशत था जो बढ़कर इस बार 84 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है, जो गेहूं भंडारण के लिए शेष है, उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

● **लोकेश शर्मा**

लॉकडाउन में विशेष इंतजाम

प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस बार गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी ऐसे वक्त में शुरू की गई थी जब प्रदेश कोरोना महामारी की चपेट में था और देशभर में लॉकडाउन लागू था। सरकार ने किसानों के लिए ऐहतियात के तौर पर कुछ नियम जारी किए और केवल उन्हीं किसानों को खरीदी के लिए बुलाया गया जिन्हें मैसेज भेजे गए थे। एक बार में एक पाली में 10 से 12 किसानों को ही खरीदी के लिए बुलाया गया था। मंडी में सोशल डिस्टेंस और सैनेटाइजर की व्यवस्था की गई। किसानों को मंडी आने की जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए। राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिन में भेजी। पटेल ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि किसान के हर एक दाने को खरीदा जाए।

किसानों पर मंडराती आसमानी आफत

पिछले तीन दशकों में 1993 के बाद यह पहला मौका है जब टिड्डियों ने भारत के इतने बड़े हिस्से पर अपना कहर बरसाया है। 2019 में टिड्डियों ने करीब 200 से भी ज्यादा बार हमला किया है। आमतौर पर देश में औसतन टिड्डी दल 10 से कम बार हमले करता है। पर 2019 से लेकर अब तक उसके हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 2014 में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि इससे पहले 1993 में टिड्डी दल ने इतने बड़े पैमाने पर अपना आतंक फैलाया था। तब उनके हमलों की संख्या 172 आंकी गई थी। पाकिस्तान से हर वर्ष टिड्डी दल राजस्थान और गुजरात पहुंचता है।

पाकिस्तान से हर वर्ष टिड्डी दल राजस्थान और गुजरात पहुंचता है। आमतौर पर एक टिड्डी का जीवनकाल 90 दिन का होता है। यह जुलाई में आती हैं, अंडे देती हैं और अक्टूबर तक इनकी नई पीढ़ी पाकिस्तान-ईरान को रवाना हो जाती है। टिड्डियों के यह दल हरियाली का पीछा करते हैं और उन इलाकों पर हमला करते हैं, जहां मानसून को गुजरे ज्यादा वक्त न हुआ हो, क्योंकि इससे उन्हें आसानी से खाना मिल जाता है, जो कि उनके विकास और प्रजनन करने में मदद करता है। टिड्डियां कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। दुनिया में टिड्डियों की 10 प्रजातियां सक्रिय हैं, जिनमें से चार प्रजातियां समय-समय पर भारत में देखी गई हैं। इनमें से सबसे खतरनाक रेगिस्तानी टिड्डी होती है। इस बार जो प्रजाति सक्रिय है, वह भी रेगिस्तानी टिड्डियां हैं। एक व्यस्क टिड्डी की रफ्तार 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। टिड्डियों का एक झुंड कितना बड़ा हो सकता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक टिड्डी दल में 10 अरब तक टिड्डियां हो सकती हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैल जाती हैं। वो एक दिन में 200 किमी तक की दूरी तय कर सकती हैं और अपने सामने आने वाले हर पेड़-पौधे को चट कर जाती हैं। एफएओ के अनुमान के अनुसार रेगिस्तान टिड्डी किसी न किसी रूप में धरती के हर 10 में से एक इंसान की आजीविका को प्रभावित करती है। जो कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक प्रवासी कीट बना देता है।

ये टिड्डियां किस कदर नुकसानदायक हो सकती हैं, इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि इन टिड्डियों का एक छोटा दल, एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट या 2500 आदमियों के बराबर खाना खा सकता है। एक व्यस्क टिड्डी का वजन करीब 2 ग्राम होता है। जो कि हर रोज अपने वजन के बराबर ही फसलों को खा सकती है। जबकि एक वर्ग किलोमीटर में फैला टिड्डी दल करीब 35 हजार लोगों के खाने के बराबर फसलों और पौधों को चट कर सकता है। भारत में अब तक टिड्डी दल उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश में भी इनके हमलों के समाचार सामने आ रहे हैं। जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों पर भी इनके संभावित हमले की आशंका जताई जा रही है। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी इन रेगिस्तानी टिड्डियों ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। जो ईरान से होती हुई पाकिस्तान पहुंची हैं। अनुमान है कि पाकिस्तान के सभी प्रांतों में 60 से अधिक जिलों में इन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

भारत के लिए एक और परेशानी की वजह यह है कि केन्या से आने वाले टिड्डी दलों के कारण भारत को दूसरा बड़ा हमला झेलना पड़ सकता है। आमतौर पर, जून के मध्य में केन्या से टिड्डियां चलती हैं जो पाकिस्तान और ईरान होते हुए भारत पहुंचती हैं। एफएओ ने अपने 21 मई को जारी बुलेटिन में बताया है कि ईरान और दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान में टिड्डियों का वसंत प्रजनन जारी है। जो कि जुलाई के आस पास भारत-पाकिस्तान सीमा पर दोबारा से पहुंच जाएंगी। एलडब्ल्यूओ द्वारा टिड्डी नियंत्रण एवं शोध विषय पर जारी एक डॉक्यूमेंट बताता है कि दुनिया में टिड्डियों की 10 प्रजातियां सक्रिय हैं, इनमें से चार प्रजातियां भारत में समय-समय पर देखी गई हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

देश में क्यों बढ़ रहे हैं टिड्डियों के हमले

खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर टिड्डियों पर निगरानी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रेसमेन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत-पाकिस्तान में हवा के स्वरूप में बदलाव आ रहा है तथा हिन्द महासागर में बार-बार आने वाले चक्रवातों की वजह से टिड्डियों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। चक्रवात से तटीय गुजरात, अरब प्रायद्वीप, सोमालिया और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बारिश हुई है। इससे टिड्डियों प्रजनन की अच्छी दशाएं बनती हैं। इतिहास बताता है कि ये प्लेग चक्रवाती हवाओं से फैलते हैं। जिससे भारत में भी इनके हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना (एलडब्ल्यूओ) 1946 में की गई थी। संगठन का अनुमान है कि 1926 से 1931 के बीच टिड्डियों के हमले से लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 100 साल के दौरान सबसे अधिक है। इसी तरह 1940-46 और 1949-55 के दौरान दो बार टिड्डियों का हमला हुआ और दोनों बार लगभग दो-दो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1959-62 के चक्र में केवल 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसके बाद 1978 और 1993 में टिड्डियों का हमला हुआ और 1993 में लगभग 75 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया।

लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से लाल आतंक एक्टिव हो गया है। प्रदेश के बालाघाट सहित नक्सल प्रभावित सभी जिलों में माओवादियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले एक माह में प्रदेश में पुलिस और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ हो चुकी हैं। जिसमें पुलिस को हथियार, नक्सल साहित्य आदि मिले हैं।

लाल आतंक एक्टिव

भारत में लाल आंतक की वजह से चर्चित दंडकारण्य के सबसे सुरक्षित क्षेत्र बालाघाट में इन दिनों नक्सली काफी सक्रिय हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां नक्सली भी अपने-अपने क्षेत्रों में लॉक थे, वहीं लॉकडाउन खत्म होते ही इनकी सक्रियता बढ़ गई है। बालाघाट सहित मप्र के नक्सल प्रभावित सभी क्षेत्रों में नक्सलियों की सक्रियता देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नक्सली बालाघाट को आधार मुख्यालय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका संकेत इससे भी मिल रहा है कि बालाघाट सहित पूरे दंडकारण्य इलाके में नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।

नक्सली बालाघाट को मुख्यालय क्यों बनाना चाहते हैं, इस संदर्भ में पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार दंडकारण्य इलाके में बालाघाट के जंगलों को नक्सली अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मान रहे हैं। वह कहते हैं कि दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश राज्यों के हिस्से सहित मप्र का बालाघाट भी शामिल है। बालाघाट का क्षेत्रफल 9,245 वर्ग किमी है। इसका वन क्षेत्र अभी भी सघन है और पुलिस की सक्रियता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है।

टाइल्स कारखानों और चावल मिलों के लिए प्रसिद्ध बालाघाट भौगोलिक नजरिए से नक्सलियों के लिए शुरू से अहम रहा है। माओवादियों के पृथक दंडकारण्य के नक्शे के लिहाज से देखें तो बालाघाट रेड कारपेट कॉरीडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जिला महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित जिले गढ़चिरौली और चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बीच गलियारा कहा जा सकता है। बस्तर और राजनांदगांव के नक्सली दलम और महाराष्ट्र के नक्सली टोलियों की महत्वपूर्ण बैठकें भी बालाघाट में होती रही हैं। तेलंगाना में कमजोर हो चुके माओवाद की भरपाई वे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से लेकर गुजरात के मुहाने तक सटे बड़वानी जिले तक नक्सलवाद के विस्तार की उनकी योजना है। नर्मदा नदी से सटे जंगलों में अपना साम्राज्य कायम करने की उनकी पुरानी हसरत है।

सूत्रों के अनुसार, नक्सली देश में बड़ी वारदात करने की तैयारी में हैं। इसके लिए ओडिशा और आंध्रप्रदेश के रास्ते उनके पास गोला-बारूद पहुंच रहा है। खास बात यह है कि पिछले कुछ माह में नक्सलियों ने सबसे अधिक सक्रियता बालाघाट सहित मप्र के नक्सल प्रभावित जिलों में बढ़ाई है। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच पिछले दो माह में कई मुठभेड़ हो चुकी है। 7 जून को मंडला जिले के जंगल में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मंडला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला कहते हैं कि मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति देखी जाती रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना क्षेत्र के एंटी नक्सल बल हॉकफोर्स के द्वारा नक्सलियों की तलाश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों का लगातार दो दिन तक आमना-सामना हुआ। 7 जून को तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और गोलियां भी चलीं। लेकिन नक्सली मौके का फायदा उठाते हुए जंगल के बीच सामान छोड़कर भाग गए। नक्सलियों की संख्या 3 थी। छत्तीसगढ़ सीमा से लगते हुए खुजराही और नेवसा के बीच जंगल में नक्सली थे।

हाल के दिनों में दंतेवाड़ा में फोर्स ने रिमोट आधारित लैंडमाइन बरामद की थी। इससे पहले भी उनके पास से अति आधुनिक हथियार मिल चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले कांकेर पुलिस ने नक्सलियों के 11 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि उच्चाधिकारियों की मानें तो हथियारों के मामले में उनकी मुख्य ताकत मुठभेड़ के बाद जवानों से लूटे हथियार ही हैं। उधर, कोरोना के खिलाफ जंग को कामयाब बनाने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण नक्सलियों की भी कमर टूटने लगी है। मप्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों से मिल रही खबरों के मुताबिक लॉकडाउन का नक्सलियों पर व्यापक असर दिख रहा है।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

बड़ी वारदात कर सकते हैं नक्सली

मप्र इंटेलीजेंस को इनपुट मिले हैं कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने मप्र का रुख किया है। नक्सली मप्र में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए बालाघाट सहित प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सूत्र बताते हैं कि 17 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा के चिंतलनार, 28 अप्रैल को मप्र के बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के सीमावर्ती गांव मोहन खोदरा और 2 मई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि माओवादियों ने वनोपज और तेंदूपत्ता से करोड़ों रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वन क्षेत्र का बंटवारा कर लिया है। मप्र का तेंदूपत्ता सबसे अच्छा रहता है। इस बार भी नक्सली तेंदूपत्ता वाले वन क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इंटेलीजेंस के सूत्रों के अनुसार, नक्सलियों की सक्रियता की खबर मिलते ही बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में पुलिस का सतर्क कर दिया गया है। ऑपरेशन से जुड़े अफसरों ने बताया कि फोर्स के दबाव में पिछले काफी समय से बैकफुट पर चल रहे माओवादी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते रही-सही कसर पूरी हो गई है। कोरोना वायरस के चलते उनके पास खाने तक का सामान नहीं है।

खतरे में बब्बर शेर

एशियाई शेरों के लिए ख्यात गुजरात के गिर अभयारण्य में शेरों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी तेजी से उनकी मौत भी हो रही है। इसलिए वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने मप्र के कूनो पालपुर में इन शेरों को बसाने की मांग एक बार फिर तेज कर दी है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बब्बर शेरों की प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 जून को एशियाई शेरों की आबादी (2015 और 2020 के बीच 151) में 29 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि का जश्न मना रहे थे, तब ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी से लेकर अब तक गुजरात के गिर लॉयन लैंडस्केप (जीएलएल) में 92 एशियाई शेरों की मौत हो चुकी है।

गौरतलब है कि गिर के एशियाई शेरों को मप्र के कूनो पालपुर में बसाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में गुजरात सरकार को पहल करने का निर्देश दिया है। वहीं मप्र सरकार ने इसके लिए कूनो पालपुर अभयारण्य को तैयार कर लिया है, लेकिन केंद्र और गुजरात सरकार की निष्क्रियता के कारण शेरों का विस्थापन नहीं हो पा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गिर अभयारण्य में शेरों की आबादी बढ़ने के कारण वे आपस में लड़ रहे हैं या फिर बीमार होकर मौत के घाट उतर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ शेर आपस में लड़ कर मर गए और कई कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) की वजह से मर गए। मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र जिनके पास रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि जसधर रेसक्यू सेंटर में समिति को दो शेर दिखाए गए, जो सीडीवी से पीड़ित थे। 92 में से 36 शेरों की मौत मई में हुई, जबकि अप्रैल में 24, मार्च में 10, फरवरी में 12 और जनवरी में 10 शेरों की मौत हुई थी। मरने वालों में 19 शेर, 25 शेरनियां, 42 शावक और 6 अज्ञात शेर शामिल हैं। इनमें से सबसे अधिक 59 शेरों की मौत गिर के ईस्ट डिवीजन, धारी में हुई, जहां 2018 में सीडीवी का प्रकोप हुआ था।

दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2018 में जब सीडीवी का प्रकोप हुआ था, उस महीने 26 शेरों की मौत हुई थी, जबकि मई में उससे अधिक शेरों की मौत हुई। एशियाई शेरों के विशेषज्ञ एवं भारतीय जैवविविधता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के आंकड़े उपलब्ध कराने वाली गैर लाभकारी संस्था मेटास्ट्रींग फाउंडेशन के सीईओ रवि चेल्लम के अनुसार, गिर लॉयन लैंडस्कैप में शेरों की मृत्यु दर का कोई बेसलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है। मार्च 2018 में गुजरात सरकार ने कहा था कि दो साल में 184 शेरों की मौत हो गई। इस बार पांच महीनों में 92 की मौत हुई है, जबकि 60 की मौत सिर्फ अप्रैल और मई में हुई है। हालांकि, गुजरात वन विभाग ने सीडीवी की उपस्थिति से इनकार किया है। जूनागढ़ वन्यजीव सर्कल के मुख्य वन संरक्षक डीटी वासवदा ने कहा कि गिर में यहां कोई सीडीवी नहीं है। हमने अप्रैल में बेबेसिया और सीडीवी के लिए बड़ी संख्या में नमूनों का परीक्षण करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि सीडीवी का मुद्दा गुजरात सरकार के खिलाफ मीडिया द्वारा उछाला गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

मंत्रालय ने 29 मई को एक समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहायक महानिरीक्षक, मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग के संयुक्त निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के एक पशु चिकित्सक शामिल है। मंत्रालय ने समिति के गठन के साथ ही कहा था कि समिति को जून के पहले सप्ताह में ही क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और शेरों की मौत के संयोग, मृत्यु का कारण पता करना चाहिए। साथ ही, यह भी पता करना चाहिए कि शेरों की मौत को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए। गुजरात के वन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि गिर में शेरों की मौतों की खबर से ध्यान हटाने के लिए एशियाई शेरों के आंकड़ों का प्रचार किया जा रहा है। शेरों की मौत की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट सरकार के पास थी, लेकिन इससे ध्यान हटाने के लिए 5-6 जून को लगाए गए अनुमान को बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं कि जो अनुमानित आंकड़ा अभी बताया जा रहा है, वो नियमित प्रक्रिया है।

● **राजेश बोरकर**

विस्थापन की प्रक्रिया शुरू

गुजरात गिर के बब्बर शेरों का कूनो नेशनल पार्क को दूसरा घर बसाने के लिए 24 साल पहले विस्थापित किए जा चुके 24 गांवों के बाद अब 25वें गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि ढाई दशक बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहां बब्बर शेर नहीं आ पाए हैं, लेकिन अब बागचा गांव को विस्थापित किया जाएगा। जिसके लिए जिला प्रशासन की बैठक भी हो चुकी है और अब गांव के परिवारों के सत्यापन के लिए राजस्व और वन विभाग संयुक्त दल भी गठित कर दिए गए हैं। हालांकि दोनों विभागों के संयुक्त दल के सत्यापन रिपोर्ट के बाद ही विस्थापित परिवारों की अंतिम सूची तय होगी, लेकिन प्रारंभिक रूप से पूर्व में बागचा के 265 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया था। बताया गया है कि बागचा गांव के विस्थापन पर साढ़े 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उल्लेखनीय है कि तीन दशक पहले संरक्षित किए गए कूनो अभयारण्य का दायरा 352 वर्ग किमी का था, जिसे बढ़ाकर डेढ़ साल पहले 748 वर्ग किमी किया गया, साथ ही नेशनल पार्क का दर्जा भी दे दिया गया। यही वजह है कि रकबा बढ़ाने के कारण पहले बफर जोन में शामिल बागचा गांव अब नेशनल पार्क में आ गया, लिहाजा कूनो वनमंडल ने तत्समय से ही बागचा को विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिसे शासन ने मंजूरी दे दी। यही वजह है कि अब विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले दिनों कलेक्टर श्योपुर की अध्यक्षता में विस्थापन संबंधी बैठक आयोजित की गई थी।

देश के सबसे बदहाल क्षेत्र में से एक बुंदेलखंड में बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन तो परंपरागत समस्या है। इस लॉकडाउन में करीब 9 लाख लोग बुंदेलखंड के 13 जिलों में वापस लौटे हैं। इन लोगों के सामने अब रोजी-रोटी की समस्या खड़ी है।

लोकल बनेगा वोकल

बुंदेलखंड की बंजर जमीन हमेशा से यहां के लोगों के लिए अभिशाप रही है। लेकिन इस बार लॉकडाउन ने क्षेत्र में स्वरोजगार और रोजगार की संभावनाओं को जन्म दिया है। हालांकि अभी पलायन कर यहां पहुंचे लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है लेकिन जल्द ही इस बंजर जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लोकल बनेगा वोकल' का नारा साकार होने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में सेना के लिए रक्षा उत्पाद बनाने वाली कई कंपनियां यहां अपनी इकाइयां लगाने जा रही हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग, आयुर्वेद व सोलर एनर्जी से जुड़ीं देशी कंपनियां भी बुंदेलखंड की ओर रुख करने की तैयारी कर रही हैं। उद्योग विभाग के अनुसार आगामी एक साल के भीतर प्रधानमंत्री के नारे का असर बुंदेलखंड में नजर आने लगेगा।

मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को विकास की रफ्तार देने वाले बुंदेलखंड के श्रमिक अब अपने क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। यहां की बंजर जमीनें क्षेत्र के विकास को नया आयाम देंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लोकल बनेगा वोकल का नारा बुंदेलखंड की धरती पर बुलंद होगा। हालांकि, इसका खाका क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की नींव पड़ने के साथ ही तैयार होने लगा था। देश की प्रमुख कारतूस बनाने वाली कंपनी स्टंप्स श्यूले एंड सोंप्पा लिमिटेड का झांसी में इकाई स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार से करार हो चुका है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी पतंजलि भी यहां सौ एकड़ में अपनी इकाई स्थापित करने जा रही है। जमीन लेने के साथ कंपनी की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। बुंदेलखंड को दलहन और तिलहन का हब माना जाता है। यही वजह है कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कई उद्यम यहां शुरू होने जा रहे हैं। ललितपुर रोड पर एक ही परिसर में लगभग चालीस इकाइयां शुरू होने जा रही हैं।

झांसी में जल्द ही ड्रोन कैमरों का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए एक भारतीय कंपनी ने उद्योग विभाग से संपर्क साधा है। विभाग से कंपनी ने जमीन मांगी है। जमीन की उपलब्धता होने पर कंपनी यहां अपने इकाई स्थापित करेगी। कंपनी की ओर से जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। ये जमीन उद्योग विभाग के माध्यम से ली जाएगी। इस इकाई के लग जाने से यहां कुशल-अकुशल तकरीबन 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह मप्र के 6 जिलों में भी रोजगार मूलक गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि मप्र सरकार की मंशा है कि इस वित्तीय वर्ष में बुंदेलखंड में कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे यहां के लोगों का पलायन रुके। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बुंदेलखंड अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। यहां का वातावरण सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए एकदम अनुकूल माना जाता है। यहां पहले से ही देश के प्रतिष्ठित अडाणी ग्रुप की इकाई स्थापित है। अब टेहरी की एक कंपनी से भी यहां 250 मेगावाट उत्पाद की क्षमता के सोलर पावर प्लांट के लिए करार हुआ है। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लोकल बनेगा वोकल के नारे की झलक बुंदेलखंड में एक साल के भीतर नजर आने लगेगी। डिफेंस कॉरिडोर में कई भारतीय कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करने जा रही हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग व आयुर्वेद के क्षेत्र में भी देशी कंपनियां यहां आ रही हैं। यहां जमीन और श्रमिकों की सुगमता से उपलब्धता उद्यमियों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। सोलर एनर्जी क्षेत्र में भी यहां बड़ी इकाई लगने वाली है।

लॉकडाउन के चलते चार राज्यों से बुंदेलखंड के 9 लाख मजदूर घर वापसी कर चुके हैं। वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में छोटे कारखानों से लेकर बड़े उद्योग इनकी मेहनत के बूते पर संचालित होते हैं, लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है कि मजदूरों के वापस लौटने के बाद यह उद्योग कैसे शुरू होंगे। वैसे भी कोरोना महामारी के दौरान भारी पीड़ा झेलने के बाद अब मजदूर दोबारा शहर जाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और मप्र की सरकारें इनके लिए यहीं पर रोजगार की व्यवस्था करने जा रही हैं।

● राकेश ग्रोवर

बाहर से लौटे मजदूरों को दिया जा रहा है काम

फिलहाल जो मजदूर बाहर से लौटे हैं उन्हें मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बुंदेलखंड के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों और शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो इनकी संख्या बहुतायत है। लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी वापस लौट आए हैं। एक बड़ी संख्या तो ऐसे मजदूरों की है जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके पहुंचे हैं। टीकमगढ़ निवासी नरेंद्र, प्रेमपाल और अनुज ने बताया कि वह 200 साथियों के साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वापस लौटे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ही 200 से ज्यादा फैक्टरी ऐसी हैं जहां बुंदेलखंड के लोग काम कर रहे थे, मगर सभी वापस लौट आए हैं। छतरपुर निवासी अनिल, कुमार और संजय ने बताया कि फिलहाल वह लोग वापस परदेस नहीं लौटेंगे। जब हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे तब विचार किया जाएगा। गुजरात से लौटे दतिया निवासी अमित कुमार ने बताया कि स्टील कारखानों में वो लोग काम करते थे। कारखाने बंद हो गए तो वो लोग आ गए। निवाड़ी के राजेंद्र ने बताया कि उनके जिले से ही करीब 2000 मजदूर गुजरात में थे, लेकिन सभी आ गए हैं। श्रमिक ठेकेदार हरगोपाल का कहना है कि कुछ जगहों से तो फोन भी आने लगे हैं कि फैक्ट्री शुरू करनी है श्रमिकों को लेकर आ जाओ। लेकिन यह लोग जाएंगे कैसे।

महामारी बनी महात्रासदी

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20

भारत सहित पूरे विश्व में भूकंप, सूनामी, बाढ़, चक्रवात सहित तमाम तरह की आपदाएं आईं लेकिन गरीबों की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई, जैसी कोरोना संक्रमण के दौरान देखने को मिली है। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान के अपने ज्ञान पर गुमान करने वाले देश अभी तक कोरोना वायरस के इलाज का न तो वैक्सीन इजाद कर पाए और न ही कोई दवा बना पाए। भारत में तो यह महामारी करोड़ों लोगों के लिए महात्रासदी बन गई है।

● राजेंद्र आगाल

कोरोनावायरस संक्रमण के मामले में भारत अब अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हमेशा तर्क दे सकते हैं कि जब दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन (जिनके पास यकीनन सबसे अच्छा मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्टर और रिसर्च है) वैश्विक महामारी के प्रकोप से नहीं बच पाए, तो मोदी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन, मोदी का लॉकडाउन (जो देश में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र का एक प्रमुख हथियार था) दुनिया के सबसे सख्त शटडाउंस में से एक था, जिसमें 100 प्रतिशत कड़ाई बरती गई, जो सबसे ऊंची थी। और फिर भी, हमारा देश कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों का दबाव झेल रहा है, जो अब 3 लाख के पार हो गए हैं। जाहिर है कि जल्दबाजी में लॉकडाउन घोषित करने के बाद से मोदी सरकार ने बहुत सारी गलतियां की हैं, जिसके कारण महामारी महात्रासदी बन गई।

गलत आंकलन का परिणाम

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक हो जाने के साथ ही जिस तरह संक्रमण की रफ्तार तेज होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यह साफ है कि इस खतरनाक वायरस से उपजी महामारी से फिलहाल छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन सरकार की कुछ गलतियों के कारण इसका फैलाव लगातार बढ़ रहा है। दरअसल, नीति आयोग के सदस्य, और कोविड पर मोदी सरकार को सलाह देने के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स के अध्यक्ष, विनोद पॉल ने 24 अप्रैल को एक प्रेस ब्रीफिंग में, एक गणित का मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने बहुत विश्वास के साथ दावा किया कि 16 मई के बाद से भारत में कोरोनावायरस के कोई नए मामले नहीं होंगे। और हममें से अधिकतर ने उनका यकीन कर लिया। तब तक, जब हम 16 मई तक पहुंचे और देखा कि हम तूफान के केंद्र में थे। लगता है कि सरकार की टास्क फोर्स की बागडोर, आंकड़ों के भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के नहीं, बल्कि उपन्यासकारों के हाथ में है। बल्कि इस टास्क फोर्स के महामारी वैज्ञानिकों ने गुमनाम तरीके से इस बात की गवाही दी कि कोरोनावायरस और उससे निपटने के उपायों पर, सरकार ने शायद ही उनसे कभी सलाह ली होगी। वैज्ञानिकों के उपायों में एक था आक्रामक तरीके से टेस्टिंग और ट्रेसिंग। नरेंद्र मोदी ने बार-बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो एक चीज नहीं कर पाए, जो भारत को इसके प्रकोप से बचा सकती थी, और वो थी टेस्टिंग। लॉकडाउन का इस्तेमाल करके टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाने की बजाय, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को केवल इसलिए संबोधित किया कि मोर्चे पर डटे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए या तो देशवासी तालियां बजाएं या महामारी से छाए अंधेरे को दूर करने के लिए कैंडल्स जलाएं। भारत को उत्साह बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। उसे ठोस नीतियां चाहिए थीं।

अवैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा

दरअसल, प्रधानमंत्री के इन चीजों पर जोर देने से सिर्फ अवैज्ञानिक प्रवृत्ति को ही बढ़ावा मिला। ये उन व्हाट्सएप फॉर्वर्ड्स से भी जाहिर था, जिन्होंने ऐसे-ऐसे दावों के साथ अंधविश्वास और मिथ्या को बढ़ावा दिया, कि एक खास समय पर कैंडल जलाने या थाली बजाने से, वायरस को मारा जा सकता है। दरअसल मोदी ने 'गैर-जिम्मेदाराना' बयान जारी किए, जिनमें राष्ट्र से कहा गया कि 21 दिन की इस लड़ाई में, कोरोनावायरस को उसी तरह परास्त करें, जैसे 18 दिन में महाभारत युद्ध जीता गया था। देश को 21 दिन के लॉकडाउन के जरिए महामारी से बचने के लिए झूठे वादों की जरूरत नहीं थी। भारतीयों को जरूरत थी वास्तविकता से रूबरू होने की। लोगों को जरूरत थी कि प्रधानमंत्री हफ्ते में नहीं, तो कम से कम एक पखवाड़े में उनसे मुखातिब हों, ताकि वो अगले कुछ महीनों के लिए तैयारी कर सकें, अपने संसाधन बचाकर रखें, सतर्क बने रहें और कोविड के मरीजों को कलंकित न करें लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किसी की परवाह नहीं की। वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस लंबे और बिना सोचे-समझे लॉकडाउन ने, देश को सीधे-सीधे एक आर्थिक समस्या में धकेल दिया है और बीमारी तथा पैसे की तंगी दोनों के हिसाब से सबसे बुरी तरह गरीब लोग ही प्रभावित हुए हैं। भारत में जो मजदूर संकट सामने आया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके ऊपर हो रही सियासत भी घिनौनी रही है। गरीबों की मुसीबतों पर देर से जागना और उनका असहयोग प्रधानमंत्री मोदी का एक अंदाज रहा। नोटबंदी से पैदा हुई अव्यवस्था के दौरान, नरेंद्र मोदी की खामोशी की मिसाल देते हुए उनके आलोचक इसकी अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके समर्थकों ने मजदूरों के इस संकट को, अपरिहार्य बताकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि लॉकडाउन के खराब ढंग से अमल में लाने से, लोगों की मौतें हुई हैं और इसे महामारी के दौरान, अनिवार्य **कोलेटरल डैमेज बताकर** खारिज नहीं किया जा सकता। कोविड के खिलाफ लड़ाई में, भारत के अलावा किसी भी देश में, इतने बड़े पैमाने पर गरीबों को, भूख या साधनों की कमी से मरते नहीं देखा गया। भारत अपने गरीबों को किसी सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे रहा है और इसके लिए किसे जिम्मेदार होना चाहिए? खुद पीड़ितों मोदी समर्थक आपको यकीन दिला देंगे कि ये गरीबों की ही गलती थी, जो घर लौटने की कोशिश में मारे गए। वो अपेक्षा करते हैं कि गरीब लोग जहां पर हैं, वहीं जमे रहें, भले ही उन्हें किराए की उनकी झोपड़ियों से निकाल दिया गया हो, या उनके पास खाने को कुछ ना हो। ऐसे समय में पीड़ितों को ही बड़े पैमाने पर शर्मसार किया जाना, एक शैतानी हरकत थी।

इस रात की सुबह कब?

हर देश अपने तरीके से कोविड-19 से लड़ रहा है, लेकिन उनकी सफलता का पैमाना अलग-अलग है। दक्षिण कोरिया ने भले इस पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन इटली जैसे देशों में उच्च मृत्यु दर देखी जा रही है। कोई भी देश यह नहीं कह पा रहा है कि यह महामारी कब खत्म होगी। अधिकांश देश लंबे समय तक नए केस आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सामाजिक दूरी जैसे तरीकों का उपयोग करके मामलों की संख्या कम कर रहे हैं। यह स्वास्थ्य प्रणाली को अत्यधिक बोझ से बचाने में मदद करती है, लेकिन लंबे समय में मामलों को फैलाता भी है। एक और तरीका है, सामूहिक प्रतिरक्षा को बढ़ाना। इसमें वायरस को अपने प्राकृतिक तरीके से फैलने दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित होकर वायरस के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लें। लेकिन, ये तरीका भयावह है और इसे खारिज कर दिया गया है। ये ज्यादातर तब अपनाया जाता है जब बीमारी से बचाव के लिए कोई टीका होता है। लेकिन, कोविड-19 का टीका न होने के कारण, यह समस्या न केवल स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ डाल सकती है, बल्कि मृत्यु दर भी बढ़ा सकती है।

पैकेज का जादुई आंकड़ा

आज की एकमात्र पीआर रणनीति है आत्मनिर्भर भारत की शब्दों की पहेली। लेकिन पहले से ही रेंग रहे व्यवसाइयों से कहना कि वो उठ खड़े हों और मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से लोन लेकर अपने

धंधे फिर से चालू करें, ना सिर्फ एक छल है बल्कि उदासीनता से भी भरा है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2020 में भारत में 12.2 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार गंवाए, जिनमें से अधिकतर मजदूर और छोटे व्यवसायी थे। और अगर आमतौर पर ये माना जाता है कि सिर्फ गरीब लोग प्रभावित हैं, तो ये दोहराया जाना चाहिए कि सीएमआईई के अनुमान के मुताबिक अप्रैल 2020 में 1.8 करोड़ कारोबारी लोग भी अपने धंधे से बाहर हो गए। असल में इस महामारी में आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं हुई हैं, जिनमें से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली बहुत सी महिलाएं अब बेरोजगार हैं। इसके अतिरिक्त, 23.3 प्रतिशत पुरुष और 26.3 प्रतिशत महिला कर्मचारियों ने अपने जॉब गंवा दिए हैं, खासकर अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां फैक्ट्रियां और औद्योगिक जोन्स स्थित हैं। आंकड़े बताते हैं कि 46 प्रतिशत महिलाओं ने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट दिए थे।

सरकारी दावे निकले झूठे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 4 घंटे के नोटिस में पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस कारण जो जहां थे वहीं थम गए। लॉकडाउन के कारण जिस तबके को सबसे बड़ी समस्या झेलनी पड़ी, वह प्रवासी मजदूर तबका था जो अपने गृहराज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में गया था। जाहिर सी बात है, कोरोना के डर से ज्यादा देश के गरीबों को भूख से मरने का डर था। यही कारण था कि प्रवासी मजदूरों ने पहले ही लॉकडाउन को तोड़ते हुए तीसरे दिन से ही चहलकदमी शुरू कर दी थी। हजारों की संख्या में मजदूरों ने पैदल ही अपने घरों के लिए सैकड़ों किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी शुरू की। इस दौरान कई मजदूरों और उनके छोटे-छोटे बच्चों ने भूख और थकान के कारण अपनी जान भी गंवाई। कईयों की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। दुधमुहे बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक, जवान मजदूरों से लेकर बुजुर्गों तक ने भूख और सरकार पर अति अविश्वास के कारण यह यात्रा शुरू की।

जब सरकार ने इन मजदूरों को डंडे के जोर पर रोकने की कोशिश की तो कहीं-कहीं मजदूर और पुलिस के बीच टसल की खबरें भी आईं। पिटते, मार खाते जैसे-तैसे इनकी स्वकार्यवाहियों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और लॉकडाउन के ठीक 37 दिन बाद प्रवासी मजदूरों के लिए यातायात के लिए श्रमिक ट्रेन की व्यवस्था करनी पड़ी। जिसे लेकर कहा गया कि मजदूरों को ट्रेन से मुफ्त उनके गृह राज्य पहुंचाया जाएगा। जिसे लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें किराए को लेकर आए दिन अपना-अपना हिसाब समझाने में लगी रहती थी। उस समय भारतीय लोग समझ तो रहे थे कि सरकार मजदूरों से किराया वसूल रही है, लेकिन सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही होती थीं। जिस कारण कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही, लेकिन अब धीरे-धीरे सरकार के लॉकडाउन का हिसाब सामने आ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने देरी की

स्वान के सर्वे में कहा गया कि 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की यात्रा के खर्चे को लेकर निर्देश दिया था जो काफी देर में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को कहा था कि राज्य सरकारें मजदूरों के घरवापसी की यात्रा का खर्च उठाएगी। यह निर्देश श्रमिक ट्रेन खुलने के 28 दिन बाद और लॉकडाउन लगने के 65 दिन बाद लिया गया। इस पर यह समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी मात्र औपचारिक तौर पर दिया। जाहिर है, इतनी देर में अधिकतम जाने वाले मजदूर अपने गृह राज्य की तरफ निकल चुके थे। या तो वह पैदल अपने घर चले गए थे या रेल, बस व अन्य माध्यमों से खर्चा करके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सिर्फ खुद के दामन को साफ करने के लिए दिया, ताकि आगे उनके ऊपर उंगली न उठ सके। यह सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्त होने पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों के किराया में देरी से निर्देश ही नहीं, बल्कि देश में जब सबसे नीचे गरीब मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पर हमला हो रहा था, पुलिस लाठियों-डंडों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में मूक बनकर देखती रही।

मप्र में सिर्फ 1220 आईसीयू

मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व चिकित्सा विज्ञानियों ने भी अनुमान लगाया है कि कोरोना का संक्रमण जून-जुलाई में सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से मरीज बढ़ते रहे तो राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में गंभीर मरीजों के इलाज में मुश्किल आ सकती है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ की आबादी के लिए अस्पतालों के आईसीयू में सिर्फ 1220 बिस्तर ही उपलब्ध हैं। इसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पताल शामिल हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार 1189 बिस्तर आईसीयू में और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऑक्सीजन वाले साधारण बेड 12 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किए जाएंगे। मरीज अचानक बढ़े तो गंभीर मरीजों के इलाज में मुश्किल आएगी। राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 15 मई को प्रदेश में कुल संक्रमित 4595 थे। इनमें 2073 इलाजरत (एक्टिव मरीज) थे। 14 जून की स्थिति में 10802 संक्रमित हो चुके हैं, इनमें इलाजरत मरीजों की संख्या 2666 हो गई है। यानी 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। भोपाल में इलाजरत मरीज 15 मई को 336 थे जो 14 जून को 733 हो गए। यानी 118 फीसदी बढ़ोतरी हुई। इंदौर में मरीजों की संख्या कम होने लगी है, पर भोपाल में हर दिन 50 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इसके बाद भी यहां चिरायु मेडिकल कॉलेज (निजी), एम्स और हमीदिया अस्पताल में मिलाकर सिर्फ 156 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। प्रदेश की 22 लैब में अभी हर दिन करीब 6 हजार सैंपलों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई तक 10 हजार सैंपल की जांच रोजाना करने को कहा है। इसके लिए सभी लैब की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सैंपल से आरएनए अलग करने के लिए स्वचलित मशीनें लगाई जा रही हैं। अभी 6 हजार सैंपलों की जांच में 150 से 200 मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। जांच बढ़ने पर रोजाना यह आंकड़ा 250 से 300 के बीच पहुंच सकता है।

झूठे वादों की कलह खुली

इस रिपोर्ट के अनुसार यह समझ आता है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें मजदूरों को लेकर सिर्फ राजनीति करती रहीं। पहले से ही बेहाल मजदूरों को और परेशान किया गया। फटेहाल मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूला गया और मीडिया में आकर सरकारें मजदूरों को लेकर झूठे दावे ठोंकती रहीं। जबकि हकीकत उलट है। पहले तो मजदूरों को लंबे समय तक जबरन डंडे के दम पर भूखे, प्यासे रोका गया। 37 दिन बाद ट्रेन व्यवस्था खोली भी गई, तो इसे मजदूरों के लिए इतना जटिल और खर्चीला बनाया गया कि उनके लिए 'कंगाली में आटा गीला' वाली बात हो गई। अधिकतम मजदूर, जिन्हें श्रमिक ट्रेन के लिए आवेदन करना नहीं आता था, उन्हें अपने ठेकेदार या जानकार से पैसे देकर आवेदन करवाना पड़ा। उसके बाद जैसे-तैसे उनमें से सक्षम मजदूर ट्रेन तक पहुंचने में कामयाब भी हुए तो उनसे किराया वसूल किया जाने लगा।

मजदूरों के किराया देने की स्थिति के बाद भी उन्हें ट्रेन में भोजन, पानी की आधारभूत सुविधाओं से वंचित किया गया। कई मजदूरों ने रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन में बासी (खराब) खाना दिए जाने की शिकायत भी की। वहीं कई ट्रेनें अपने रास्तों से भटकती भी पाई गईं। जिसके भीतर भूख और प्यास से मजदूरों के मरने की खबर भी आई। सरकार ने देश के गरीबों को बुरे समय में उनके हाल पर यूं ही मरने के लिए छोड़ा। बचीखुची पाईपाई तक उनसे ली। सरकार ने ट्रेन व्यवस्था शुरू करते हुए कहा था कि मजदूरों से किसी प्रकार का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन मजदूरों के हाथो में रेल की टिकटें और स्वान की रिपोर्ट ने यह दिखा दिया है कि सरकार के ये सारे दावे फर्जी साबित हुए।

निजी अस्पतालों में महंगा पड़ रहा कोरोना का इलाज

कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुल्क तय नहीं करने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। निजी अस्पताल अपने हिसाब से शुल्क तय कर रहे हैं। इसकी वजह से कई मरीज यहां इलाज से वंचित हो रहे हैं। निजी अस्पतालों का कहना है कि कोरोना के मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था की लागत बहुत अधिक है। इसकी वजह से शुल्क भी अधिक हैं। पूर्वी दिल्ली में निजी अस्पतालों में सबसे बड़े पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में जनरल वार्ड के लिए प्रतिदिन का शुल्क 25 हजार रुपए रखा गया है। इसके अलावा महंगी दवा, जांच आदि का शुल्क अलग से देना होगा। इसका शुल्क औसतन 10 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन पड़ सकता है। अगर मरीज को कमरा चाहिए तो उसके लिए 30,490 रुपए देने होंगे। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का शुल्क 53,050 रुपए रखा गया है। इसी तरह अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो मरीज को 72,550 रुपए प्रतिदिन देने होंगे। अन्य खर्च भी जोड़ दें तो वेंटिलेटर का खर्च औसतन 90 हजार रुपए प्रतिदिन पड़ सकता है। वहीं देशभर में कोरोना की जांच की जो फीस तय की गई है उतनी तो देश में करोड़ों लोगों की मासिक आय भी नहीं होगी। देश में कोरोना की जांच की फीस 4500 रुपए रखी गई है। अस्पताल में किसी भी बीमारी का इलाज कराने पहुंच रहे मरीज का सबसे पहले कोरोना टेस्ट हो रहा है और उससे 4500 रुपए वसूला जा रहा है। कोरोना वायरस की आड़ में देश में एक नया गोरखधंधा शुरू हो गया है।

चुनौतियों से निपटने लायक नीति

एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन राज्यों के एजेंडे में स्वास्थ्य कभी प्राथमिकता में नहीं दिखा। जन स्वास्थ्य कभी चुनावों में बड़ा मुद्दा बनकर नहीं उभरा, जिस कारण राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा-पत्र में जन स्वास्थ्य को उतनी तरजीह कभी नहीं दी, जितनी देनी चाहिए थी। देश की आम जनता स्वास्थ्य के मसले पर ज्यादा जागरूक नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक वर्ग में यह अहसास कि स्वास्थ्य सेवा सामान्यत: मतदाताओं के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक नागरिक उन मुद्दों के प्रति संजीदा नहीं होता, तब तक राजनीतिक दल उस मुद्दे को वोट बैंक का जरिया नहीं मानते हैं।

भारत में स्वास्थ्य देखभाल के खस्ताहाल ढांचे से जुड़े आंकड़े समस्या की गंभीरता की ओर इशारा करते हैं। देश में 135 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 26 हजार हॉस्पिटल हैं यानी 47 हजार लोगों पर केवल एक सरकारी हॉस्पिटल है। करीब 30 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर नहीं हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञों के करीब 70 प्रतिशत पद खाली हैं। देश में 63 फीसदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी ऑपरेशन थिएटर नहीं है, 29 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कक्ष नहीं है। इससे भारत में जन स्वास्थ्य तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों की अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग की जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

देश में 80 फीसदी शहरी और करीब 90 फीसदी ग्रामीण नागरिक अपने सालाना घरेलू खर्च का आधे से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय कर देते हैं। इस वजह से हर साल लगभग 4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ जाती है। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास न तो कोई सरकारी स्वास्थ्य स्कीम है और न ही कोई निजी बीमा। ऐसी स्थिति में आबादी के बड़े हिस्से के लिए सरकारी स्वास्थ्य एकमात्र विकल्प बचता है। ऐसे में समय की मांग है कि जनस्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में घोषित किया जाए और इसको बजट में ऊपर का स्थान दिया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में उन्नतिशील संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए तथा स्वास्थ्य के विषय को

राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने की दिशा में केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर की शुरुआत की जा सकती है। इसके माध्यम से कुछ विशिष्ट, समर्पित एवं प्रशिक्षित लोगों को चुना जा सकेगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के मानवीकरण, वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सामग्री प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता एवं आवश्यक सामाजिक निर्धारकों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

छोटे उद्योगों पर अधिक संकट

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आंकलन किया है कि भारत की जीडीपी विकास दर 1.2 प्रतिशत सकारात्मक रह सकती है। इसके विपरीत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वैश्विक संस्था ब्लूमबर्ग ने ऋणात्मक (-)0.4 प्रतिशत, फिच, स्टैंडर्ड एंड पूअर एवं इकरा नामक रेटिंग एजेंसियों ने (-)5 प्रतिशत, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने (-)10 प्रतिशत और ग्लोबल कंसल्टेंसी संस्था आर्थर बी लिटिल ने (-)11 प्रतिशत रहने का आंकलन किया है। अधिकतर विद्वानों की सहमति (-)5 प्रतिशत पर दिखती है। अन्य लोगों के आंकलन में गिरावट इससे भी अधिक हो सकती है। इस वर्ष फरवरी में जीएसटी की वसूली 105 हजार करोड़ रुपए हुई थी। अप्रैल में 30 और मई में 60 हजार करोड़ रुपए की वसूली बताई जा रही है। इन दो माह में 71 प्रतिशत और 43 प्रतिशत गिरावट हुई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार जून में गिरावट का दौर जारी है। मई में 2.54 करोड़ ई-वे बिल जारी हुए थे जिन पर 60 हजार करोड़ रुपए की जीएसटी की वसूली हुई। 1 से 10 जून तक 87 लाख ई-वे बिल जारी हुए। इस रफ्तार से पूरे जून में 2.61 करोड़ ई-वे बिल जारी होने की संभावना है। इसके आधार पर जून में जीएसटी की वसूली 62 हजार करोड़ रुपए होने के आसार हैं जो फरवरी के मुकाबले (-)41 प्रतिशत

होगी। मान लें कि जुलाई में सुधार हो जाएगा और केवल (-)20 प्रतिशत की गिरावट होगी और अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक विकास दर शून्य रहे तो भी पूरे वर्ष का औसत (-)14.6 प्रतिशत गिरावट का रहेगा। अगस्त 2020 से मार्च 2021 की विकास दर को शून्य मानने का कारण यह है कि पिछले 4 वर्षों में हमारी जीडीपी विकास दर लगातार गिर रही है। वर्ष 2017 में यह 10 प्रतिशत थी, 2018 में 8 प्रतिशत, 2019 में 5 प्रतिशत और 2020 में मात्र 4 प्रतिशत रह गई। वर्तमान संकेतों के अनुसार कोरोना का प्रकोप जुलाई तक रहने का अंदेशा है।

दूसरा दौर भी आने की आशंका

चूंकि प्रकोप का दूसरा दौर भी आने की आशंका है इसलिए अगस्त के बाद विकास दर सकारात्मक रहने की संभावना कम ही है और हम इसे शून्य मान सकते हैं। जीएसटी के अनुपात में ही जीडीपी में भी परिवर्तन हो रहा है। 2019 और 2020 के बीच जीएसटी की वसूली में 3.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जबकि जीडीपी में 4 प्रतिशत की। अत: 2020-21 में जीएसटी की वसूली में (-)14.6 प्रतिशत गिरावट से जीडीपी में भी इतनी ही गिरावट आ सकती है। रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि जीडीपी में गिरावट अल्पकालीन होगी और अगस्त के बाद आर्थिक विकास चल पड़ेगा। कोरोना संकट की अवधि को पार करने के लिए सरकार ने जो अतरिक्त ऋण लिए हैं उस पर ब्याज अगस्त के बाद की राजस्व में तीव्र वृद्धि से अदा कर दिया जाएगा। इस आंकलन में सरकार पिछले चार वर्षों से विकास दर में आ रही गिरावट को अनदेखा कर रही है।

चूंकि गिरती अर्थव्यवस्था को कोरोना ने एक बड़ा झटका दिया है ऐसे में इसमें संदेह है कि अगस्त के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पुन: तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। यदि यह मान भी लें कि इस पूरे वर्ष में जीडीपी की गिरावट केवल (-)5 प्रतिशत होगी तो भी हमें तैयारी (-)15 प्रतिशत की करनी चाहिए। संकट को कम नहीं आंकना चाहिए। बीते चार वर्षों में जीडीपी विकास दर में गिरावट का सिलसिला नोटबंदी से शुरू हुआ। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना के कारण छोटे उद्योगों पर अधिक संकट आया है। इनके संकटग्रस्त होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार कम बने और मांग भी कम हो गई। मांग कम होने से बड़े उद्योग भी संकट में आ गए हैं। इसलिए सरकार को छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें ऋण देने से काम नहीं चलेगा। उनकी मुख्य समस्या बाजार में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा है।

भारत में आर्थिक असमानता का सच उजागर किया?

महान दार्शनिक रूसो ने कहा था कि 'कोई भी नागरिक कभी भी इतना समृद्ध नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे नागरिक को खरीद सके, और कोई भी नागरिक इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वह खुद को बेचने को मजबूर हो जाए।' पर बीते समय में कोरोना वायरस का भारत और विश्व पर प्रहार इतना क्रूर था कि मानवीय संवेदनाओं के यह सिद्धांत उलट गए। भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को केरल में मिला। तब से अब तक साढ़े चार माह के समय में तैयारियों का आंकलन करें तो यह तैयारियां बढ़ती जरूरतों से कम दिखती हैं। नतीजतन प्रतिदिन कोरोना के करीब 10,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। शुरुआत में यह वायरस आयातित था और ज्यादातर मामले सिर्फ विदेशों में पढ़ाई या दूसरे देशों से लौटे व्यवसायी वर्ग के लोगों में दिख रहे थे किन्तु आज स्थिति बदली हुई है और संक्रमण का स्वभाव भी। वायरस के संक्रमण का चरित्र बदला और अब ये हर वर्ग तक पहुंच गया। यह स्थिति और भयावह है क्योंकि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं जो अनौपचारिक सेक्टर में कार्यरत हैं और सघन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिससे दो गज की दूरी का पालन करना असंभव प्रतीत होता है। भारत में टीबी और पोलियो ऐसी दो बीमारियां हैं, जिनकी शुरुआत संपन्न वर्ग से हुई किन्तु निम्न और मध्यम वर्ग इन बीमारियों से आज भी जूझ रहा है।

छोटे उद्योग, बड़ा संकट

पिछले दो महीने में कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए की गई पूर्णबंदी से उद्योगों को भारी झटका लगा है। इसका सीधा असर देश की विकास दर पर पड़ा है। पिछले कुछ समय में सरकार की ओर से जो राहत और प्रोत्साहन पैकेज जारी किए गए हैं, उससे यह उम्मीद तो बंधी है कि कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा, लेकिन यह सरकार और उद्योगों दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। एक जून को सरकार ने दो लाख कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को उबारने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की सहायता और रेहड़ी-पटरी वालों को भी फिर से कारोबार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए तक के कर्ज की मंजूरी दे दी है।

साथ ही, अच्छा प्रदर्शन कर रही एमएसएमई को और मजबूत बनाने के लिए पचास हजार करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इससे एमएसएमई उद्योगों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि एमएसएमई को लाभ देने के लिए सरकार ने इसकी परिभाषा में बड़ा बदलाव किया है। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक इकाई की परिभाषा के तहत निवेश की सीमा बढ़ाकर सूक्ष्म उद्योग के लिए 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का कारोबार कर दिया है। वहीं लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। मध्यम उद्योग के लिए 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए कारोबार की सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे में **देश और दुनिया के अर्थविशेषज्ञों** का मानना है कि जो एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनमें नई जान फूंककर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने पिछले महीने घोषित व्यापक आर्थिक पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 100 से ज्यादा राहतों की घोषणा की थी।

उल्लेखनीय है कि नए राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार किसी भी विदेशी आपूर्तिकर्ता से 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद नहीं करेगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे छोटे और मझौले उद्योगों की वस्तुओं व सेवाओं की नई मांग पैदा की जा सकेगी। इसी तरह निर्माण परियोजना को पूरा करने और पंजीकरण की समयावधि को छह महीने आगे बढ़ाए जाने से डेवलपर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कारणों से एमएसएमई के कई कर्ज एनपीए हो गए थे। ऐसे में उनके पास नकदी जुटाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बैंक एमएसएमई को कर्ज नहीं दे रहे थे। लेकिन अब नए पैकेज के तहत एनपीए वाले एमएसएमई को भी नया कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नए आर्थिक पैकेज में छोटे उद्योगों के उत्पादन को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए जो संकल्पना की गई है, उससे स्थानीय एवं स्वदेशी उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वैश्विक संकट में जब दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई हैं, तब भी स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था, स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार देश के बहुत काम आए हैं।

यदि हम वर्तमान समय में वैश्विक ब्रांडों की ओर देखें तो पाएंगे कि वे भी कभी बिल्कुल स्थानीय ही थे। इसलिए कोरोना संकट में न सिर्फ हमें स्थानीय उत्पाद खरीदने हैं, बल्कि उनको हरसंभव तरीके से आगे बढ़ाना भी जरूरी है। हमें स्थानीय ब्रांडों और उत्पादों को अपनी अर्थव्यवस्था का **आधार बनाने** और उन्हें दुनियाभर में मशहूर करने की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा।

हम मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाकर स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बना सकते हैं। आज दुनियाभर में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली भारत की कई कंपनियां अपनी जबर्दस्त पहचान बनाए हुए हैं। यदि हम पेट्रोलियम उत्पाद और गूगल, फेसबुक जैसी टेक कंपनियों को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्रों में हमारे स्थानीय उत्पाद वैश्विक उत्पादों का रूप ले सकते हैं और दुनिया के बाजारों में छा सकते हैं। इस समय दुनिया में दवाओं सहित कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, परिधान, जेम्स व ज्वैलरी, चमड़ा और इसके उत्पाद, कालीन और मशीनी उत्पाद जैसी कई वस्तुओं की भारी मांग है। इसलिए इन क्षेत्रों में दुनिया का बाजार अनंत संभावनाएं लिए हुए है।

● **पारस कुमार**

छोटे उद्योगों के समक्ष गंभीर चुनौतियां

पूर्णबंदी और श्रमिकों के पलायन ने छोटे उद्योगों के समक्ष गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हालांकि सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को बगैर किसी जमानत के आसान बैंक कर्ज सहित कई राहतों का ऐलान किया है, लेकिन अधिकांश बैंक कर्ज में डूबने की आशंका के मद्देनजर कर्ज देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। स्थिति यह है कि करीब सवा छह करोड़ इकाईयों में से आधी से अधिक इकाईयां उत्पादन शुरू भी नहीं कर पाई हैं। जिनमें काम शुरू हुआ है, वे भी काफी कम क्षमता के साथ परिचालन कर रही हैं। कच्चे माल की दिक्कतें उनके सामने खड़ी हैं और आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है। मजदूरों की कम उपलब्धता के कारण कारखानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पहले ही सुस्त चल रही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एमएसएमई के आधार पर बढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है। 30 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास दर 4.2 फीसदी के साथ ग्यारह वर्ष के निचले स्तर दर्ज की गई। इस तरह जहां कोविड-19 से पहले ही अर्थव्यवस्था की गति सुस्त रही, वहीं अब प्रमुख वैश्विक संगठनों और कई अर्थविशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर ऋणात्मक रहेगी।

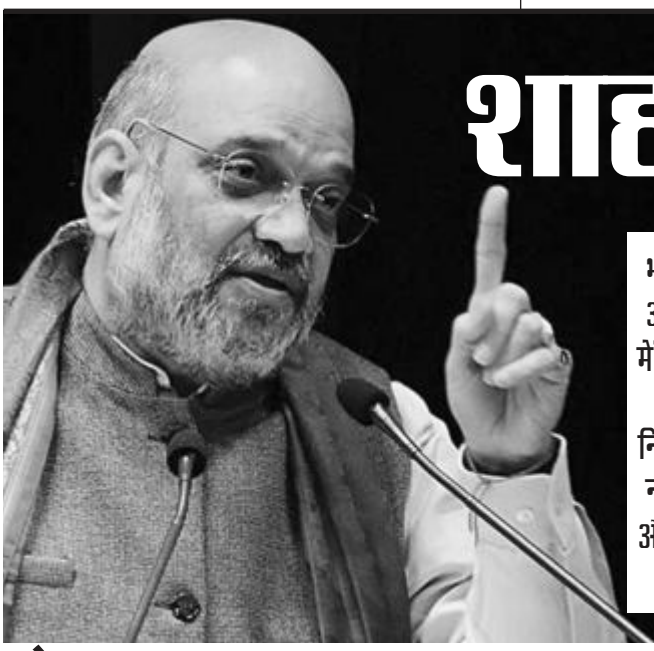

शाह हुए सफल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक लंबी पारी खेलने के बाद अब अमित शाह देश के गृहमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री के रूप में उनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान देश में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। शाह के गृहमंत्री बनने के बाद कई ऐसे निर्णय हुए हैं, जो आजादी के बाद से ही प्रतीक्षारत थे। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी को एक बार फिर ताकत और विश्वसनीयता मिली है। लोगों को उम्मीद है कि यह जोड़ी भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान अगर किसी मंत्रालय की सबसे ज्यादा चर्चा हुई और जिसने देश के इतिहास को बदलने वाले कुछ निर्णय लिए तो वह है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। पिछले एक साल में जहां इस मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र भी यही मंत्रालय रहा, जिस पर विपक्ष ने कई मौकों पर समय पर काम न करने का आरोप लगाया। आइए जानते हैं आखिर एक साल में अमित शाह का गृह मंत्रालय क्यों रहा महत्वपूण।

भारत समेत पूरा विश्व कोरोनावायरस की चपेट में है। पिछले 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। पिछले 100 साल में ऐसा पहला मौका था जब किसी महामारी के चलते गतिविधियों में ताला लगा दिया गया था। इस निर्णय को देशभर में लागू करवाना और इसके साथ ही समन्वय से चरणबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण गतिविधियों को गतिशील बनाए रखना मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी और इससे निभाया गृह मंत्रालय ने। हालांकि विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या सरकार नहीं समझ पाई और लॉकडाउन लागू करना मोदी सरकार की गलती थी और आज भी यह आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अगर हम नजर डालेंगे कि लॉकडाउन की चार चरणों को कैसे देश में अमल किया गया तो उसमें गृह मंत्रालय की **भूमिका का अंदाजा** लग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद जैसे ही लॉकडाउन देशभर में शुरू हुआ प्रदेशों को किस दिशा में जाना है क्या-क्या निर्देशों का पालन करना है गृह मंत्रालय की ओर से लगातार निर्देश आने शुरू हो गए। इन निर्देशों से प्रदेशों को यह जानकारी मिलने में सहूलियत हुई कि आखिरकार अब जब महामारी के चलते पूरा देश बंद हो जाएगा तो कैसे हमें काम करना है। आदेश जारी करने के बाद समय-समय पर इसकी निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई स्पष्टीकरण भी जारी किए। एक ओर जहां स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य मंत्रालय अपने-अपने विभागों का काम देख रहे थे तो वहीं गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान एक 24 घंटे का कंट्रोल रूम अपने मंत्रालय में स्थापित कर दिया था और दोनों गृह राज्यमंत्री लगातार इस कंट्रोल रूम में काम की निगरानी करते। हर घंटे सिलसिलेवार तरीके से देश के हर एक राज्य की जानकारी इस कंट्रोल रूम में ली जाती और उसके मुताबिक रणनीति बनाई जाती और दिशा-निर्देशों का खाका तैयार किया जाता। कोरोनावायरस संक्रमण का दौर अब भी जारी है लॉकडाउन पूरी तरीके से कब उठेगा और कैसे गतिविधियां सामान्य दिशा की ओर बढ़ेगी यह आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।

5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह अपनी चिर परिचित अंदाज में संसद भवन आए। लेकिन उससे पहले सबको यह आभास हो चुका था कश्मीर को लेकर कुछ न कुछ अहम जरूर होने वाला है। उसकी वजह थी कश्मीर में भारी तादात में सुरक्षा बलों की मौजूदगी, ठीक 1 घंटे पहले यानी 9 बजे हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अहम बैठक और कश्मीर में हो रही तमाम तरीके की हलचल ने भी इस हवा को जोर दे दिया था। हाथ में चंद कागजात लिए गृहमंत्री अमित शाह ने संसद भवन में बोलना शुरू किया। करीब 11:05 पर उन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाएगा। यानी कि जो विशेष अधिकार इस कानून के तहत कश्मीर के लोगों के पास था अब इस धारा के हटने के बाद वह अधिकार खत्म हो गए थे। कश्मीर में अब आईपीसी के कानून के मुताबिक न्याय व्यवस्था चलने का ऐलान किया गया। इस धारा के हटने के बाद सबसे अहम बदलाव ये हुआ कि अब कश्मीर में भारत का कोई भी आदमी आकर जमीन खरीद सकता है

पुलिसिंग को मजबूत बनाने पर जोर

अपने 100 दिनों के कार्यकाल में गृहमंत्री अमित शाह ने जिन पुलिस अकादमियों का दौरा किया उसमें हैदराबाद की नेशनल पुलिस अकादमी और दिल्ली की ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमुख थे। इसके अलावा गृहमंत्री दिल्ली के पुलिस मेमोरियल भी गए जिसको शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में बनाया गया है। पुलिस सिस्टम से जुड़ी इन जगहों का दौरा कर गृहमंत्री ने यह साफ कर दिया कि पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करना उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य में से एक है। इसके लिए पुलिस को मजबूत बनाने के लिए विशेष संस्थान खोले जाएंगे जहां पर वह खासतौर के तकनीकी शिक्षा ले सकें साथ ही तैनात पुलिस वालों को उनके काम के लिए पूरा सम्मान मिले इसके लिए सिर्फ पुलिसकर्मियों के लिए स्मारक बनाया गया जिसमें आजादी के बाद से अब तक 35 हजार से ज्यादा शहीद हुए पुलिसकर्मियों का नाम है। गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि अपराधियों से 10 कदम आगे पुलिस को रहना चाहिए तभी अपराध पर काबू पाया जा सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ 26 अगस्त को बैठक की जिसमें गृहमंत्री शाह के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।

अगर बेचने वाला शख्स राजी है। इस धारा के हटने के बाद से मानो भारत के लिए कश्मीर के रास्ते खुल गए। लेकिन स्थानीय लोग यानी कश्मीर में जो लोग रहते हैं वह इस धारा के हटने के बाद किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे इसका अभी सबको इंतजार है।

पिछले कई दशकों में असम और उसके आसपास के **इलाकों में बोडोलैंड** राज्य की अलग मांग कर रहे कई संगठनों ने हथियार उठा रखा था और लगातार प्रदेश में हिंसक वारदात को अंजाम दे रहे थे। गृह मंत्रालय ने पहली बार इन अलग-अलग गुटों को एक मंच पर लाया और उनके साथ विकास का खाका बनाकर एक ऐसी शांति की प्रक्रिया स्थापित की जिसके बाद यह संगठन मुख्यधारा में आने को तैयार हो गए। दरअसल इससे पहले भी बोडो संगठनों को बातचीत के लिए मनाया गया था लेकिन एक साथ सारे संगठन बात नहीं मान रहे थे। मध्यस्थकारों के जरिए सारे पक्षकारों को एक मंच पर लाया गया नई दिल्ली बुलाया गया और शांति समझौते पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए गए।

5 अगस्त को गृहमंत्री मंत्री अमित शाह ने एक और अहम घोषणा की वह थी जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन। इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान है। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए। हालांकि गृहमंत्री ने ये भी साफ किया कि जम्मू-कश्मीर को वापस प्रदेश बनाया जा सकता है अगर तय समय की समीक्षा के बाद माहौल अनुकूल पाया गया। इस अधिनियम के पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होने का प्रावधान है। यानी देश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं अब उनकी तरह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी होगा। 5 अगस्त को ही हुई इस घोषणा के बाद भारत में जम्मू-कश्मीर का नक्शा बदल गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अपने अस्तित्व में आ गए। ब्रू रियांग समझौते का फैसला करीब 35000 लोगों से जुड़ा हुआ था लेकिन इसके जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने देशभर में यह संदेश देने की कोशिश की कि दूरदराज इलाके में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को अगर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो तो भारत सरकार उनके साथ है। मिजोरम से लाकर त्रिपुरा में ऐसे लोगों को बसाने के लिए भारत सरकार और 2 प्रदेशों की सरकार ने कई महीनों तक मिलकर एक योजना तैयार की और उसके बाद ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन 2019 विधेयक भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद सत्र के पहले महीने में ही पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रह रहे लोगों को 3 फीसदी आरक्षण का लाभ उसी तरह से मिलना शुरू हो गया जैसे नियंत्रण रेखा पर रह रहे लोगों को मिलता है। सरकार का बिल पारित कराने के पीछे ये मकसद था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को समान अधिकार और सहूलियतें मिले। जम्मू-कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण कदम उठाते वक्त गृहमंत्री ने यह साफ कर दिया कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के साथ है और हर कदम पर उस इलाके के विकास के लिए वह काम करेगी। इसीलिए सरपंचों और पंचों का जम्मू-कश्मीर में सशक्तिकरण किया गया यानी उन्हें और ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए जिसके बाद उन्हें अपने गांव में अपने इलाकों में अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करने की छूट है। इसके अलावा केंद्र सरकार के 80,000 करोड़ रुपए जो परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चल रही हैं उसके भी काम में तेजी लाई गई है।

यूएपीए कानून में बदलाव और एनआईए को मजबूत बनाना इन दोनों कानूनों को मजबूत बनाने के लिए संसद में दो महत्वपूर्ण बिल पारित कराए गए जिसके पीछे सरकार का मकसद यही था कि जांच **एजेंसियां जो संवेदनशील अपराधों** की तफ्तीश कर रही है उनको और ज्यादा शक्ति मिले। यही नहीं कानून को इतना मजबूत बना दिया जाए कि अगर जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है तो अपराधी को तुरंत सजा मिले। यह तो थी संसद के भीतर सरकार द्वारा कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए जाने की बात। लेकिन संसद के बाहर भी कुछ ऐसे कदम थे जिसके जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह बदलाव करना चाहती है और इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए।

● **इन्द्र कुमार**

गृह मंत्रालय पर सवाल

पिछले एक साल के दौरान अगर महत्वपूर्ण निर्णय जिस मंत्रालय ने दिए तो विपक्ष की ओर से सवाल भी इसी मंत्रालय पर सबसे ज्यादा उठाए गए। इस फेहरिस्त में सबसे आगे था दिल्ली दंगों के दौरान गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस का वक्त पर सही कदम न उठाना। विपक्ष का आरोप था कि समय पर कदम नहीं उठाए गए इसलिए 40 लोगों की मौत दिल्ली दंगों के दौरान हो गई। इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में दिया। सिलसिलेवार तरीके से प्रभावशाली कदम उठाने का सिलसिला घटना के दिन से ही शुरू हो गया था। बहरहाल इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। इसके अलावा जेएनयू और जामिया में छात्रों का जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसे लेकर भी विपक्ष का यही कहना था कि सरकार ने छात्रों की बात नहीं सुनी इसीलिए आंदोलन उग्र होता गया। जबकि सरकार का पक्ष यही था कि छात्रों की हर वाजिब मांग को वह सुनने को तैयार है। काफी गतिरोध के बाद यह प्रदर्शन खत्म हुआ। इसके अलावा शाहीन बाग में एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसकी देशभर में चर्चा हुई। इसमें भी गृह मंत्रालय को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई। हालांकि समय-समय पर भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने इन मुद्दों पर अलग-अलग मंचों पर सफाई दी और अपना पक्ष रखा लेकिन आने वाले दिनों में इन्हीं को आधार बनाकर विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश करेगा और उसका जवाब तैयार करना और इससे निपटना गृह मंत्रालय और भारत सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। अमित शाह की असली परीक्षा तब होगी। अब देखना यह है कि शाह इस परीक्षा में किस रणनीति के तहत काम करते हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई अवसर ऐसे दिए जब विपक्ष उन्हें मुद्दा बनाकर सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर सकता था। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस न तो उन मुद्दों को सफलता पूर्वक उठा पाई और न ही विपक्ष का नेतृत्व कर पाई। इस कारण मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी का माहौल नहीं बन पाया। अब कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किए गए लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसे भुनाने के लिए कांग्रेस ठीक से मोर्चा नहीं संभाल पाई।

एंटी इंकम्बेंसी नहीं...

केंद्र में भाजपा को सत्ता संभाले 6 साल हो गए लेकिन आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी नहीं है। इसकी यह वजह नहीं है कि केंद्र सरकार सबकुछ अच्छा कर रही है। दरअसल, विपक्ष कमजोर और निष्क्रिय है। जरा फरवरी 2020 की स्थिति पर गौर करें। नरेंद्र मोदी सरकार 'क्रमबद्ध' सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर नरमी दिखाने को तैयार नहीं थी, जिनसे कि लाखों भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिनने का खतरा था। भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषणों से, बहुतों के अनुसार, दिल्ली में भड़के दंगों में 50 से अधिक लोग जान गंवा चुके थे। ये नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों को लेकर सत्ता प्रतिष्ठान की प्रतिक्रिया थी। सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने तक को तैयार नहीं थी। मुख्य विपक्ष कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श हिंदू-मुस्लिम के मुद्दों पर केंद्रित था, जिसे वे अपना सबसे कमजोर पक्ष मानती हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के बावजूद वे बहस को रोजी-रोटी के मुद्दे की तरफ मोड़ने में नाकाम रहे थे।

जानकारों का कहना है कि इन दिनों कांग्रेस के भीतर ही तीन कांग्रेस हैं। कांग्रेस (एस), कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (पी)। और ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को मालूम नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। सोनिया गांधी घोषणा करती हैं कि कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के ट्रेन टिकट का खर्च उठाएगी और राहुल गांधी इस बारे में ट्वीट तक नहीं करते, जूम कॉन्फ्रेंस की बात ही जानें दें। वास्तव में, उन्हें दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर होना चहिए था, इस मुद्दे पर आगे बढ़कर नेतृत्व देना चाहिए था। राहुल गांधी और उनके लोग पार्टी में इस कदर हाशिए पर पड़े हैं कि शायद निजी तौर पर वे इस बात का विलाप करते हों कि ज्यादातर शीर्ष नेता उन्हें रीट्वीट तक नहीं करते। वहीं प्रियंका गांधी उत्तरप्रदेश में अपने मन का काम करती हैं, क्योंकि उनके ताकतवर सहयोगी संदीप सिंह को ये दिखाना है कि उनके पास डीके शिवकुमार और अहमद पटेल से बेहतर आइडिया है। इसका परिणाम स्वरूप अक्सर ऐसा लगता है मानो अपनी राजनीतिक छाप छोड़ने के लिए तीनों धड़े एक-दूसरे से होड़ में लगे हों। वास्तविक विभाजन के अभाव में, ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी को पता ही नहीं है कि वह क्या कर रही है या किस दिशा में बढ़ रही है।

कांग्रेसी नेताओं को सिर्फ एक ही बात प्रेरित करती है कि पार्टी के अन्य नेताओं को सफल होने नहीं दिया जाए। वैसे ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके कारण उन्हें कुछ करने की प्रेरणा तो मिलती है। लेकिन तीनों खेमों में से किसी को भी सफलता मिलती नहीं दिखती है क्योंकि उनमें से किसी को भी 'राजनीतिक अभियान' की समझ नहीं है या ये तक नहीं पता है कि सार्वजनिक रूप से कोई बात सामने रखने के लिए एक प्रचार अभियान की जरूरत होती है।

महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, विभिन्न विचारधाराओं के सफल राजनेताओं ने आम जनता के मन में किसी बात को बिठाने के लिए राजनीतिक अभियान की जरूरत को समझा है। राजनीतिक अभियान नियोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जिसके जरिए एक या कुछेक सुसंगत विचार पेश किए जाते हैं, यह बारंबार दोहराए जाने के कारण विचार विशेष लोगों को समझने में मदद करता है; इसमें पहले से तय नाम, **कीवर्ड और हैशटैग** होते हैं; और इसे न्यूनतम दो सप्ताहों तक चलाया जाता है।

गांधी निकटतम समुद्र तट तक पहुंचकर नमक बना सकते थे। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने दांडी का लंबा रूट चुना और उस मार्च

कोरोना संकट एक और अवसर

आज लाखों की संख्या में गरीब प्रवासी मजदूर, अचानक घोषित हुए लॉकडाउन की वजह से मुसीबत झेल रहे हैं, और भारत अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से दो-चार हैं। लेकिन मोदी सरकार लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रही है कि लॉकडाउन न केवल सफल रहा है, बल्कि इससे हजारों लोगों का जीवन भी बचाया जा सका है। भारत में कोरोनावायरस से हो रही मौतों की, दूसरे विकसित देशों के साथ लगातार तुलना करने से, इस सरकार को एक पॉजिटिव कहानी बनाने में मदद मिली है, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने स्वीकार कर लिया है। मौजूदा सियासी माहौल और लोगों के मूड को देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा 2024 में तीसरा चुनाव जीत लेगी। ऐसा संभव नहीं लगता कि फिलहाल जो बढ़त उसे हासिल है, पार्टी उसे आसानी से गंवा देगी। इस बात की भी संभावना नहीं है कि लोग अचानक से विपक्षी दलों और नेताओं में भरोसा दिखाने लगेंगे। 2024 में चुनावी मुकाबला तभी मुमकिन है, जब चीजें बिल्कुल उलट जाएं। अवसर बहुत कम हैं लेकिन एक संभावना अभी भी बाकी है। हमने देखा है कि एक बेहद लोकप्रिय कांग्रेस, जिसकी अगुवाई एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री (राजीव गांधी) कर रहे थे, सिर्फ कुछ महीनों में बिखर गई और अगला चुनाव हार गई।

की बारीकी से योजना बनाई ताकि नागरिक अवज्ञा के उनके संदेश को आम जनता पूरी तरह आत्मसात कर सके। इस तरह, नरेंद्र मोदी राजनीतिक को इवेंट मैनेजमेंट का रूप देने वाले कोई पहले व्यक्ति नहीं हैं। स्मार्ट राजनीति हमेशा से ऐसी ही रही है क्योंकि मूलत: ये जनता से संवाद का उपक्रम है।

लगता नहीं है कि गांधी की विरासत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी (सच में करती भी है?) इस बात को समझती है। सोनिया गांधी (मतलब अहमद पटेल) घोषणा करते हैं कि कांग्रेस सभी प्रवासी श्रमिकों के टिकट का भुगतान करेगी। शानदार आइडिया। मोदी सरकार घबराकर एक फर्जी दावा करती है कि केंद्र टिकट का 85 प्रतिशत दे रही है, जबकि शेष 15 प्रतिशत राज्यों की जिम्मेवारी है। ये कांग्रेस का एक दिवसीय आयोजन, या कहें कि प्रेस-रिलीज आयोजन साबित हुआ। यदि इसी को अभियान की तरह चलाया जाता तो हर किसी को पता चलता कि कांग्रेस ने कितने टिकट खरीदे; कांग्रेसी सरकारों ने क्या किया, आदि-आदि। इसी तरह राहुल गांधी ने दो अर्थशास्त्रियों 'रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी' के साथ जूम पर चैट किया और फिर उस बारे में भूल गए। उनसे क्या निकला? परिणाम क्या रहे? आगे क्या कदम उठाए गए? कुछ प्रवासी श्रमिकों से मिलने में उन्हें कई हफ्ते लग गए, और वो भी अपने आप में एक अकेला कार्यक्रम था जिसे 'वृतचित्र' की तरह पेश किया गया जिसे किसी ने नहीं देखा।

इसी तरह, प्रियंका गांधी ने एकबारगी दावा किया कि कांग्रेस मजदूरों के लिए बसें उपलब्ध करा रही हैं और योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए उनकी पोल खोल दी कि वो तुरंत बसें भिजवाएं। बारंबार, हम अभियान वाले दृष्टिकोण का अभाव देखते हैं जो कि इस तरह की नाकामियों से बचा सकता था। राहुल गांधी को प्रवासी मजदूरों के साथ दिल्ली से अमेठी तक चलके जाना चाहिए था। जिम में इतना व्यायाम करना भला किस दिन काम आएगा? और मजदूरों के लिए बस चलाने देने से योगी आदित्यनाथ के इनकार के खिलाफ एक भावपूर्ण भाषण देने के लिए प्रियंका गांधी को खुद दिल्ली या राजस्थान से लगने वाली उत्तरप्रदेश की सीमा पर जाना चाहिए था। उन्हें अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। इसकी बजाय पार्टी के उत्तरप्रदेश प्रमुख गिरफ्तार किए जाते हैं और पार्टी नेता, हमेशा की तरह, ट्वीट कर इसकी निंदा करते हैं।

किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए बहुत सामान्य बात है कि शासन के पहले वर्ष में वो लोकप्रिय बनी रहती है। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा करने के समय, नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता पूरी तरह बरकरार है। हालिया सर्वेक्षणों के सबूत भी इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, खासकर **भारत में कोरोनावायरस** संकट से कुशलता के साथ निपटने से, मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। विरोधी लहर का मूड आमतौर पर तब बनना शुरू होता है, जब सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लेती है, यानी सत्ता में रहने के ढाई साल बाद। तो, सवाल ये उठना चाहिए कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आधा समय पूरा होने पर, उसके खिलाफ विरोधी लहर उठेगी, या नहीं? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता। फिलहाल लोगों के मूड, और पूरी तरह अव्यवस्थित पड़े विपक्ष को देखते हुए, मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से, 2024 में तीसरा राष्ट्रीय चुनाव जीत लेगी।

मोदी की अगुवाई में भाजपा ने पिछले 6 सालों में, बहुत से चुनावी पैटर्न तोड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भाजपा 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, और उत्तर भारत के बहुत राज्यों में पार्टी का सीट शेयर अपने शिखर पर पहुंच जाएगा। ऐसा माना जाता था कि उप्र, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भाजपा के लिए 2014 के अपने चुनावी प्रदर्शन को दोहराना नामुमकिन साबित हो सकता है। लेकिन पिछले तमाम चुनावी पैटर्न्स को तोड़ते हुए, पार्टी ने इनमें से बहुत से राज्यों में, न केवल अपनी चुनावी सफलता को दोहराया, बल्कि कुछ में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया, और उनमें से बहुत से सूबों में अपना वोट शेयर 50 प्रतिशत के पार ले गई। 2019 में भाजपा से पहले कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी सियासी पार्टी **लगातार दो चुनाव नहीं जीत पाई** है। अपने चुनावी प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दोनों से पार्टी को दूसरे कार्यकाल के मध्य में उठने वाली किसी भी विरोधी लहर से निपटने में सहायता मिलेगी।

मोदी आज उतने ही लोकप्रिय हैं (मगर अधिक नहीं), जितने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी अपने समय में थे। कोरोनावायरस वैश्विक महामारी से ग्रस्त कई देशों में हुए सर्वेक्षणों में, मोदी को कोविड-19 से निपटने में, अपने वैश्विक समकक्षों से ऊंचा आंका गया है। जो चीज मोदी सरकार को लोकप्रिय बनाती है, वो है बहुत समय से लंबित पड़े विवादास्पद कानूनों को पास करने की इसकी क्षमता। धारा 370 को कमजोर करने, जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन, तीन तलाक कानून और नागरिकता संशोधन कानून ने, अधिकतर हिंदुओं में खुशी की लहर भर दी है, और भाजपा में उनकी आस्था को बरकरार रखा है।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

वातानुकूलित हवाई किला

महामारी व लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर रोक कांग्रेस पार्टी के आलसी लुटियंस नेताओं के लिए वरदान साबित हुई है। उन्हें अब बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भी नहीं। क्योंकि राजनीतिक धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। घरों से दूर फंसे मजदूर जब जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हों, राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर लगाते हैं, जिसका शीर्षक है- 'कार्यालय में एक शांत शाम'। इतनी बेवकूफी के लिए निश्चय ही बहुत प्रयास की जरूरत होती होगी, प्रवासी श्रमिकों से मिलने में राहुल गांधी को 50 दिनों से अधिक का समय लगता है। प्रियंका गांधी ने अपना काम अपने 'निजी सचिव' को सौंप रखा है जो कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या किसी को पता है कि नरेंद्र मोदी का निजी सचिव कौन है? या अमित शाह का? नहीं, क्योंकि ये नेता राजनीति की मूल बातें जानते हैं, जैसे ये बात कि नेता का काम है नेतृत्व करना।

मनरेगा में टॉप पर छत्तीसगढ़

श्रमिकों को मनरेगा के तहत दिया जा रहा रोजगार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, बसों एवं अन्य माध्यमों से अब तक 3 लाख 13 हजार प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे हैं। गृहराज्य लौटने पर प्रवासी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर एवं अन्य लोग रुके हुए थे। राज्य सरकार द्वारा इन श्रमिकों को छत्तीसगढ़ लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था और अधिकारियों की मुस्तैदी से इन श्रमिकों को सकुशल छत्तीसगढ़ वापस लाया जा रहा है। श्रम मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अन्य राज्यों से वापस लौटे इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनका मनरेगा के तहत जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका भी जॉब कार्ड बनाकर रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है।

कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के बाद भी मनरेगा के विभिन्न मानकों पर छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरुआती दो महीनों में ही सालभर के लक्ष्य का 37 फीसदी काम पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल अप्रैल और मई के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 175 प्रतिशत काम हुआ है। इन दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। दो माह के भीतर **सर्वाधिक परिवारों** को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। राज्य में 1996 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 5 करोड़ 3 लाख 37 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन कर 25 लाख 97 हजार ग्रामीण श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान 1114 करोड़ 27 लाख रुपए का मजदूरी का भुगतान भी किया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ताजा वित्त वर्ष के पहले दो महीने में दो करोड़ 88 लाख 14 हजार मानव दिवस बनाने का लक्ष्य दिया था। इसके सापेक्ष 5 करोड़ 3 लाख 37 हजार मानव दिवस का काम छत्तीसगढ़ में किया गया। इस तरह से छत्तीसगढ़ ने कुल काम का 37 प्रतिशत इन्हीं दो महीनों में हासिल कर लिया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य में प्रति परिवार को कम से कम 23 दिन का काम मनरेगा के अंतर्गत दिया गया, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 16 दिन ही है। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में मनरेगा के अंतर्गत व्यापक स्तर पर शुरू किए कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विपरीत परिस्थितियों में इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजी-रोटी की चिंता से मुक्त करने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने प्रदेशभर में सक्रियता एवं तत्परता से किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सरपंचों, मनरेगा की राज्य व जिला और जनपद पंचायतों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बीच यह बड़ी उपलब्धि है। उनकी कोशिशों से लाखों लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में आजीविकामूलक सामुदायिक व निजी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों अप्रैल और मई के लिए 2 करोड़ 88 लाख 14 हजार मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ ने इस समयावधि में 5 करोड़ 3 लाख 37 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन कर 175 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। मनरेगा से हो रहे आजीविका संवर्धन के कार्यों ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। जीवन-यापन के साधनों को सशक्त कर इसने लोगों की आर्थिक उन्नति के द्वार खोले हैं। कोविड-19 से निपटने लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौर में भी मनरेगा से निर्मित संसाधनों ने हितग्राहियों की आजीविका को अप्रभावित रखा है। नए संसाधनों ने उन्हें इस काबिल भी बना दिया है कि अब विपरीत परिस्थितियों में वे दूसरों की मदद कर रहे हैं।

लॉकडाउन में जब लोग रोजी-रोटी की चिंता में घरों में बैठे हैं, तब जांजगीर-चांपा के सीमांत किसान खम्हन लाल बरेठ अपनी डबरी से मछली निकालकर बाजारों में बेच रहे हैं। डबरी के आसपास की जमीन में उगाई गई सब्जियां उन्हें अतिरिक्त आमदनी दे रही हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पैदा हुए विपरीत हालातों के बीच भी उनका 14 सदस्यों का परिवार आराम से गुजर-बसर कर रहा है। खम्हन लाल की इस बेफिक्री का कारण मनरेगा के तहत उनके खेत में खुदी डबरी है। इस डबरी ने मछली पालन के रूप में कमाई का अतिरिक्त साधन देने के साथ ही बरसात में धान की फसल के बाद सब्जी की खेती को भी संभव बनाया है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

सरकार तो संकट में नहीं?

राज्यसभा चुनाव के चलते ही फिलहाल राजस्थान में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बार-बार स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। खुले तौर पर अशोक गहलोत के निशाने पर नजर तो भाजपा ही आ रही है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ भी कुछ-कुछ संदेह की आंच और लपटें घूम रही हैं। ऐसे में सचिन पायलट को भी सफाई देनी पड़ रही है। अभी मध्य प्रदेश जैसी कोई खिचड़ी भले ही नहीं पक रही हो, लेकिन सचिन पायलट भी नपे-तुले बयान वैसे ही दे रहे हैं जैसे लॉकडाउन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से बातें सुनने को मिल रही थीं।

अब ये तो है कि सचिन पायलट भी वैसी ही नाव पर सवार हैं, जैसी नाव लेकर सिंधिया कांग्रेसी भंवर में जूझ रहे थे और जब किनारे पहुंचे तो सबसे करीब भाजपा नजर आई और उसी के होकर रह गए। सिंधिया के फैसला ले लेने के बाद सचिन पायलट पर भी निगाहें वैसे ही टिकी थीं, लेकिन सचिन पायलट अभी तक सिस्टम में रहकर ही हालात से जूझने के फैसले पर कायम हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत वैसे ही फूटी आंख भी नहीं सुहाते होंगे जैसे सिंधिया को कमलनाथ।

बहरहाल, राजस्थान के मामले में फिलहाल ये समझना ये जरूरी है कि अगर वास्तव में कोई खतरा है तो वो सिर्फ राज्यसभा सीटों तक ही सीमित है या फिर अशोक गहलोत सरकार पर भी है? एक जुड़ता और ज्यादा अहम सवाल ये भी है कि अगर अशोक गहलोत को लगा कि सरकार जा सकती है तो वो किस हद तक जा सकते हैं? कांग्रेस ने 110 विधायकों को दिल्ली रोड पर जयपुर के एक रिसॉर्ट में ठहराया है। विधायकों में निर्दलीय भी हैं। विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार हालिया राजनीति में **कम से कम दो स्थितियों** में जरूर हो रही है- एक, जब राज्यसभा के चुनाव होने वाले होते हैं और दो, जब किसी राज्य में सरकार बनने या बिगड़ने वाली होती है।

राजस्थान में मामला तो ऊपर से राज्यसभा चुनाव का लगता है, लेकिन क्या पता- मध्य प्रदेश में भी सारी राजनीतिक उठापटक की नींव राज्यसभा चुनाव को लेकर ही पड़ी थी। क्या हुआ और सब कैसे हुआ आपको एक-एक वाकया याद होगा ही। अभी कितने दिन हुए हैं। कुमारस्वामी तो शांत हो गए, लेकिन कमलनाथ तो पलटवार की तैयारी में जुटे हुए हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा पहुंचकर भी अपने पुराने तेवर दिखाने की कोशिश कर ही रहे थे। सवाल है कि राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियां राज्यसभा चुनाव तक ही सीमित रह जाने वाली हैं या फिर अशोक गहलोत के हाथों की लकीरें भी कमलनाथ की तरह कोई अंगड़ाई ले रही हैं?

राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने वाले हैं और 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में जीत के लिए हर प्रत्याशी को 51 वोटों की जरूरत होगी। अगर मैदान में तीन ही उम्मीदवार होते तो कोई बात ही नहीं होती, सभी निर्विरोध जीत चुके होते। चार-चार उम्मीदवारों के मैदान में उतर जाने से मामला फंस रहा है। कांग्रेस ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने राजेंद्र गहलोत के साथ-साथ ओंकार सिंह लखावत को भी अपने दूसरे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है।

विधानसभा में संख्या बल के चलते सत्ता में होने और उसके नाते कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वैसे कांग्रेस का तो दावा है कि उसे 123 विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस निर्दलियों और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी जोड़कर पेश कर रही है। भाजपा के पास 72 विधायक हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीन विधायक भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। गणित के हिसाब से जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कांग्रेस भी दो सीटें आराम से जीत जाएगी, लेकिन अगर भाजपा ने ऑपरेशन कमल जैसा कोई कमल दिखाया तो कांग्रेस के लिए राज्यसभा की सीटें जीतनी मुश्किल तो होगी ही अशोक गहलोत के भी कमलनाथ गति को प्राप्त होते देर नहीं लगने वाली है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, 'हमारे विधायक बहुत समझदार हैं... वे समझ गए। उन्हें खूब लोभ-लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन ये हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जहां एक पैसे का सौदा नहीं होता। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी धरती का मुख्यमंत्री हूं जिसके लाल बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के सरकार का साथ देते हैं कि सरकार स्थिर रहनी चाहिए राज्य में। और तभी लगे हाथ, अशोक गहलोत भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का **इल्जाम जड़** देते हैं। रिजॉर्ट में रखे गए कांग्रेस विधायकों लेकर कोई कह रहा है कि वे पॉलिटिकल क्वारंटीन में हैं तो कोई लॉक-अप रखा हुआ बता रहा है। तभी कांग्रेस सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर ट्विटर पर रणदीप सुरजेवाला के साथ एक तस्वीर में पेश होते हैं और समझाते हैं कि सब मजे में है। अशोक गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर भाजपा ने साफ-साफ कह दिया है कि किसी को पैसे का कोई ऑफर दिया ही नहीं गया है। यहां तक कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी ऐसी कोई जानकारी होने से इंकार कर रहे हैं, फिर तो सवाल उठता है कि अशोक गहलोत सरकार बचाने के नाम पर किसी और पॉलिटिकल लाइन पर काम तो नहीं कर रहे हैं?

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

निशाने पर सचिन पायलट तो नहीं?

राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भी गतिविधियां होती हैं, उसके लिए सचिन पायलट को शक की निगाह से देखा जाता है। राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें पायलट को ही टारगेट किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देखें तो राजस्थान में राज्यसभा का ये चुनाव लगभग उतना ही महत्वपूर्ण हो चला है जितना 2017 में गुजरात में हुआ राज्यसभा का चुनाव। वो चुनाव कांग्रेस नेता अहमद पटेल के चलते अहम हो गया था और ये कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के कारण। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के उतने ही भरोसेमंद हैं जितने सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल।

दरकने लगी महागठबंधन की दीवार

महाराष्ट्र में तीन दलों (शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी) के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की दीवारें दरकने लगी हैं। कांग्रेस ने पहली बार खुलकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच बीते दो दिन से अंदरखाने बैठक शुरू है लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने गुरुवार को ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की।

दरअसल, महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल होते हुए भी कांग्रेस को उतना महत्व नहीं मिल रहा है जितने की वह हकदार है। शिवसेना अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के शिल्पकार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार किसी भी मुद्दे पर आपस में चर्चा कर निर्णय ले लेते हैं जबकि कांग्रेस को इसमें शामिल करने की जरूरत भी नहीं महसूस की जाती। यही वजह है कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शामिल जरूर है लेकिन किसी निर्णय प्रक्रिया में उनके नेताओं की सलाह नहीं ली जाती। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी की हुई टेलीफोनिक वार्ता में सबकुछ ठीक होने की बात सामने आई थी। खुद ठाकरे ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस को सरकार में पूरा सम्मान दिया जाएगा।

कांग्रेस के एक मंत्री ने बताया कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि तीन दलों की सरकार में कांग्रेस को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए और सरकार की निर्णय प्रक्रिया में कांग्रेस की भी भागीदारी होनी चाहिए। इधर, ठाकरे सरकार में एनसीपी दिन-प्रतिदिन भारी पड़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं को यह खटक रहा है और इससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। इस बीच कांग्रेस के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिवसेना सचिव व मुख्यमंत्री के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के साथ बैठक की।

सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोरात व प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री से विधान परिषद की राज्यपाल नामित 12 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। लेकिन अभी तक यह बैठक नहीं हो सकी। विधान परिषद् के राज्यपाल मनोनीत 8 सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि 2 सदस्यों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा। 2 सीट इस्तीफे के चलते पहले से रिक्त हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार के गठन के समय ही यह तय हो चुका है कि तीनों दलों में से प्रत्येक को विधान परिषद् की चार-चार सीटें मिलेंगी। लेकिन अब शिवसेना पांच सीटों पर दावा कर रही है, जो कांग्रेस-एनसीपी को स्वीकार नहीं होगा।

शिवसेना नीत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में तनाव के बीच कांग्रेस सरकार में अपनी भूमिका को प्रभावी बनाना चाहती है। कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक, मुख्यमंत्री राकांपा के अध्यक्ष, शरद पवार से कोविड-19 वैश्विक महामारी और चक्रवात 'निसर्ग' से प्रभावित लोगों को राहत देने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे ऐसी भावना पैदा हो रही है कि प्रदेश कांग्रेस को अलग-थलग कर दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस हफ्ते की शुरुआत में मुलाकात कर यह चर्चा की थी कि पार्टी नेताओं एवं मंत्रियों को गठबंधन सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी मिलिंद नारवेकर भी **कांग्रेस नेतृत्व के विचारों** को जानने के लिए इस बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे थे।

उधर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच फिर एक बार टकराव हो सकता है। इस बार टकराव की आशंका 12 विधान परिषद् की उन सीटों को लेकर जताई जा रही है जो राज्यपाल के कोटे की हैं। अब तक की प्रक्रिया के मुताबिक मंत्रिमंडल की ओर से सुझाए गए नामों को राज्यपाल इन सीटों पर मनोनीत कर देते हैं, लेकिन जिस तरह की कड़वाहट हाल के वक्त में राज्यपाल और ठाकरे सरकार के बीच देखी गई उसके मद्देनजर माना जा रहा है कि राज्यपाल ऐसा आसानी से नहीं करेंगे। जब से भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं तब से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनका छत्तीस का आंकडा रहा है। जिस तरह से उन्होंने 23 नंवबर 2019 की सुबह गुपचुप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद और अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई उससे तीनों पार्टियां उनसे खफा हो गईं।

● **मुंबई से बिन्दु माथुर**

सरकार और राज्यपाल के बीच फिर टकराव

यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले का भी राज्यपाल ने विरोध किया। इस बीच भाजपा नेता नारायण राणे राज्यपाल से मिलने चले गए और राजभवन से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम साबित हुई है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उनके इस बयान से सियासी हलकों में आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं भाजपा राज्यपाल की मदद से ठाकरे सरकार को गिराने की कोई साजिश तो नहीं रच रही। विवाद तब थमा जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा का सरकार को गिराने का कोई इरादा नहीं है और सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण खुद-ब-खुद गिर जाएगी। अब राज्यपाल और ठाकरे सरकार के बीच ताजा टकराव विधान परिषद् की राज्यपाल कोटे की सीट को लेकर आशंकित हैं। कुल 12 सीटों को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस आपस में बांटेंगी और कैबिनेट के जरिए अपने उम्मीदवारों के नाम राज्यपाल को भेजेंगी। आमतौर पर इन सीटों को लिए उन लोगों को उम्मीदवारी दी जाएगी जिन्हें विधानसभा और परिषद् के चुनाव में टिकट नहीं दिया जा सका, जो दूसरी पार्टी से आए हैं और जिनका राजनीतिक पुनर्वसन करना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोश्यारी इन नामों को मंजूरी दे देते हैं या फिर ठाकरे सरकार से टकराव का तेवर अपनाते हैं।

भर्ती का भर्ता

भर्ती का भर्ता कैसे बनता है अगर आपको जानना है तो पढिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की यह कड़वी सच्चाई जिसने योगी आदित्यनाथ सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रख दी और गले की फांस बन बैठी। विपक्ष मन ही मन प्रश्न पूछता हुआ गाना गा रहा है चुनाव बहुत से लड़े होंगे तुमने, मगर कोई भर्ती भी तुमने करी है? सिलसिला शुरू होता है उत्तरप्रदेश में भाजपा की सरकार के आने से। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा सरकार बहुमत से आई। और उसने आते ही कुछ दिनों के भीतर प्राइमरी में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों के पदों को अवैध घोषित कर दिया और उनको निकालने की ठानी। भाजपा के प्रदेश में आने से बहुतों के जीवन में खुशी की लहर आ गई थी। पर कुछ चेहरे गम में भी डूब चुके थे। गाना था आने से उसके आए बहार, पर शिक्षामित्रों के मन में चलने लगा जाने से उसके आए बहार।

शिक्षामित्रों के समुदाय में लगभग भूचाल सा आ गया। सनद रहे कि शिक्षामित्रों का समायोजन समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। और भाजपा को विरोध करने का एक अच्छा मौका मिल चुका था। क्योंकि शिक्षामित्र 12वीं पास की योग्यता से लिए गए थे जो कि एनसीटीई के नियमों के खिलाफ था। अर्थात उसमें कहीं भी इनके स्थायी पद का जिक्र नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए योगी सरकार ने शिक्षामित्रों को पद से हटा दिया और कहा 'हमें योग्य शिक्षक चाहिए। इसी भर्ती में शिक्षामित्रों का नेता रिजवान अंसारी उभरकर आया, उसके नेतृत्व में शिक्षामित्रों ने कई केस व आंदोलन किए। बहुत से शिक्षामित्र (लगभग 90 प्रतिशत) 10 साल से अधिक साल तक प्राइमरी में अध्यापन कार्य कर रहे थे। बहुतों की शादी भी इसी पद को स्थायी समझकर हुई थी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि **दहेज एक कुप्रथा** है परंतु शिक्षामित्रों ने अपने पद के नाम पर लाखों का दहेज लेकर शादी कर ली थी और इस कांड से उनकी इज्जत दांव में लग गई। गली, मोहल्ले, गांव, और शहर से इनमें तानों की बौछार सी होने लगी। शिक्षामित्रों के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि, 'अब जाएं तो जाएं कहां? करें तो करें क्या?'

सुप्रीम कोर्ट के पास शिक्षामित्र गुहार लगाने गए। जहां कोर्ट ने इन्हें 10 हजार मासिक सैलरी में बने रहने को कहा। परंतु शिक्षामित्रों की सैलरी एक प्राइमरी अध्यापक की सैलरी के बराबर हो चुकी थी अर्थात् लगभग 40 हजार से भी अधिक। ऐसे में 10 हजार रुपए मासिक में गुजारा करना उन्हें मुश्किल लगा। शिक्षामित्रों ने पुन: अपील की। और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को 2 मौके दिए। इन दो मौकों में शिक्षामित्रों को दूरस्थ संस्थान से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) करके टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) अर्थात् शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना था। उसके बाद प्राथमिक स्तर के अध्यापक के लिए निकलने वाली भर्तियों में सम्मिलित होकर उसे उत्तीर्ण करना था। साथ ही शिक्षामित्रों को 25 भारांक भी दिया गया। जो तभी जोड़ा जाएगा जब वो परीक्षा की कटऑफ पार कर लेंगे। 2017-18 में 68500 प्राइमरी शिक्षक के पद निकले। जिसमें बीटीसी/डीएलएड किए हुए प्रशिक्षु और शिक्षामित्र सम्मिलित हुए। पदों की संख्या 68500 थी और प्रतियोगियों की संख्या 1 लाख 10 हजार लगभग थी। परीक्षा परिणाम आया और 150 अंक की लिखित परीक्षा में कट ऑफ लगाई गई 40 और 45 प्रतिशत। अर्थात् आरक्षण वर्ग के लिए 40 प्रतिशत यानि 60 अंक और अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत यानी 65 अंक। इस कट ऑफ को पार करने वाला हर प्रतिभागी शिक्षक बनने योग्य माना गया। 68500 पदों में 40-45 प्रतिशत की कटऑफ पर 45 हजार लगभग लोग ही पास हो पाए। और एक बार फिर से योगी जी का बयान आया उत्तरप्रदेश में योग्य शिक्षकों की कमी है। वर्ष 2019 आया। 6 जनवरी को अगली परीक्षा 69000 प्राथमिक अध्यापकों की हुई। पर ये भर्ती 68500 से कुछ अलग थी। इसकी वजह थी इसमें बीएड को शामिल करना। हालांकि बीएड किए हुए छात्राध्यापक बड़ी कक्षा में पढ़ाने के योग्य माने जाते हैं। उनको प्राथमिक में पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का अलग मनोविज्ञान होता है और बड़ी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का अलग। परंतु सरकार बीएड अभ्यर्थियों हेतु पद निकालने में सक्षम नहीं थी।

इसे सरकार की नाकामी या असफलता ही कहा जाएगा कि 7-8 सालों में बीएड हेतु कोई पद ही न निकले थे। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को नौकरी हेतु प्राइवेट विद्यालयों में जाना पड़ता था। सरकार ने इस 69000 भर्ती में बीएड को भी योग्य घोषित करते हुए जगह दे दी। परंतु बीएड को ये कहा गया कि जॉइनिंग के सालभर के भीतर उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। जिससे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने हेतु पूर्ण योग्य होंगे। परीक्षा की आंसर की आई और साथ ही अबकी बार कटऑफ 60 और 65 प्रतिशत कर दी। इसकी वजह थी कि इस बार भाग लेने वाले परीक्षार्थी 4 लाख से भी ज्यादा थे। ऐसे में 40 और 45 प्रतिशत कटऑफ लगाना, मतलब बेवजह लोगों को उम्मीद देना कि आप चयनित हो सकते हैं और इसमें योग्यता भी कम हो जाती।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

इस वजह से शिक्षामित्रों को जाना पड़ा फिर से कोर्ट

अब शिक्षामित्रों का कॉम्पिटीशन बीएड और बीटीसी दोनों से था। और परीक्षा के शुरुआत में कटऑफ का कोई जिक्र न होने की वजह से कुछ ने यह सोच लिया कि हम कुछ भी करके आ जाएंगे 25 भारांक तो मिलना ही है। और कुछ ने सोचा 40 और 45 प्रतिशत कटऑफ के हिसाब से पास होने भर का कर लिया जाए। मन में बस यही चल रहा था एक नौकरी चाहिए, जिंदगी के लिए। पर जब कटऑफ 60 और 65 प्रतिशत लगी तो शिक्षामित्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और रिजवान अंसारी के नेतृत्व में वो कोर्ट गए। और सिंगल बेंच में फैसला उनके हक में अर्थात् 40 और 45 प्रतिशत कटऑफ में आ भी गया। पर सरकार डबल बेंच गई और फिर वकीलों की दलीलों के बाद फैसला 60-65 प्रतिशत कटऑफ का यहां से आया। वकील कई थे जिनमें बीएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं ने चंदा इकट्ठा करके खुद के वकील अलग से भी कर रखे थे। उधर टीम रिजवान अंसारी ने भी मजबूत वकील कर रखे थे। महीनों ये सब चला और लगभग डेढ़ साल होने को आए हैं। पर सरकार भर्ती कराने में नाकाम रही है। संशोधित उत्तर कुंजी, परीक्षा परिणाम और चयनित सूची आने के बाद फिर से भर्ती की प्रक्रिया रुक गई।

भाजपा का नीतीश प्रेम

आलाकमान कल्चर

समस्या ये नहीं है कि कोई ऐसा योग्य चेहरा नहीं है, जिसे पार्टी सामने ला सके। समस्या ये है कि भाजपा किसी को घोषित करना नहीं चाहती। अगर पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को सामने करती है, तो काफी कुछ श्रेय उस चेहरे को चला जाएगा। और कांग्रेस के हाईकमान कल्चर की तरह, मोदी-शाह भी कोई इलाकाई क्षत्रप पैदा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हर चुनाव की जीत मोदी के नाम हो और जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। नीतीश कुमार को छोड़कर मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव लड़ना, भाजपा के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। और फिलहाल वो जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। भाजपा ये कर सकती है कि चुनावों के बाद कोई सरप्राइज दे सकती है। बिहार को संबोधित एक 'वर्चुअल रैली' में अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को, दो-तिहाई बहुमत के साथ जीत हासिल होगी। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा और रामविलास पासवान की एलजेपी के पास मिलकर इतनी सीटें हो सकती हैं कि वो एक भाजपा मुख्यमंत्री बिठा सकते हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि चुनाव 'नीतीश कुमार की अगुवाई में' लड़ा जाएगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला, सीटों के बटवारे में हो सकता है। भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो नीतीश कुमार को अपने से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने दे। सौदेबाजी की अपनी बढ़त के साथ भाजपा सुनिश्चित करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों पर लड़े और मुश्किल सीटों पर जेडी(यू) को लड़ने दे।

एक बार फिर भाजपा ने कहा है कि बिहार में गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। खासकर गृहमंत्री अमित शाह इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। उनका इसे बार-बार कहना ही, अपने आप में मायने रखता है। अमित शाह को ये कहते रहना पड़ता है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक वास्तविकता ऐसी है कि किसी को आश्चर्य नहीं होगा, अगर भाजपा नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ने का फैसला कर ले और अंत में बिहार को एक भाजपा मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन बिहार को एक भाजपा मुख्यमंत्री देने की अमित शाह की अनिच्छा, ताज्जुब में डालती है क्योंकि उन्हें एक आक्रामक खिलाड़ी माना जाता है, जो आगे निकलकर बैटिंग करता है। इसके लिए सामान्य रूप से दिए जा रहे स्पष्टीकरण समझ में नहीं आ रहे। नहीं, नीतीश कुमार का जेडी(यू), और लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), एक बार फिर वापस नहीं आ सकते। याद है कि दोनों कितनी बुरी तरह अलग हुए थे? न तो वो एक-दूसरे पर भरोसा करेंगे, और न ही जनता उन पर एकसाथ भरोसा करेगी।

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय की धमकी, आरजेडी और जेडी(यू) दोनों को, इस बार भाजपा को हराने की कोशिश नहीं करने देगी। आखिरकार, नीतीश कुमार को भी एक तथाकथित सृजन घोटाले की चिंता करनी है। नहीं, नीतीश कुमार बिहार में अजेय नहीं हैं। 2020 का साल, 2010 की तरह नहीं हैं। बतौर नेता उनका कद घट चुका है, और तीसरे कार्यकाल में हर साल, उनकी राजनीतिक पूंजी कम ही हुई है। नीतीश कुमार अभी तक खेल में बने हुए हैं तो सिर्फ इसलिए, कि उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। युवा तेजस्वी यादव अभी तक निष्क्रियता दिखाने में ही चैम्पियन साबित हुए हैं। टीना (कोई विकल्प नहीं) फैक्टर को छोड़ दें, तो बिहार के लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं। आप इसे पटना की गलियों में, गंगा के पुलों पर, सीमांचल के गांवों में, हर जगह **सूंघ सकते** हैं। हवा में बदलाव है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा।

भाजपा ही वो पार्टी है जो चुनौती देने वाले विपक्ष की जगह भर सकती है। भाजपा के लिए सही समय है कि नीतीश कुमार को छोड़ दे, और हवा का रुख भांपने वाले, लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के रामविलास पासवान जैसे छोटे सहयोगियों के साथ, अकेले दम पर बिहार चुनाव लड़े। अकेले खड़े होने में भाजपा को एक डर सता सकता है- गैर-यादव ओबीसी वोट। बिहार में भाजपा को अगड़ी जातियों की पार्टी के रूप में देखा जाता है, और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार, गैर-यादव ओबीसी वोटों, खासकर ईबीसी (अति पिछड़े वर्ग) के वोटों के प्रतीक की हैसियत से अहमियत रखते हैं, जिस वर्ग को उन्होंने खुद पैदा किया है। इस पुराने हिसाब में इस सच्चाई को अनदेखा किया जाता है, कि भाजपा काफी लंबे समय से, ईबीसी वोट पर काम कर रही है और 2015 में विधानसभा चुनाव हारने के समय भी, उसने इस वर्ग से अच्छे खासे वोट लिए थे। सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। जिस तरह पंजाब में एक आम राय है, कि मुख्यमंत्री सिख होना चाहिए और वो भी जाट, उसी तरह बिहार सियासत में भी एक आम सहमति है, कि मुख्यमंत्री किसी ओबीसी समुदाय से होना चाहिए। भाजपा **विरोधी ओबीसी** मतदाताओं से कहते हैं कि भाजपा किसी ऊंची जाति वाले को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाकर, अगड़ी जातियों का दबदबा कायम करना चाहती है। आखिरकार, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में यही नहीं किया?

इस समस्या का एक सीधा सा समाधान है। एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, जो ओबीसी कम्युनिटी से हो। ये समझ में आता है कि शायद भाजपा उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना नहीं चाहेगी। वो भले ही काबिल हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में मजाक किया जाता है कि वो भाजपा के भीतर जेडी(यू) के नुमाइंदे हैं। अगर भाजपा कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना चाहती है, तो उसके पास चेहरों की कमी नहीं रहेगी। पार्टी ने नित्यानंद राय को एक ओबीसी नेता के तौर पर तैयार किया और वो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय में अमित शाह के कनिष्ठ सहकर्मी हैं। वो एक यादव हैं। भाजपा के पास काफी समय है एक ऐसा लीडर तैयार करने का, जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार्य हो और नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ रही सत्ता-विरोधी भावना को देखते हुए, एक नए चेहरे को जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा।

● **विनोद बक्सरी**

आक्रामकता नहीं छोड़ेगा चीन

चीन के कद को घटाने के लिए ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश की थी

अमेरिका ने भी चीन के आक्रामक होते जा रहे तेवरों से निपटने की जरूरत जताई है। चीन के कद को घटाने के मकसद से मौजूदा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इस पेशकश को खारिज कर दिया। दोनों देशों के बीच भले ही हाल में तनाव बढ़ा हो, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इसे सार्थक बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई कि इसे बड़े विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। वैसे एशिया की इन दो बड़ी शक्तियों के बीच सीमा को लेकर यह न तो पहला और न ही आखिरी गतिरोध है। इसे लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक नजरिए हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वास्तविकता यही है कि चीन के उभार के साथ ही भारत भी खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। दोनों देशों समेत पूरी दुनिया को भविष्य में और बड़े संघर्षों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानि एलएसी पर हालिया तनातनी के बाद गत दिनों दोनों पक्षों के बीच साढ़े पांच घंटे की वार्ता भी हो गई जिसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के बीच करीब 3,488 किलोमीटर में फैली एलएसी का उचित सीमांकन नहीं हुआ है जिस कारण यह दोनों देशों के बीच यदाकदा अदावत का अखाड़ा बन गई है। हालांकि इस साल तल्खी को नया आयाम मिला जब दोनों देशों ने लद्दाख के दुर्गम और ऊंचे इलाकों में यकायक अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया। अब भले ही दोनों देश सैन्य-कूटनीतिक स्तरों पर समाधान में जुटे हों, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच महीनेभर से अधिक कड़वाहट भरी टकराव जारी रही। भारत ने शुरुआत में इसे अधिक तूल नहीं दिया, लेकिन मई के अंत में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया कि पूर्वी लद्दाख के भीतरी इलाकों में भारी संख्या में चीनी सैनिक जमा हो गए। उनके बयान ने यह भी दर्शाया कि हालात से निपटने के लिए भारत ने जरूरी कदम उठाए।

वर्ष 2017 में 73 दिन चले डोकलाम गतिरोध के बाद यह दोनों देशों के बीच पैदा हुआ सबसे तल्ख मसला है। अबकी बार इसकी चिंगारी मई की शुरुआत में तब सुलगी जब लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में दोनों पक्ष के सैनिक हिंसक संघर्ष में उलझ गए। कुछ दिन बाद सिक्किम के नाथू ला में भिड़ंत की खबरें आईं। यह आग कुछ बुझी तो मालूम पड़ा कि भारत पैंगोंग त्सो के जिस इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है वहां चीन ने न केवल अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी, बल्कि अपनी निर्माण गतिविधियां भी तेज कर दीं। जवाब में भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। भारत और चीन के बीच मौजूदा तनातनी को स्थानीय पहलुओं के चश्मे से भी देखा जा सकता है। दोनों पक्ष एलएसी के इर्द-गिर्द बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहे हैं। भारत पैंगोंग त्सो के साथ ही गलवन घाटी में दार्बुक-शायोक-दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क भी बना रहा है। इसे ही चीन की त्योरियां चढ़ने का तात्कालिक कारण माना जा रहा है।

मौजूदा घटनाक्रम में दिलचस्प पहलू यही है कि यथास्थिति में बदलाव को लेकर अभी तक भारत चीन के सामने शिकायत करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है। गत वर्ष भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के दर्जे में बदलाव कर लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से विलग करने के बाद परिदृश्य बदल गया। हालांकि भारत ने स्पष्टीकरण दिया था कि इससे एलएसी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर भी चीन ने इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक में आवाज उठाई, लेकिन वह अपनी मुहिम में सफल न हो सका।

असल में बीजिंग को अंदेशा है कि अब भारत अक्साई चिन के उस 37,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर भी दावा कर सकता है जिस पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। लिहाजा चीन के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बढ़ गई है। यही कारण है कि एलएसी और एलओसी पर बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहे भारत के प्रयासों में चीन अड़ंगा लगा रहा है, क्योंकि इससे भारत को सामरिक मोर्चे पर बढ़त हासिल होगी जो चीन कभी नहीं चाहेगा। इससे चीन की बीआरआई और सीपैक जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। ऐसे में भारत जहां अपने मोर्चे को मजबूत बना रहा है वहीं बीजिंग इसी कोशिश में है कि किसी तरह यथास्थिति बनाई रखी जाए।

इस बीच यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस विवाद ने उस समय दस्तक दी जब चीन कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। दक्षिण चीन सागर से ताइवान, हांगकांग से लेकर अमेरिका के साथ व्यापार **युद्ध जैसे तमाम पहलुओं** पर चीनी विदेश नीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। वहां घरेलू तनाव बढ़ रहा है। सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि और कोरोना महामारी से लचर तरीके से निपटने को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। वास्तव में समस्याओं से ध्यान भटकाने और राष्ट्रवाद की भावना को गति देने के लिए सैन्य तौर-तरीकों का इस्तेमाल तानाशाही शासकों का सबसे आम नुस्खा होता है। ऐसे में चीनी नेताओं को यही लगता है कि जब पूरी दुनिया और खुद चीन कोविड-19 के झटके से उबरने में लगा हुआ है तब यही वक्त भौगोलिक सीमा के विस्तार के लिहाज से सबसे मुफीद है। इधर, भारत भी बीजिंग के कदमों को लेकर नाखुशी जाहिर करने में अधिक मुखर हुआ है। ट्रंप जैसे तुनकमिजाज राष्ट्रपति के दौर में भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध और बेहतर होते गए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे समान विचारों वाले साथियों के साथ भारत अपनी सक्रियता से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति को नई दिशा देने में जुटा है। हाल के दिनों में नई दिल्ली के कई कदम चीन को चुभे होंगे। जैसे भारत ने हाल में चीनी निवेश के लिए नियमों को सख्त बना दिया। उसने कोरोना को लेकर चीन की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग कर रहे देशों का समर्थन किया। वहीं दो भारतीय सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा भी लिया। ऐसे में सीमा विवाद के जरिए चीन की मंशा भारत पर कुछ बढ़त हासिल करने की भी हो सकती है।

● **कुमार विनोद**

सत्ता नहीं, जनता सर्वोपरि

चुनाव की दहलीज पर खड़ा अमेरिका इन दिनों आमजन के गुस्से की लपटों से घिरा है। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान देकर 'गुस्से की आग' को और हवा दे दी। हालांकि ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख आर्ट एसिविडो ने ट्रंप के बयान पर आपत्ति जताते हुए साफ कहा, 'अगर आपके (ट्रंप के) पास मुद्दे से निपटने का कोई अच्छा सुझाव नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखें।' एसिविडो हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के 150 से अधिक शहर हिंसा की चपेट में हैं। करीब 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तक अरबों डॉलर की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। अनेक लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों की लपटों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के 28 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में 21 हजार के करीब सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

असल में, हिंसा तब भड़की, जब अफ्रीकी मूल के अमेरिकी निवासी 46 वर्षीय एथलीट जॉर्ज फ्लॉयड के प्रति एक पुलिस अधिकारी की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ। श्वेत पुलिस अफसर **डेरेक चौविन ने फ्लॉयड** को जमीन पर पटका और उसकी गर्दन पर घुटना रख दिया। फ्लॉयड का दम घुटता रहा और अफसर की क्रूरता जारी रही। एक राहगीर ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। फ्लॉयड की मौत और वीडियो के वायरल होने के बाद जनता भड़क गई। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से उठीं गुस्से की लपटें वाशिंगटन स्थित 'व्हाइट हाउस' तक पहुंच गईं। मामला इस कदर गंभीर हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष तौर पर तैयार बंकर में पहुंचाना पड़ा। कोरोना महामारी के दौर में बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क पहने हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को सकते में डाल दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की तुलना फासीवादियों से कर डाली और प्रभावित शहरों में सेना तैनात करने की चेतावनी भी दे दी।

बेशक, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता और प्रदर्शन की आड़ में लूटपाट की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन जनता के उस बड़े वर्ग की चिंता को समझना सरकार की जिम्मेदारी है जो भेदभावपूर्ण व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का संदेश दे रहा है। अमेरिका में रंगभेद हिंसा का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी, कभी छिटपुट तो कभी बड़ी वारदातें हुई हैं। इस वक्त पुलिस अफसर की क्रूरता के बाद जिस तरह से पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे अमेरिकी सरकार पर धब्बा तो लगा है। हालांकि कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो अमेरिका को थोड़ा अलग बनाती हैं। फ्लॉयड की मौत के इस मामले में वहां न सिर्फ तमाम अमनपसंद लोगों ने प्रतिक्रियाएं दीं, बल्कि संस्थानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आरोपी अफसर चौविन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन पर थर्ड-डिग्री के इस्तेमाल और हत्या का आरोप लगाया गया, जिससे उन्हें 35 साल तक की कैद हो सकती है।

दरअसल, हिंसा के दौर में राष्ट्रपति ट्रंप को भी जनता की भावनाओं को समझना चाहिए था और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। ट्रंप की बयानबाजी के बीच ह्यूस्टन पुलिस के प्रमुख आर्ट एसिविडो एक नायक के रूप में उभरे हैं जो ऐसी स्थिति में दिल जीतना जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को मुद्दे का सही हल तलाशने तक चुप रहने के लिए कह दिया। बहरहाल, ट्रंप दुनिया के सबसे 'ताकतवर' राष्ट्र की सत्ता पर तो काबिज हो गए, लेकिन ऐसे नाजुक मौकों पर उन्हें अपने इस पुलिस अफसर से सीखना चाहिए कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामले से कैसे निपटा जाना चाहिए। कमोबेश **यही संदेश** अन्य देशों के उन नेताओं के लिए भी है जो सत्ता सौंपने वाली जनता को, सत्ता पर काबिज होने के बाद या तो भूल जाते हैं या फिर विरोध करने के उनके अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं। सत्ता के मद में जनता को भूलने वालों का हश्र भी दुनिया ने देखा है।

अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वे देश में विभाजन की आग भड़का रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह हालिया घटनाओं को हैंडल किया है, उससे वे नाराज हैं और आश्चर्यचकित भी हैं। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 'ओवररेटेड जनरल' की संज्ञा दी और कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मैटिस ने अपना पद छोड़ दिया था।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

काले लोगों के साथ किस तरह होता है दुर्व्यवहार

अमेरिका में काले लोगों के साथ अधिक ज्यादती होती है। मौजूदा आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पुलिस की गोली से मारे जाने के मामले में अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों की तादाद उनकी अमेरिका में कुल आबादी के अनुपात में अधिक है। आधिकारिक आकड़ों के मुताबिक, 2019 में अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों को संख्या अमेरिका की कुल आबादी का 14 फीसदी है। 23 फीसदी से ज्यादा मामलों में अफ्रीकी-अमेरिकी पुलिस की गोली का शिकार बनते हैं और संख्या के हिसाब से यह करीब 1000 मामलों से थोड़ा ज्यादा होता है। 2017 से लगातार यह आकड़ें बने हुए हैं जबकि पुलिस की गोली से मारे जाने वाले गोरे लोगों की संख्या में तब से गिरावट आई है। गोरे लोगों की तुलना में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार होने वाले अफ्रीकी-अमेरिकियों की दर कहीं ज्यादा है जबकि सर्वे में यह बात सामने आई है कि दोनों ही समुदायों में ड्रग्स का इस्तेमाल समान स्तर पर ही होता है। 2018 में करीब प्रति एक लाख अफ्रीकी-अमेरिकियों पर 750 लोग ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुए थे जबकि इसकी तुलना में गोरे अमेरिकी सिर्फ 350 ही थे। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए पिछले सर्वे में यह बात सामने आई थी कि गोरे लोग उसी स्तर पर ड्रग्स का सेवन करते हैं जितने की अफ्रीकी-अमेरिकी लोग। लेकिन गिरफ्तारी के मामले में अफ्रीकी-अमेरिकियों की दर अधिक है। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन के अध्ययन में पाया गया है कि मारिजुआना रखने के आरोप में अफ्रीकी-अमेरिकी लोग 3.7 गुना गोरे की तुलना में अधिक गिरफ्तार हुए हैं भले ही मारिजुआना के सेवन के मामले में दोनों लगभग बराबर ही थे।

लॉकडाउन की लाइफ लाइन

महिलाएं दुनिया में लॉकडाउन की सफलता का आधार बनकर मजबूत संचालक शक्ति के रूप में उभरी। बावजूद इसके कि लॉकडाउन का महिलाओं के जीवन पर हर तरह से बुरा असर पड़ा है। इस दौरान दुनियाभर में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई। महिलाओं पर पारिवारिक हिंसा की घटनाएं अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, चीन, स्पेन, इटली और भारत समेत सब जगह बड़े स्तर पर दर्ज हुई हैं। परिणाम महिलाएं लॉकडाउन के दौरान भारी मानसिक दबावों में जीने को मजबूर रही। ऊपर से महामारी का भय अभी भी बराबर बना हुआ है। महिलाएं अपने परिवार के प्रति बहुत सरोकारी स्वभाव रखती हैं। इसी प्रवृत्ति के चलते अपनी और अपने परिजनों की चिंता उन्हें और भी गहरे अवसाद में धकेल रही है।

पूरी दुनिया के काम भले ही थम गए हों और पहले से कम हो गए हों, पर महिलाओं के काम तो घर में रहते हुए भी कई गुना बढ़े हैं। घर के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। लॉकडाउन के दौरान उन पर पहले से भी ज्यादा काम का बोझ आया है। वास्तव में तो सफल लॉकडाउन की आधारशिला महिलाएं ही बनी हैं। काम के दोहरे दबावों के बीच घर में मौजूद पुरुषों के बेतुके बयान व सलाहें, छोटे बच्चों की उलूल-जुलूल मांगें और बुजुर्गों की अतिरिक्त अपेक्षाएं। इन सबने मिलकर महिलाओं की दिनचर्या को अतिरिक्त दबावों और कार्यों से बेहद बोझिल बना दिया। इससे स्पष्ट है कि लॉकडाउन की लाइफलाइन महिलाएं ही बनी हैं। यहां तक कि जो महिलाएं घरेलू कामकाज तक सीमित थीं उनके संकट भी **कोरोना संकट के साथ गुणात्मक रूप** में बढ़े हैं। चूंकि लॉकडाउन के कारण घर में काम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। परिणाम उनके कामकाज के घंटे लगभग दोगुने हो गए हैं।

दुनिया में अचानक आए इस संकट से लोगों के काम-धंधे चौपट हुए हैं तो उनके मानसिक तनाव बढ़ेंगे ही, लोग आर्थिक दबाव में आएंगे ही। जिसके परिणाम समाज में बढ़ते तनाव, अवसाद और अपराधों में उभरकर सामने आ रहे हैं। घरेलू हिंसा का बढ़ना इसी क्रम का एक अपरिहार्य परिणाम मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं। पर यह बात मनोवैज्ञानिकों की मान भी ली जाए तो भी, एक बड़ा और गंभीर सवालिया निशान तो सभ्य समाज पर है ही, कि क्या पुरुष अकेले इस संकट का सामना कर रहे हैं? क्या यह खतरा घर में दुबके बैठे सिर्फ पुरुषों पर ही है? क्या ऐसी महामारी में भी पुरुष-वर्ग महिलाओं के प्रति संवेदनशील सोच नहीं रखता है? क्या महिलाएं इंसान नहीं है? ये तमाम वे मौजूं सवाल हैं जो आज के तथाकथित 21वीं सदी के आधुनिक कहे जाने वाले सभ्य समाज के गले में अटके हैं।

हिंसा का आंकड़ा बढ़ा

पूरी दुनिया में महामारी से उपजे इस संकट के दौरान देखने में आया है कि बच्चों में बढ़े चिड़चिड़ेपन की सारी खपत मां के आंचल में ही होती है। दुनिया के मर्द परिस्थितियों से उपजे तनाव और गुस्से की जकड़न में मूर्छित है। यहीं उसके हजार दुखों की एक बड़ी वजह है। जिसके चलते परिवार के परिवार परेशान हैं। दुनिया में महिला हिंसा का आंकड़ा इसी मर्दवादी हीन-ग्रंथि की विष-बेल से बढ़ता है। दुनिया में इस लॉकडाउन को जिन कुछ नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए याद रखा जाएगा। उनमें सांप्रदायिकता का सवाल सबसे ज्यादा सालने वाला होगा। वहीं नस्ल, जाति और वर्गीय भेदभाव के वीभत्स दृश्य सभ्य विश्व-समाज पर बड़े सवालिया निशान छोड़ गए हैं। लॉकडाउन ने एक बार फिर तथाकथित सभ्य समाज की उन सिलाईयों को उधेड़ फेंका है जो पुरुष वर्चस्व वाली दुनिया में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक रवैए और महिला विरोधी सोच के घटिया व्यवहार को अक्सर कवर किए रखती है। इस कड़वी सच्चाई को सतह पर लाने का काम भी कोविड-19: लॉकडाउन ने बखूबी किया। पितृसत्तात्मक सोच पुरुषों की धमनियों में लहू के साथ बहती है, यह एक बार फिर जगजाहिर हुआ। आधुनिक सभ्यता का यह कलंकित कोना महिलाओं के प्रति हिंसक वारदातों के अंबार के आर्काइव्ज की तरह इन घटनाओं के घटित होने के प्रमाण सहेज रहा है। साथ ही उस सकारात्मक योगदान के लिए भी महिलाएं ही बढ़त बनाए हुए हैं।

चीन में तो लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा की घटनाओं में तीन गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं स्पेन की सरकार महिलाओं को हिंसा से बचने के अजीब-अजीब तरीके सुझा रही है कि महिलाएं हिंसा के समय स्वयं को बाथरूम में बंद कर लें। इटली सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्देशित किया कि चौबीसों घंटे महिलाओं की काउंसिलिंग और सहायता के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध कराएं, सरकार इसके लिए तत्पर है। फ्रांस ने तो इस संकट को बढ़ता देख और हिंसा को हद से गुजरता देख, फ्रांसिसी महिलाओं के लिए यहां तक किया कि अगर महिलाएं पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत न जुटा पाएं तो उनके लिए एक गुप्त कोड की व्यवस्था की गई है।

महिलाएं पास के किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर मास्क-19 मांग ले बस। अगर वे अपने ऊपर हुई किसी भी तरह की हिंसा या यातना का सामना कर रही हैं तो, मास्क-19 सुनते ही केमिस्ट की यह जिम्मेदारी है कि उस पीड़ित महिला की घरेलू हिंसा से रक्षा-सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। महिला हिंसा के निरंतर बढ़ते मामलों को देख स्पेन सरकार ने भी इस मॉडल को अपने यहां अपनाने का फैसला लिया। दुनियाभर में इतना लंबा लॉकडाउन महिलाओं के कंधों पर सवार होकर सफल होने की तरफ बढ़ रहा है पर शर्म की बात यह है कि महिला हिंसा का ग्राफ भी उसी के समानांतर बढ़ा है। यह सत्य है कि लॉकडाउन की सफलता का मुख्य आधार महिलाएं ही है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

कर्म से अंदर की निर्बलता को पहचाने

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।

श्रीमद्भगवदगीता मानव से कहती है कि तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, उसके फल में नहीं। और तुम्हारा साथ अकर्म में भी न हो, यानी यह सोचकर भी मत बैठ जाओ कि कर्म करने से क्या लाभ इसलिए कर्म को ही त्याग दूं। कथा में कथ्य क्या है? किसी देश, काल और संस्कृति के साहित्यिक आख्यान का ध्येय उस समय को दिशा देना होता है। महाभारत जैसे महाकाव्य के कहने को आज हम फिर कैसे और क्यों कहें?

गीता का केंद्रीय संदेश है, बिना फल की चिंता किए कर्म करना। लेकिन ज्ञानदाता खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे अर्जुन को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो सामने खड़े हैं इनके कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए इन्हें इसका दंड मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। इनके कर्म बुरे हैं तो इनका वध होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन बीच में जाकर खड़े होते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ पितामह, गुरु और भाई ही दिखते हैं। लेकिन गीता-ज्ञान के बाद वो सिर्फ कर्म के मोहरे हैं जिन्हें अर्जुन से दंडित होना है।

आज का समाज जिस आपराधिक दंड संहिता से नियमबद्ध है उसका आधार इस पौराणिक आख्यान में देख सकते हैं। कर्म के अनुपात में फल। बुरे कर्म वालों को माफी देने का मतलब है बाकियों को भी उस तरफ लेकर जाना। जब भरोसा हो जाएगा कि किसी की भी मर्यादा का हरण करने वाले को बाद में माफ कर दिया जाएगा तो फिर **मर्यादा का ही अस्तित्व** खत्म हो जाएगा। अगर आप तटस्थ रहेंगे और उसके बाद भी आपके मान-सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी तो कुछ भी कर निर्भय रहने की प्रवृत्ति ही आगे जाएगी। लेकिन गीता का ज्ञान देने वाले ने ही इसका विरोधाभासी रूप प्रस्तुत किया।

महाभारत का आख्यान शुरू होता है राजा भरत के लोकतांत्रिक स्वरूप से। जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म को मानते हुए उन्होंने अपने पुत्रों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। राजा भरत खुद को प्रजा के पालक के रूप में देख रहे थे तो राज्य का वारिस भी उनके बीच में से एक को चुना। अपने पुत्र को ही सत्ता सौंपना प्रजा के साथ विश्वासघात होता। राजा भरत ने जो धर्मक्षेत्र बनाया वह शांतनु के आत्ममोह और आगे जाकर पुत्रमोह और भाई-भतीजावाद के कारण कुरुक्षेत्र बन गया। भरत के आदर्श के खिलाफ भरतवंश से मांग उठी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब कर्म नहीं, जन्म ही राज और समाज के नियम तय कर रहा था। उसमें भी धृतराष्ट्र के जन्म के आधार को इसलिए कुचला गया क्योंकि वे नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र इसलिए नेत्रहीन पैदा हुए क्योंकि नियोग विधि के वक्त उनकी माता ने वेदव्यास के कठोर तप के कारण कठोर हुए चेहरे को देख डर के मारे आंखें बंद कर ली थीं। धृतराष्ट्र का जन्म अपनी मां की प्रकृति के अनुसार हुआ लेकिन ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद उनकी इस प्राकृतिक कमी को स्वीकारा नहीं गया। यानि जन्म और कर्म दोनों के साथ सुविधाजनक तरीके से घालमेल कर कुरुक्षेत्र के मैदान का निर्माण शुरू हो गया था। धर्म और अधर्म का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था और दोनों अपने रूप बदल रहे थे।

धृतराष्ट्र को ग्लानि रही कि नेत्रहीनता के कारण उनके जन्म के अधिकार को छीना गया। अब वे अपने बेटे को राजा देखना चाहते थे। उनके इस पुत्र-मोह को अधर्म की संज्ञा दे जो धर्मक्षेत्र बनाया गया उसमें भरत के आदर्श का भारत नहीं बल्कि उसी सामंती सत्ता की स्थापना हुई कि राजा का बेटा राजा। धृतराष्ट्र की जगह पांडु पुत्रों के मोह और अधिकारों की स्थापना हुई।

महाभारत के युद्ध में जीत के बाद युधिष्ठिर महाराज बने और भीम युवराज, अर्जुन हस्तिनापुर की सीमाओं के प्रहरी। नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के मुख्य अंगरक्षक बने। पांडु पुत्रों तक ही सत्ता सीमित कर भाई-भतीजावाद की मजबूत बुनियाद पड़ी। विदुर को महामंत्री बनाया गया जो हमेशा से पांडवों के साथ थे। यानि युद्ध के बाद आप उसी की स्थापना कर रहे थे, जिसे खत्म करने के लिए आपको बनाया गया था। भगवान के धरती पर अवतार का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना करना था। लेकिन संदेश दिखा कि एक की पितृसत्ता की जगह आप दूसरी पितृसत्ता लाना चाहते थे। पांडु के पुत्रों के नैसर्गिक अधिकार को ही शुद्ध और धर्मसम्मत माना गया। महाभारत के कई प्रसंगों में भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र-मोह को कोसते हैं। लेकिन वे उसके विकल्प में एक और मोह ही देते हैं।

महाभारत का वृहत्तर संदेश युद्ध के परिणाम में नहीं है। यह संदेश युद्ध के दौरान दिखाई गई निर्बलता में है, जिसे बलीभूत करने के लिए कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। महाभारत को हम इसलिए नहीं जानते हैं कि इसके द्वारा किसी सामंती सोच या सामाजिक बुराई को खत्म किया गया। कथा का कथन यही है कि हमें कर्म करना है, अपने अंदर के निर्बल को पहचानना है। महाभारत में अलग-अलग समय और जगह का पाठक अपने-अपने धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र तलाशता है। रचने वाले और पढ़ने वाले के बीच युद्ध के बाद हर बार जो एक नई महाभारत बनती है वहीं पर साहित्य सार्थक होता है।

● **ओम**

खुदकुशी

कवियत्री जी की पुस्तक जिसका शीर्षक 'खुदकुशी' है, का विमोचन कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी उनसे एक पत्रकार प्रश्न पूछता है, 'कवियत्री जी! आप कविताएं क्यों लिखती हो?'

कवियत्री जी कुछ क्षण मौन रहने के बाद मुस्कुराई। कवियत्री जी की मुस्कान में फीकेपन तथा कृत्रिमपन के साथ एक कटाक्ष भी था। कवियत्री जी ने उसी मुस्कान के साथ कहा, 'खुदकुशी टालने के सबके अपने अलग-अलग तरीके होते हैं!'

पत्रकार तथा अन्य श्रोतागण समझ नहीं पाए कि कवियत्री जी अपनी पुस्तक 'खुदकुशी' का प्रचार कर रहीं हैं या वे अपने जीवन का यथार्थ व्यक्त कर रहीं थी। लेकिन सच तो केवल वही जान सका होगा जो उनकी मुस्कान का मतलब समझा होगा।

— अनाम

आदत नहीं है

दर्दे दिल को जताने की आदत नहीं है,
बेवजह यूं सताने की आदत नहीं है।
छोड़ देती मैं भी बात करना मगर,
मुझे रूठ जाने की आदत नहीं है।
प्यार दिल में सम्हाले छुपाए रखी,
क्योंकि होठों पे लाने
की आदत नहीं है।
भूलूं कैसे तूझे बोल दे तू ही अब,
कि मुझे भूल जाने की आदत नहीं है।
करले तू सितम जितना भी सनम,
मुझे घबराने की आदत नहीं है।
सभी कसमें निभाए मैंने, कि मुझे
वचन झुठलाने की आदत नहीं है।
करती हूं मैं तुझपर हमेशा यकीं,
कि मुझे आजमाने की आदत नहीं है।
तेरी हर खुशी मेरी भी है खुशी,
अत: जलने जलाने की आदत नहीं है।
मानती है किरण बात तेरी सभी,
क्योंकि बात बढ़ाने की आदत नहीं है।

— किरण सिंह

दो जून की रोटी

लॉकडाउन में दो जून की रोटी की तलाश भी पूरी नहीं हो पा रही... यह सोचता हुआ रामदयाल अपनी रिक्शा लेकर मंदिर वाले मार्केट के पास खड़ा था, तभी बूढ़े सुधाकर बाबू जो अपने घर जाने के लिए रिक्शे की तलाश में थे, आकर रिक्शे में बैठ गए।

'कहां चलना है बाबूजी! रिक्शे वाले की आंखें चमक उठीं। सामने टेंपों स्टैंड के बाद वाली गली तक ले चलो...सुधाकर बाबू ने व्यग्रता दिखाते हुए कहा।

रामदयाल को अपने बच्चों के चेहरे अपने नजरों के सामने घूमते दिखाई दे रहे थे, जिन्हें बेहद मुश्किल से दो जून की रोटी मिल पा रही थी। वह सोच रहा था यदि एक-दो सवारी और मिल जाए तो आज सबको पेट भर खाने को मिल जाएगा। इधर, सुधाकर बाबू भी सोच रहे थे बेचारे रिक्शावाले की हालत कितनी दयनीय है, बिना इसके स्वाभिमान को आहत पहुंचाते हुए कैसे मदद करूं।

तभी सुधाकर बाबू ने कहा 'क्या तुम रेलवे कॉलोनी तक चलोगे।'

रामदयाल ने कहा 'बाबूजी उधर जाने में पौन घंटे लग जाते हैं, और सवारी भी नहीं मिलती' ये पगडंडी पकड़ लीजिए पांच मिनट में पहुंच जाएंगे।

सुधाकर बाबू ने पांच सौ का नोट निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया और तेजी से आती एक टैंपो में बैठ गए। लॉकडाउन में पतली गली में एक आध टैंपो दिख जाती थी।

रामदयाल ने पुकारते हुए कहा 'बाबूजी छुट्टे नहीं है।'

सुधाकर बाबू ने कहा 'रख लो मेरे पास भी नहीं है, यह टैंपो छूट गई तो परेशानी होगी।'

रामदयाल ने सोचा ईश्वर भी किस रूप में प्रकट होते हैं, उसने हाथ जोड़ लिए।

टैंपो आगे बढ़ चुकी थी सुधाकर बाबू को संतोष मिला, रिक्शेवाले को दो जून रोटी की रोटी मिल जाएगी।

रामदयाल के आखिरी शब्द उसके कानों तक पहुंची हे भोले बाबा।

— निभा कुमारी

रिकॉर्ड क्वीन स्टेफी ग्राफ

सात बार विम्बलडन विजेता

1980 और 90 के दशक लॉन टेनिस की दुनिया में जर्मनी की चमत्कारिक प्रतिभा स्टेफी ग्राफ के दशक थे। उनका नाम महिला टेनिस के विश्व वरीयता-क्रम में, 17 अगस्त 1987 से 1997 तक, पूरे 377 सप्ताह पहले नंबर रहा। यह एक ऐसा कीर्तिमान है, जो आज तक नहीं टूटा है। 14 जून 1969 को दक्षिण जर्मनी के मानहाइम में जन्मी स्टेफी ग्राफ ने 20 वर्ष पहले 13 अगस्त 1999 के दिन व्यावसायिक टेनिस की प्रतियोगिताओं से विदा ली। तब तक 22 ग्रैंड स्लैम टाइटलों सहित कुल 107 प्रतियोगिताएं उनकी विजय का कीर्तिमान बन चुकी थीं। ग्रैंड स्लैम खिताब थे- सात विम्बलडन, छह फ्रेंच ओपन, पांच यूएस ओपन और चार ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1999 के ही फ्रेंच ओपन के दौरान उनका अमेरिका के टेनिस दिग्गज आंद्रे अगासी से पेरिस में परिचय हुआ। निकटता बढ़ी और अक्टूबर 2001 में दोनों परिणयसूत्र से बंध गए। दोनों का 17 साल का एक बेटा और 15 साल की एक बेटी है।

टेनिस खेलने के अपने सक्रिय जीवनकाल में स्टेफी ग्राफ को, सभी तरह के टूर्नामेंटों में कुल मिलाकर 900 बार विजय प्राप्त हो चुकी थी। केवल 115 बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इस तरह देखें तो 88.7 प्रतिशत बार जयमाला स्टेफी ग्राफ के ही गले में पड़ी। 1988 में ओलंपिक स्वर्ण पदक के रूप में उन्होंने एक ऐसा 'गोल्डन स्लैम' भी जीता, जो बाद में दूसरी कोई महिला टेनिस खिलाड़ी नहीं जीत पाई है।

स्टेफी ग्राफ को निसंदेह एक चमत्कारिक टेनिस प्रतिभा ही कहा जाएगा। पर, कोई प्रतिभा भी तभी निखर पाती है जब उसे पहचानने और निखारने वाला कोई पारखी भी मिलता है। संयोग से, स्टेफी के पिता ही वह पारखी थे। वे टेनिस शिक्षक थे। मात्र चार साल की आयु में ही वे ताड़ गए कि स्टेफी टेनिस के खेल-मैदान का एक होनहार बिरवा है। उन्होंने उसे टेनिस का रैकेट पकड़ाया और शीघ्र ही पाया कि उसके पैरों की चपलता और उसकी 'फोरहैंन्ड' कुशलता गजब की है। पिता पेटर ने स्टेफी को बड़ी बारीकी से एक पेशेवर भावी टेनिस खिलाड़ी के रूप में गढ़ना-तराशना शुरू कर दिया। जब वह 13 साल की थी तो पहली बार उन्होंने अपनी इस होनहार बेटी को 'डब्ल्यूटीए' (विमन्स टेनिस एसोशिएसन) की प्रतियोगिता में उतार दिया।

14 साल की होते-होते स्टेफी ग्राफ 'डब्ल्यूटीए' के विश्व वरीयता-क्रम में 98वें नंबर पर पहुंच गईं। तब जर्मन राज्य बाडेन-व्युर्टेम्बेर्ग की राज्य सरकार ने उन्हें स्कूल छोड़कर पूरी तरह टेनिस पर ही ध्यान देने की विशेष अनुमति प्रदान की। इसके बाद तो चमत्कारों की झड़ी लग गई। 15 साल की होते-होते स्टेफी ग्राफ के नाम की धूम मच गई थी। विम्बलडन और फ्रेंच ओपन, दोनों में वे प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गईं। 1986 में अमेरिका के 'हिल्टन हेड आइलैंड टूर्नामेंन्ट' के फाइनल में उस समय के एक बड़े नाम क्रिस एवर्ट-लॉयड को हराकर स्टेफी ग्राफ ने अपने जीवन का पहला व्यावसायिक टाइटल जीता।

18 साल की होते ही 1987 में उस समय की टेनिस की सबसे दिग्गज महिला खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा को पेरिस के फ्रेंच ओपन के फाइनल में स्टेफी ग्राफ के आगे हार माननी पड़ी। स्टेफी का वह पहला 'ग्रैंड स्लैम' टाइटल था। उसी साल उन्होंने विश्व वरीयता-क्रम में नवरातिलोवा का पहला स्थान भी छीन लिया। 176 सेंटीमीटर लंबे छरहरे बदन और सुनहरे बालों वाली स्टेफी ग्राफ टेनिस की दुनिया की अब निर्विवाद महारानी बन गई थीं। स्टेफी ग्राफ के खेल-जीवन के वर्षों में 1988 को सबसे शानदार माना जाता है। उस साल उन्होंने टेनिस-जगत की चारों ग्रैंन्ड स्लैम प्रतियोगिताएं, यानी एक के बाद एक मेलबर्न, विम्बलडन, पेरिस और न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम खिताब तो जीते ही, दक्षिण कोरिया में सियोल ओलंपिक का एकल स्वर्ण पदक और युगल कांस्य पदक भी आपने नाम किया। युगल में उनका साथ दिया था जर्मनी की ही क्लाउडिया कोडे-किल्श ने। उस एक ही वर्ष में स्टेफी ग्राफ को 73 बार विजय मिली और केवल तीन बार पराजय झेलनी पड़ीं। जिन दिनों स्टेफी ग्राफ का विजयरथ सरपट दौड़ रहा था, उन्हीं दिनों पुरुषों के टेनिस जगत में जर्मनी के ही बोरिस बेकर के नाम की भी धूम मची हुई थी। 1989 का पुरुषों का विम्बलडन फाइनल बोरिस बेकर ने और महिलाओं का स्टेफी ग्राफ ने जीता था। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का तब तक एकीकरण नहीं हुआ था। लेकिन इस दोहरी विजय पर अपार खुशी सीमाओं के आर-पार एक समान थी। संयोग से उसी वर्ष नवंबर में बर्लिन दीवार भी गिर गई और 40 वर्षों से विभाजित जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। इसी को कहते हैं, 'ऊपर वाला जब देता है, तो छप्पर फाड़ कर देता है।'

कुछ ऐसा ही शुभसमय उनके लिए 1992 भी सिद्ध हुआ। उस वर्ष स्टेफी ग्राफ ने विम्बलडन की घास पर सातवीं बार चैंपियनशिप जीती। पुरुषों के एकल फाइनल में आंद्रे अगासी को विजय मिली। दोनों का कहना है कि उस समय वे एक-दूसरे को केवल व्यावसायिक खिलाड़ियों के तौर पर ही जानते थे, न कि कोई प्रेमी युगल थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस साल की सफलता ने ही दोनों की आंखें पहली बार लड़ाई थीं, भले ही दोनों ने विवाह 9 साल बाद किया। महिला टेनिस की दुनिया में स्टेफी ग्राफ का दबदबा 1990 तक अक्षुण रहा। उनके पिता, जो साथ ही उसके प्रशिक्षक, प्रबंधक, परामर्शदाता इत्यादि सब कुछ थे, एक महिला-मॉडल के साथ कथित प्रेम-प्रकरण के कारण उस साल सड़क-छाप पत्र-पत्रिकाओं में बहुचर्चित हो गए। यह चर्चा कई महीनों तक चलती रही। स्वाभाविक है कि पिता की बदनामी से स्टेफी ग्राफ की मनोदशा भी अछूती नहीं रह सकती थी। साथ ही टेनिस कोर्ट में एक नई प्रतिस्पर्धी, सर्बिया की मोनिका सेलेस, उन्हें भारी चुनौती देने लगी थी। वह भी एक चमत्कारिक खिलाड़ी थी और आयु में स्टेफी से चार साल छोटी भी थीं।

● आशीष नेमा

बॉलीवुड ने खोया एक और टैलेंट

ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। 14 जून को उन्होंने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके नौकर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सुशांत ने सुइसाइड क्यों किया है, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस को सुशांत के दोस्तों ने बताया है कि वह बीते 6 महीने से डिप्रेशन में थे और दवाइयां टाइम से नहीं ले रहे थे। सुशांत का परिवार उनके इस कदम से सदमे में है। वहीं पूरा बॉलीवुड इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है। कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को सुशांत के घर से डिप्रेशन के इलाज की फाइल मिली है। सुशांत केदारनाथ, एमएस धोनी और छिछोरे जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं। उन्होंने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से घर-घर में पहचान बनाई थी। बता दें कि बीते दिनों उनकी मैनेजर दिशा की मौत हुई है। दिशा सलियन ने पिछले दिनों मुंबई में एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

लॉकडाउन के अनुभवों पर किताब लिख सकता हूं: अनुपम खेर

बहुमुखी कलाकार अनुपम खेर इन दिनों चर्चा में हैं, अपने शो कुछ भी हो सकता है, को लेकर। लॉकडाउन में लोगों को उम्मीद देने के इरादे से वे अपने इस लोकप्रिय शो को अपने अपने डिजिटल पोर्टल पर लाए हैं। लॉकडाउन के अनुभव के बारे में जब अनुपम से पूछा गया तो उन्होंने कहा - लॉकडाउन के अनुभवों पर मैं एक किताब लिख सकता हूं। वे कहते हैं- अभी मैं 74 दिन से घर पर मुंबई में अकेला बैठा हूं और किरण जी (अभिनेत्री पत्नी किरण खेर) चंडीगढ़ में हैं। लॉकडाउन के पहले तक मैं खुद को बहुत ही रेस्टलेस इंसान समझता था। मुझे हर जगह जाना होता था। हर काम करना होता था। मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकता था। मगर जब 74 दिन से मैं घर पर बैठा, वो भी अकेला, तो मुझे लगा कि मुझ में काफी संयम और ठहराव है।

मुझे फेयरनेस क्रीम और कोला की ऐड फिल्म करने का अफसोस : दीपिका

फेयरनेस क्रीम एंडोर्स करने को लेकर सिलेब्स की आलोचना हो रही है। इस बीच ऐक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ ब्रैंड्स का ऐड करने पर दुख जताया है। ये फेयरनेस क्रीम और कोला ब्रैंड्स थे जिनसे वह अब खुद को अलग कर चुकी हैं। अमेरिकी में हुई अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद भारत में भी ब्लैक लिव्स मेटर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कई सिलेब्स ने भी इसका विरोध किया। साथ ही कई लोगों ने सिलेब्स को वाली फेयरनेस क्रीम्स के ऐड करने के लिए आड़े हाथ भी लिया। दीपिका पादुकोण जो कई बड़े ब्रैंड्स को एंडोर्स कर रही हैं, उन्होंने माना कि पहले ब्रैंड्स चुनने में उनसे गलती हुई है। इंडस्ट्री से जुड़े एक सोर्स की मानें तो दीपिका को न सिर्फ अपनी गलती का अहसास है बल्कि वह खुद को इन ब्रैंड्स से अलग भी कर चुकी हैं। इनमें फेरयरनेस क्रीम और कोला ब्रैंड्स शामिल थे।

कई साल तक ब्रैंड से जुड़ी रही हैं दीपिका

सोर्स की मानें तो दीपिका ने इन ब्रैंड्स के ऐड तब किए जब फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करना आम बात थी। हालांकि कुछ साल पहले समझ बढ़ने के साथ इस सोच में बदलाव आया है। इसके साथ ही शुगर वाले ड्रिंक्स हेल्थ के लिहाज से ठीक नहीं इस बात अहसास होने पर उन्होंने खुद को कोला ब्रैंड से भी अलग कर लिया। दीपिका कई साल इन ब्रैंड्स से जुड़ी रहीं लेकिन कुछ साल पहले इन ब्रैंड्स से खुद को अलग कर चुकी हैं।

हिंदी साहित्य के इतिहास में तालाबंदी काल

हिंदी साहित्य के इतिहास पुनर्लेखन का समय फिर से एक बार निकट आता दिखाई दे रहा है। वीरगाथा काल से शुरू होकर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तक लिखे गए इतिहास में अब तालाबंदी (लॉकडाउन) काल को जोड़ना पड़ेगा। लॉकडाउन का सही उपयोग किसी ने किया तो वह हिंदी के रचनाकारों ने किया। कोरोना को देश से भगाने के जितने प्रयास किए गए उनमें हिंदी के रचनाकारों ने भी अपने मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया पर जमकर योगदान दिया। यहां तक कि इस काल में कई नए रचनाकार भी पैदा हुए। जिनको जीवन पर्यन्त साहित्य का 'स' और कविता का 'क' छू भी नहीं पाया था वो भी कोरोना की कृपा से कवि हो गए। और अपनी छुपी हुई प्रतिभा से साहित्य समाज को संक्रमित करने लगे।

जो अकवि घर में बैठे-बैठे अभी तक केवल अपनी रोजी-रोटी के चक्कर में सर खपाया करते थे उनको लॉकडाउन में प्रसारित महाभारत बड़ी शिक्षा दे गई। लॉकडाउन उनके लिए कवि-शायर बनने का सुनहरा अवसर लेकर आया। हस्तिनापुर नरेशों की तरह कई **कवि और लेखक** इस दौरान ऐसे पैदा हुए जिन्होंने किसी शायर की गजल के दो शेर लिए और किसी कवि की कविता की चार पंक्तियां ली और जोड़-तोड़ कर एक नई कविता को जन्म दिया और अपनी संतान घोषित कर दिया। लॉकडाउन काल से पहले तक जो लोग बैंक और बीमा कंपनी से मुफ्त मिली डायरियों में लिखकर जिंदगी को गुलजार रखने का प्रयास करते थे, इस काल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप के माध्यम से अपनी तुरंत जन्मी कविता का 'जातकर्म' संस्कार संपन्न कराते नजर आए। कुछ ऐसे लोग जिनको घरेलू और 'बाथरूम सिंगर' का खिताब प्राप्त था, वे लोग बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर अपनी प्रतिभा का सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगे।

लॉकडाउन काल में वाचिक परम्परा के कवियों के हाथ से माया और राम दोनों निकल गए। रोज कवि सम्मेलन पढ़ने वाले कवियों को एक कवि सम्मेलन भी नसीब नहीं हुआ। और तो और अपनी पहचान व प्रतिभा को बचाने के लिए बिना पेमेंट लिए रोज नए कपड़े पहनकर फेसबुक-इंस्टाग्राम पर आना पड़ रहा है। मंच पर चुटकुलों को कविता कहने वालों को ये डर सताने लगा है कि लोगों को कहीं ये पता न चल जाए कि कविता क्या होती है। अगर पता चल गया तो उनकी रोजी-रोटी के लाले पड़ जाएंगे।

बगैर जाम के जूम के माध्यम से झूमती हुई ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों ने तो वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ कवियों ने तो बकायदा रोज पांच-छह गोष्ठियों में अपनी सक्रिय भागीदारी भी की और रोजाना बिस्किट की परमानेंट प्लेट सामने रखकर, घर की चाय पीकर, कभी अध्यक्ष तो, कभी अतिथि के रूप में अपनी प्यास बुझाई। आखिर पत्नी को कब तक नई रचना सुना-सुना कर पकाएं। कुछ कवियों ने हड़बड़ाहट में इन कवि गोष्ठियों का रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन जो कवि रिकॉर्ड रखने में होशियार है वे इतिहास लेखन से पहले गिनीज बुक और वर्ल्ड बुक वालों प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए बाध्य करने की तैयारी कर रहे है। जो कि गिनीज बुक और वर्ल्ड बुक को सम्मान सहित उन्हें प्रदान करना भी पड़ेगा।

फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन आने वालों ने भी लॉकडाउन काल में कुछ कम योगदान नहीं दिया है। रोज किसी ना किसी विषय को लेकर घंटों लंबी चर्चाएं करते हैं। जो चर्चाएं अभी तक बंद कमरे या किसी स्कूल के हाल में होती थी वह सार्वजनिक होने लगी है। जिनके भाग्य में मुश्किल से अतिथियों सहित पांच श्रोता होते थे, उन्हें अब बीस-पच्चीस श्रोता मिलने लगे जो कि पूर्वकाल से 4 से 5 गुना थे। और वह भी लाइक और पारम्परिक कमेंट्स के साथ। 'बहुत खूब', 'सुंदर रचना', 'बधाई सर', 'मजा आ गया आपको सुन कर' ऐसे कमेंट्स लिखकर चर्चा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और चर्चा को सफल बनाने वालों का योगदान भी अभूतपूर्व है। क्योंकि उनको भी जीवन में वह सब सुनने को मिल गया जिसे सुनना उन्होंने चाहा ही नहीं। हालांकि फेसबुक पर श्रोता कम दर्शक अधिक होते हैं। पर जब घर बैठे गंगा घर आए तो कौन हाथ नहीं धोए। सर का सम्मान भी हो गया और संबंधों में भी एक बार फिर मिठास घुल गई।

जो 'कवि कम श्रोता' थे उनके लिए लॉकडाउन काल स्वर्णिम काल रहा। वे कवि जिनके भीतर कवि सम्मेलन के मंचों पर चढ़ने का कीड़ा तो सालों से कुलबुला रहा था, लेकिन उन्हें कोई बुला नहीं रहा था और ना कोई जुगाड़ लग पा रहा था। ऐसे में यह अवसर उनके लिए तो परमात्मा के दिए किसी दिव्य वरदान से कम नहीं रहा। अपना फेसबुक-इंस्टाग्राम एकाउंट, अपना मोबाइल, अपने शब्द, अपनी मर्जी, सब कुछ अपना यहां तक कि उन्हें झेलने वाले भी अपने, यानि कि जो उनके फेसबुक-इंस्टाग्राम मित्र हैं। यदि पहुंच थोड़ी लंबी हुई तो किसी समूह या किसी संस्था के बैनर तले बने फेसबुक-इंस्टाग्राम पर काव्य पाठ कर अपनी भूख मिटा रहे हैं। कुछ ने तो लंबी कहानियां, व्यंग्य और उपन्यास के अंश तक 'लाइव हावर' में पढ़ डाले, चाहे उनके श्रोता दो या तीन रहे हों या अंत तक पहुंचते समय शून्य हो गए हों। लेकिन वर्तमान लॉकडाउन काल में वे फेसबुक लाइव आने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा गए। और लॉकडाउन के इतिहास लेखकों के लिए सिरदर्द बन गए।

● **संदीप सृजन**

भोपाल विकास प्राधिकरण

आवेदन प्राप्ति दिनांक 15.06.2020 से दिनांक 30.06.2020

राजा भोज आवासीय योजना

गोदरमऊ चरण 2

ऑफर के माध्यम से

रेरा पंजीकृत क्र. P-BPL-17-286

ऑफर फार्म रू.500/-

भोपाल शहर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक एवं राजमार्ग क्र. 12 से लगी हुई भूमि पर पूर्ण विकसित भूखण्ड उपलब्ध

ऑफर आमंत्रण

लोकेशन अनुसार भूखण्ड मूल्य का निर्धारण ।

विकास अनुसार चरणबद्ध तरीके से भुगतान।

सभी भूखण्ड फ्री होल्ड है

नियमानुसार आरक्षण

अनु. क्र.	भूखण्ड/इकाई का विवरण	भूखण्डों / इकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्ग मी. प्रत्येक भूखण्ड	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	पट्टे लीज पर या भूमिस्वामी अधिकारों पर व्ययन	वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे लीज) के प्रकरणों में	निक्षेप रकम प्रति भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूखण्ड क्र.- 05 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	अनु. जाति	7,13,600	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	71,360
	भूखण्ड क्र.- 08 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	7,13,600	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	71,360
	भूखण्ड क्र.- 04, 06, 07 एवं 09 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	सामान्य	7,13,600	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	71,360
2	भूखण्ड क्र.- 246, 256, 262 एवं 307 सेक्टर- सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	अनु. जाति	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 244, 255, 264, 302, 320 एवं 225 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 308 एवं 217 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	पिछड़ा वर्ग	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 304 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	प्राधिकरण कर्मचारी	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 266 एवं 310 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	स्व. संग्राम सेनानी	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 300 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	सैनिक भूतपूर्व सैनिक	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 207 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	पत्रकार	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 260 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	विकलांग	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.- 254 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	सामान्य महिला	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
	भूखण्ड क्र.-245, 247, 251 252, 253, 257,258, 261, 263, 265,301, 303, 305, 306, 309,316, 318, 319, 321, 197, 274 एवं 285 सेक्टर-सी	आवासीय	55.75 वर्ग मी.	सामान्य	7,94,828	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	79,483
3	भूखण्ड क्र.- 595 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	13,39,560	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,33,956
	भूखण्ड क्र.- 594, 596, 597 एवं 598 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्ग मी.	सामान्य	13,39,560	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,33,956
4	भूखण्ड क्र.- 625 एवं 636 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्ग मी.	अनुजाति	12,80,024	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,28,000
	भूखण्ड क्र.- 627 एवं 632 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	12,80,024	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,28,000
	भूखण्ड क्र.- 635 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्ग मी.	पिछड़ा वर्ग	12,80,024	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,28,000
	भूखण्ड क्र.- 623, 624, 626, 628, 629, 631, 633, 634 एवं 630 सेक्टर-सी	आवासीय	74.42 वर्ग मी.	सामान्य	12,80,024	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,28,000
5	भूखण्ड क्र.- 372 सेक्टर-बी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	सामान्य	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
6	भूखण्ड क्र.- 414 एवं 415 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जाति	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
	भूखण्ड क्र.- 409 एवं 413 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
	भूखण्ड क्र.- 404 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	पिछड़ा वर्ग	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
	भूखण्ड क्र.- 407 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	स्व संग्राम सेनानी	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
	भूखण्ड क्र.- 410 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	विकलांग	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
	भूखण्ड क्र.- 400, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 411 एवं 412 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	सामान्य	16,47,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,64,700
7	भूखण्ड क्र.- 685 सेक्टर-सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जाति	13,04,516	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,30,452
	भूखण्ड क्र.- 62सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	13,04,516	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,30,452
	भूखण्ड क्र.-778 सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	पिछड़ा वर्ग	13,04,516	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,30,452
	भूखण्ड क्र.- 907, 777, 779, 780, 781 एवं 782 सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	सामान्य	13,04,516	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,30,452
8	भूखण्ड क्र.-386 सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जाति	11,71,200	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,17,120
	भूखण्ड क्र.-386 ई	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	11,71,200	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,17,120
	भूखण्ड क्र.-386-बी386-डी, 386-एफ, 386-जी एवं 386-एच	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	सामान्य	11,71,200	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,17,120
9	भूखण्ड क्र.-465 सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जाति	18,11,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1, 81,100
	भूखण्ड क्र.-473 सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	18,11,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1, 81,100
	भूखण्ड क्र.- 469 सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	पिछड़ा वर्ग	18,11,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1, 81,100
	भूखण्ड क्र.- 466, 467, 468, 470, 471, एवं 472 सेक्टर- सी	आवासीय	91.5 वर्ग मी.	सामान्य	18,11,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1, 81,100
10	भूखण्ड क्र.- 493 सेक्टर- ए	आवासीय	80.00 वर्ग मी.	सामान्य	12,80,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,28,000
11	भूखण्ड क्र.- 383 एवं 385 सेक्टर- सी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	अनु. जाति	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
	भूखण्ड क्र.-387 एवं 393 सेक्टर- सी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	अनु. जनजाति	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
	भूखण्ड क्र.- 395 सेक्टर- सी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	पिछड़ा वर्ग	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
	भूखण्ड क्र.- 382, 384, 386, 388, 389, 390, 391, 392 एवं 394 सेक्टर- सी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	सामान्य	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
12	भूखण्ड क्र.-347 सेक्टर- बी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	सामान्य	24,30,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,43,000
13	भूखण्ड क्र.- 354 सेक्टर-बी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	अनु. जाति	19,24,695	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,92,470
	भूखण्ड क्र.- 353 सेक्टर-बी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	अनु. जाति	19,24,695	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,92,470
	भूखण्ड क्र.- 348, 349, 350, 351 एवं 352 सेक्टर-बी	आवासीय	135.00 वर्ग मी.	सामान्य	19,24,695	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	1,92,470
14	भूखण्ड क्र.- 51, 52 एवं 53 सेक्टर-ए	आवासीय	162.00 वर्ग मी.	सामान्य	29,16,000	भूमिस्वामी अधिकार	फ्री- होल्ड	2,91,160

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निधारण शुल्क (भू -राजस्व प्रीमियम राशि) रजिस्ट्री पृथक से देय होगा ।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनु सार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा ।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ -सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अंतिम रजिस्ट्री से पूर्व पृथक से देय होगी ।
4. सम्पत्ति फ्री-होल्ड पर विक्रय हेतु है ।
5. जी.एस.टी. एवं अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी ।
6. किश्तो का निर्धारण निम्नानुसार देय होगा-

   1-आवंटन मूल्य का 50 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के समयावधि मे जमा करना अनिवार्य होगा ।
   2-आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत सड़क कार्य पूर्ण होने पर ।
   3-आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत जल प्रदाय कार्य पूर्ण होने पर ।
   4-आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत सीवर नेटवर्क शुरू होने पर ।
   5-आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत विद्युत लाईन एवं सबस्टेशन चार्ज होने पर ।
   6-शेष 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर समस्त शुल्क सहित ।
   7-शेष नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेंगें ।

दिनांक 01.07.2020 को अपरान्ह 12.00 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष ऑफर खोले जावेंगे।

अधिक जानकारी के लिये कार्यालय में संपर्क करें-
प्रगति भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन–1, एम.पी.नगर, भोपाल
फोन नं. 0755-2701836, 37 फैक्स : 0755-2701806
सहायक यंत्री, श्री अरविन्द मंडराय मोबाईल 9826597251, उपयंत्री श्री वी.एन. पचौरी 9827069669
Email : info@bda.org.in website : www.bda.org.in

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444

Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®